

वर्ष: 20 | अंक: 24
 16 से 30 सितंबर 2022
 पृष्ठ: 48
 मूल्य: 25 रु.

In Pursuit of Truth

आक्स

पाक्षिक



भारत जोड़ो यात्रा का औचित्य?

महात्मा गांधी, इंदिरा, आडवाणी
की पदयात्राओं ने बदली भारत
की सियासी तस्वीर

हाथी पर इंदिरा, ट्रेन में राजीव ने
किया सफर, पैदल ही निकल
पड़े राहुल गांधी



नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश

“ राज्य में उच्च गुणवत्ता के साथ परिणामोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सीएम राइज स्कूलों की स्थापना की जा रही है। इन स्कूलों का लक्ष्य विश्व स्तरीय शिक्षण विधियों द्वारा बच्चों के ज्ञान और कौशलवर्धन के साथ ही भारतीय परंपरागत नृत्यों, संस्कृति एवं मूल्यों को समर्थित कर बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। -शिवराज सिंह चौहान

मध्यप्रदेश में विश्व स्तरीय स्कूली शिक्षा का उदय

स्कूली शिक्षा के नवाचारों को ध्यान में रखते हुए, मध्यप्रदेश सरकार प्रत्येक विद्यार्थी को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूरे राज्य में उच्च गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु माहत्वपूर्ण पहल के माध्यम से व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं।



सीएम राइज स्कूल : भविष्य के लिए एक दृढ़दर्शी सोच - स्कूली शिक्षा में अनुमोदीकरण, नवीन संसाधनों का समावेश, बच्चों का सर्वांगीण विकास, स्कूलों की संरचना में व्यापक सुधार, बच्चों की शिक्षा एवं अन्य गतिविधियों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार 9,200 सर्वसुविधापूर्ण सीएम राइज स्कूल की स्थापना कर रही है। 370 विद्यालयों को फेज-1 (2021-2024) तक पूर्णरूपेण विकसित किया जाएगा और शेष विद्यालयों को फेज-2 (2024-32) में पूरी तरह क्रियाशील बनाया जाएगा।

• 4 स्तरीय स्कूलों की परिकल्पना •



सीएम राइज स्कूलों के प्रमुख बिंदु

- 1 शिक्षा सार्वभौम सुनिश्चिता संरचना
- 2 परिसर सुविधा
- 3 पढ़ाई/कैरी के 12वीं तक
- 4 सर्वोत्कृष्टता और डिजिटल संरचना
- 5 सांस्कृतिक विरासत संरक्षण
- 6 31वीं तक के कौशल कार्यक्रम
- 7 अधिस्तरीय की सुव्यवस्था
- 8 संसाधनपूर्ण प्रयोगशाला, पुस्तकालय और डिजिटल लाइब्रेरी
- 9 उच्चतम स्तर का कक्षा संरचना
- 10 उच्च प्रतियोगिता शिक्षण एवं अन्य संरचना

अन्य महत्वपूर्ण शैक्षणिक पहल

- ☑ सुपर 100 : मोबाइली छात्रों को उनके भविष्य के सपनों को साकार करने में सहायता प्रदान करने के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण कोर्सेज।
- ☑ स्नातकीय भाषाओं पर अव्यवस्थित प्रारंभिक पाठ्यक्रम : स्नातकीय भाषा में सहज-सहज और शिवांगी शिक्षण प्रणाली।
- ☑ कक्षा 5 और 8 के छात्रों में लैंग्वेज की गुणवत्ता में सुधार : दैनिकिक सर्वेक्षणों और छात्रों के लैंग्वेज डेटा के विस्तृत विश्लेषण द्वारा।

सर्वांगीण विकास हेतु अतिरिक्त प्रयास

अनुभव : STEAM (साइंस, टेक्नोलॉजी, एंजिनियरिंग, आर्ट्स और मैथ्स) के जरिए कला शिक्षा को बढ़ावा देने में अग्रणी राज्य। यह कार्यक्रम बच्चों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का एक मंच प्रदान करता है।

उपम : एक जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम, जो स्वस्थ मानसिकता को बढ़ावा देने और नवीं दृष्टिकोण विकसित करने पर केंद्रित है, जिससे बच्चों में निर्माण लेने की क्षमता का विकास होता है।

अनुभवशील कार्यक्रमों के लिए इंजीनियरी प्रशिक्षण : अनुभवशील कार्यक्रमों की बनना निर्माण हेतु राज्य स्तरीय प्रशिक्षणों द्वारा प्रशिक्षण और डिजिटल मॉड्यूल द्वारा संवर्धित शिक्षण व्यक्तित्व प्रशिक्षण मॉडल।

मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, पढ़ने, लिखने और गणना में बुनियादी कौशल को विकसित करना। तीसरी कक्षा तक सभी छात्रों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल सुनिश्चित करना।

राजकाज

8

विंध्य बिगाड़
न दे खेल

जिस विंध्य अंचल ने बीते आम विधानसभा चुनाव में प्रदेश भाजपा की झोली में एक तरफा जीत डालते हुए कांग्रेस के दिग्गजों को घर बैठने पर मजबूर कर दिया था, वही अंचल अब भाजपा संगठन व सत्ता के लिए मुसीबत...

राजपथ

10-11

दागियों-बागियों
को अभयदान!

मप्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और भाजपा ने किसी को भी नाराज नहीं करने की रणनीति बनाई है। इस रणनीति के तहत दोनों पार्टियों ने दागियों और बागियों पर कार्यवाही न करने का फैसला किया है।

मुद्दा

15

332 करोड़ की
सड़कें खराब

प्रदेश में इस बार हुई रिकॉर्डतोड़ बारिश ने सड़कों की दशा बिगाड़ दी है। मप्र की 76000 किलोमीटर सड़कों में से 8 हजार किमी इस बार बारिश में खराब हो गईं। ये सड़कें लोक निर्माण विभाग, मप्र सड़क विकास निगम और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की हैं।

विवाद

20

प्लानिंग में फंसा
अटल प्रोग्रेस-वे

चंबल के बीहड़ों की सूरत बदलने के लिए अटल चंबल प्रगति पथ (एक्सप्रेस-वे) अब बीहड़ों से दूर हो जाएगा। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने बीहड़ में एक्सप्रेस-वे के निर्माण पर आपत्ति लगा दी है। इसके बाद एक्सप्रेस-वे का ले-आउट फिर से बनाया जा रहा है। चार साल पहले...



आजादी के पहले महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा निकालकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। आज गांधी के देश में राजनीतिक यात्राएं निकालने की परंपरा बन गई है। हर यात्रा का उद्देश्य जनहित ही बताया गया लेकिन दांडी यात्रा को अपवाद मानें तो शेष राजनीतिक यात्राएं देश हित के कितनी करीब रहें, उससे देश का कितना भला हुआ, यह किसी से छिपा नहीं है। देश में अब तक जितनी भी यात्राएं निकाली गई हैं, उनका मकसद सत्ता रहा है। इसी कड़ी में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं।



सियासत

30-31

एकता की न
पकने वाली...

मिशन 2024 के लिए विपक्षी एकता की लगातार कवायद हो रही है। पहले ममता बनर्जी, फिर अरविंद केजरीवाल, उसके बाद केसीआर और अब नीतीश कुमार इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन यह प्रयास अभी तक नेताओं की मेल-मुलाकात से आगे नहीं बढ़ पाया है।

उत्तरप्रदेश

34

यदुकुल के
सहारे चक्रव्यूह

उप्र की राजनीति में अहम जगह रखने वाला यादव कुनबा फिर से बिखर चुका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही चाचा शिवपाल सिंह यादव को खुला खत भेजकर कह चुके हैं कि जहां सम्मान मिले, वहां चले जाएं। और, चाचा शिवपाल यादव भी इसके बाद से ही...

बिहार

35

पलटवार की
ताक में भाजपा

एनडीए यदि बिहार के घटनाक्रम से फिलहाल स्तब्ध है, तो इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि वह बिहार सरकार को अपने मन से शासन करने के लिए संपूर्ण संवैधानिक अधिकार (राज्य-केंद्र के बीच) देकर चुप होकर बैठ जाएगी। यह कभी हो ही...

6-7 अंदर की बात

40 महिला जगत

41 अध्यात्म

43 कहानी

44 खेल

45 फिल्म

46 व्यंग्य



हताशा में बढ़ती आत्मघाती प्रवृत्ति...

कि सी कवि ने लिखा है...

शकता कौन नहीं जीवन में, हर किसी ने यहां विराम लिया।

गलती इसमें तेरी ही रही, क्यों तूने पूर्ण विराम लिया।।

देश में जिस तेजी से आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, उस पर कवि की उक्त पक्तियां बड़ी सीख हैं। हमारा जीवन अनमोल है। तनाव, निराशा या हताशा का समाधान आत्महत्या नहीं है। मनोचिकित्सकों का मानना है कि अवसाद से ग्रस्त लोगों की मानसिक चिकित्सा के जरिए उन्हें स्वस्थ बनाया जा सकता है। इसके अलावा परिवार और समाज का भावनात्मक संबल भी अवसाद में जाने से बचाने में मददगार हो सकता है। इस प्रकार देश में लगातार आत्महत्याओं के बढ़ते ग्राफ को तेजी से नीचे लाने में काफी मदद मिल सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के अनुसार दुनियाभर में एक साल में करीब 7.3 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इसके अलावा करीब 20 लाख लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं। यह स्थिति परेशान करने वाली है। राष्ट्रीय आत्महत्या के आंकड़ों के अनुसार दुनियाभर में सभी आत्महत्याओं में भारत का हिस्सा करीब 25 फीसदी है। 18-39 आयु वर्ग की युवतियों में मृत्यु का प्रमुख कारण आत्महत्या है। पिछले दिनों राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी रिपोर्ट में 2021 में भारत में आत्महत्या की दर में 7.14 फीसदी की वृद्धि देखी गई है। भारत में पिछले 5-6 वर्षों में आत्महत्या की दर बढ़ने के कारणों को लेकर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि लोग ज्यादा से ज्यादा आत्मकेंद्रित होते जा रहे हैं। उनके प्रत्यक्ष मित्र कम और सोशल मीडिया पर मित्र अधिक हैं। ऐसे लोग अपने परिवार के सदस्यों से कट रहे हैं और अपने फोन या सोशल मीडिया घेरे तक ज्यादा सीमित हो गए हैं। एनसीआरबी द्वारा जारी पिछले 5 वर्षों के आत्महत्या के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्पष्ट है कि आत्महत्या की घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। एनसीआरबी के मुताबिक देश में 2017 में आत्महत्या के 1 लाख 29 हजार 887 मामले दर्ज हुए थे, जिसकी दर प्रति लाख आबादी पर 9.9 थी। 2018 में यह दर बढ़कर 10.2 पर पहुंच गई। 2019 में कुल 1 लाख 39 हजार 123 लोगों ने और 2020 में 1 लाख 53 हजार 52 लोगों ने आत्महत्या की। 2021 में एनसीआरबी के मुताबिक कुल 1 लाख 64 हजार 33 लोगों ने आत्महत्या कर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में हम जिस प्रकार का बनावटी और दोहरे मापदंड वाला जीवन जी रहे हैं, उसमें तनाव विद्यमान है, जिससे समाज का लगभग प्रत्येक वर्ग प्रभावित है। जहां दहेज जैसी कुप्रथा और पारिवारिक समस्याओं के कारण महिलाओं की आत्महत्या के मामले सामने आते हैं, वहीं युवाओं द्वारा पढ़ाई का दबाव, कैरिअर संबंधी समस्याएं और खराब होते विश्वास आत्महत्या जैसे घातक कदम उठाने की प्रमुख वजह बन रहे हैं। महामारी के दौर में नौकरियां छिन जाने, अपने करीबियों को खोने और अकेलेपन ने लोगों को चिंतित, उदास, एकाकी और अति संवेदनशील बना दिया है, जिसके कारण भी कुछ लोग जीवन में आई मुसीबतों का मुकाबला करने के बजाय आत्महत्या की तरफ कदम उठा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक आत्महत्या को रोकने का सबसे अच्छा तरीका चेतावनी संकेतों को पहचानना और इस तरह के संकट का जवाब देना है। देश में हर साल लाखों आत्महत्याएं समाज में हताशा और निराशा व्याप्त होने का जीता-जागता प्रमाण है। हालांकि आत्महत्या की समस्या केवल आर्थिक या राजनीतिक समस्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे सामाजिक और मानसिक कारण भी मौजूद होते हैं।

- राजेन्द्र आगाल

पाठक
अक्षर

वर्ष 20, अंक 24, पृष्ठ-48, 16 से 30 सितंबर, 2022

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :

प्लॉट नम्बर 150, जौन-1 मनोरमा कॉम्प्लेक्स,

एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर

भोपाल- 462011 (म.प्र.),

फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com

Website : www.akshnews.com

RNI NO. HIN/2002/8718 MPEPL/642/2021-23

ब्यूरो

कोलकाता:- इंद्रकुमार, छत्तीसगढ़:- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,

जयपुर:- आर.के. बिनानी, लखनऊ :- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संपादकता

094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे

098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया

094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार

098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव

089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी

075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुत्री

फोन : 9811017939

जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)

मोबाइल-09829 010331

रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,

फोन : 0771 2282517

भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर,

भिलाई, मोबाइल 094241 08015

इंदौर : नवीन खुशवंशी, खुशवंशी कॉलोनी, इंदौर,

मो.-9827227000

देवास : जय सिंह, देवास

मो.-7000526104, 9907353976

स्वाधिकाारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 150, जौन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा कॉम्प्लेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।



रोजगार की तैयारी

प्रदेश में रोजगार के मद्देनजर उन उद्योगों को जल्द स्थापित करने जमीनें आवंटित की जा रही हैं, जिनसे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। भोपाल सहित आसपास के जिलों के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। जिला उद्योग केंद्र के अफसरों के साथ मिलकर नए उद्योगों को जमीनें आवंटित करते जा रहे हैं।

● नीलम सेन, भोपाल (म.प्र.)



मिशन 2023 में जुटी भाजपा-कांग्रेस

मप्र में भाजपा और कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई हैं। एक तरफ भाजपा अपने सिपहसालारों को प्रदेश के हर एक छोटे से छोटे क्षेत्र में तैनात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस चुनाव को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता अपने-अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। मप्र में कांग्रेस को सत्ता से हटाकर भाजपा जब से सत्ता में आई है सरकार और संगठन में शह-मात का खेल चल रहा है। इस कारण भाजपा में अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। वहीं कांग्रेस भी दलबदल को लेकर चिंतित नजर आ रही है, क्योंकि 15 साल बाद सत्ता में वापसी करने के 15 माह में ही कांग्रेस की सरकार दलबदल के कारण गिर गई थी।

● राजविंदर सिंह, ग्वालियर (म.प्र.)

रोचक होगा लोकसभा चुनाव

देशभर में प्रधानमंत्री मोदी अपनी अलग साब्र बनाए हुए हैं। इसको लेकर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। ताकि वे 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्तापक्ष को कड़ी टक्कर दे सकें। वहीं कई विपक्षी पार्टियों के प्रमुख तो प्रधानमंत्री की कुर्सी की लालसा पाले हुए भी हैं। इनमें से सबसे पहला नाम नीतीश कुमार का है, जिन्होंने हाल ही में बिहार में भाजपा से नाता तोड़कर राजद के साथ मिलकर सरकार बनाई है। वहीं ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इससे लोकसभा का चुनाव रोचक हो जाएगा।

● नौशाद खान, सीहोर (म.प्र.)

भूमिफियाओं के हौंसले बुलंद

शासन-प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदेश में भूमिफियाओं के हौंसले बुलंद हैं। अवैध खनन, नकली दवाओं, राशन माफियाओं, मिलावट माफियाओं के अलावा सबसे ज्यादा संख्या भूमिफियाओं की है। सरकार को इस ओर कठोर कार्यवाही करने की जरूरत है।

● प्रियांशी मोदी, इंदौर (म.प्र.)

बिजली का झटका

बिजली सब्सिडी कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं के साथ पावर और हैंडलूम जैसे कुटीर उद्योगों और ग्राम पंचायतों को दी जाती है। इसके अलावा कई राज्यों में इंडस्ट्री और बिजनेस को भी बिजली सब्सिडी दी जा रही है। अधिक खर्च वाले कई उपभोक्ताओं को बिजली कंची दर पर मिलती है।

● नीलेश चौहान, राजगढ़ (म.प्र.)



वनों की कटाई रोकना जरूरी

एक समय में मप्र को वनों के प्रदेश के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि यहां वनों की कमी होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण अवैध कटाई है। वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने में वन रक्षकों की कमी बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। वहीं वन क्षेत्रों में हो रही अवैध कटाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले साल वन विभाग ने अवैध कटाई के 40 हजार से ज्यादा मामले सामने आए थे।

● प्रशांत शर्मा, शिवपुरी (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल



किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं आजाद

जम्मू-कश्मीर में अब विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दी गई है। इनमें से 43 सीटें जम्मू में होंगी, जबकि 47 सीटें कश्मीर में होंगी। अभी तक 36 सीटें जम्मू में थी और कश्मीर में 46 सीटें थी। इन 90 सीटों में से 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने का भी प्रावधान किया गया है। जबकि 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर की नई विधानसभा में लद्दाख का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। क्योंकि वह अब केंद्रशासित प्रदेश बन चुका है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आगामी चुनाव बदली हुई परिस्थितियों में होंगे। ऐसी स्थिति में गुलाम नबी आजाद किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। दरअसल, आजाद की खासियत यह है कि वह जम्मू-कश्मीर के उन गिने-चुने नेताओं में हैं, जिनकी घाटी से लेकर दिल्ली तक स्वीकार्यता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें पसंद करते हैं। तो नेशनल काँग्रेस के नेता फारूक अब्दुल्ला भी कांग्रेस छोड़ने के बाद उनका स्वागत करने को तैयार दिख रहे हैं। इसके अलावा अलगाव विरोधी मुस्लिमों के भी वह पसंद रहे हैं और हिंदू समुदाय भी उन्हें वोट देता है। ऐसे में आजाद चुनाव बाद किंगमेकर की भूमिका निभा सकते हैं। खासतौर पर उस समय जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिले।

दुविधा में प्रशांत किशोर

पीके को राह नहीं सूझ रही है। पीके यानी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। विदेश से भारत आए पीके 2014 में तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने भाजपा और नरेंद्र मोदी के प्रचार व चुनावी रणनीति का ठेका लिया था। उनकी कंपनी का तो धंधा ही यही है। तब कहा गया था कि अबकी बार भाजपा सरकार के बजाय 'अब की बार, मोदी सरकार' का नारा उन्हीं की देन था। बहरहाल उनके पास मतदाताओं को प्रभावित करने का हुनर है या नहीं पर इतना साफ है कि भाजपा की 2014 की जीत ने पीके का कद बढ़ाया था। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित राज्यों के चुनाव में कई दलों के लिए रणनीति बनाने का काम किया। नीतीश कुमार तो उनसे कुछ ज्यादा ही प्रभावित हुए थे। अन्यथा उन्हें पार्टी में पदाधिकारी क्यों बनाते। आरसीपी सिंह के मामले में भी नीतीश के इस मिजाज को सबने देखा ही। कैसे, उन्होंने दूसरे सूबे के एक आईएएस अफसर को अपने जिले और जात का होने के कारण किस हद तक सिर चढ़ाया था। रूठे तो अचानक जमीन पर पटक भी दिया। पीके को तो अपने इस मिजाज का स्वाद उन्होंने 2020 में ही चखा दिया था। मंत्री स्तर का ओहदा तो छीना ही था, पार्टी से भी निकाल दिया था। तभी से पीके कई बार सियासी पारी खेलने की घोषणा कर चुके हैं।



कायम रहेगी कांग्रेस में कलह

बीते दिनों से पार्टी जहां महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार को घेरने में जुटी है, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता राज बब्बर ने सरकार की प्रधानमंत्री जनधन योजना की तारीफ की है। राज बब्बर पार्टी के असंतुष्ट नेताओं में शामिल हैं। राज बब्बर ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना को आठ साल पूरे हो गए। लोगों तक पैसा और मदद सीधे बिना किसी दखल के पहुंचाना अपने आप में यह एक क्रांति है। इसमें आधी से ज्यादा खाता धारक महिलाएं हैं। ऐसी योजना आपका पैसा आपके हाथ के नाम पर मनमोहन सिंह सरकार में भी शुरू हुई थी। मौजूदा सरकार ने इसे बेहतर तरीके से लागू किया है। राज बब्बर फिलहाल कांग्रेस संगठन में किसी पद पर नहीं हैं। वह लंबे वक्त से पार्टी की बैठकों और कार्यक्रमों से भी दूर हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस में कलह कायम है। दरअसल, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली में कांग्रेस के कई असंतुष्ट नेता गैरहाजिर रहे। वहीं, गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने का फायदा जम्मू-कश्मीर के नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विकार रसूल को हुआ। कांग्रेस की रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीडब्ल्यूसी के सदस्य आनंद शर्मा गैर हाजिर रहे। वहीं, असंतुष्ट नेताओं में शामिल मनीष तिवारी भी मौजूद नहीं थे।

संदेश और सहारा

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों दल अपने-अपने कार्यकर्ताओं व समर्थकों की लामबंदी करने में जुटे हैं। कांग्रेस तो इतना ज्यादा कुछ नहीं कर रही है। लेकिन, भाजपा पिछले एक साल से अपने तमाम अग्रणी संगठनों और मोर्चों के सम्मेलन करने में जुटी है। इन दिनों भाजपा महिला मोर्चा के सम्मेलन विधानसभा हलकेवार हो रहे हैं। पहला सम्मेलन सुजानपुर में हुआ और राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने इस सम्मेलन में खासतौर पर शिरकत की। गोस्वामी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेमकुमार धूमल को सहारा भी दे गईं और जयराम सरकार व प्रदेश भाजपा को संदेश भी दे गईं कि वे धूमल के साथ हैं और वे धूमल को ही नेता मानती हैं। 2017 विधानसभा चुनावों में धूमल सुजानपुर से अपना चुनाव हार गए थे। तब से भाजपा के विरोधी खेमे ने धूमल को आगे नहीं आने दिया। उन्हें क्या, उनके खेमे के तमाम नेताओं को हाशिए पर धकेल कर रखा। इनमें इंदु गोस्वामी भी शामिल रहीं।

सियासी सपना और कवि कल्पना

हिंदी पट्टी में एक कहावत प्रसिद्ध है—जहां न जाए रवि, वहां जाए कवि। यानी जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती, वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है। लेकिन आज की छवि प्रबंधन वाली राजनीति में साहित्यिक कल्पना का संबंध मानदेय से जोड़ दिया जाना स्वाभाविक है। भाजपा से नीतीश कुमार के नाता तोड़ने के बाद बिहार में 'प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा, मन की नहीं काम की' जैसे होर्डिंग्स लगने शुरू हो गए। इन पोस्टरों को लेकर कहा गया कि नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति का रख करने का संदेश देना चाहते हैं। एक कार्यक्रम में इन पोस्टर की बाबत पूछे गए एक सवाल पर राज्यसभा सांसद व भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि किसी कवि या लेखक को आप पैसे देंगे तो वो आप के लिए बढ़िया तुकबंदी कर सकता है। सिर्फ तुकबंदी या होर्डिंग से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। आपका अपने राज्य में प्रभाव घटता जा रहा है और आप 45 पर सिमट गए हैं।

साड़ी का शौक पड़ा भारी

महिला चाहे गृहिणी हो या कामकाजी, शौक-श्रृंगार उनकी सबसे बड़ी हॉबी होती है। महंगे गहने और कपड़े उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। ऐसी ही एक महंगी साड़ी एक महिला आईएएस अधिकारी पर भारी पड़ गई है। दरअसल, मैडम का अतीत धार्मिक और सांस्कृतिक पक्षों से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैडम को साड़ी खरीदना और पहनना खूब भाता है। अपने इसी शौक में 1992 बैच की उक्त महिला आईएएस अधिकारी इस कदर फंस गई कि उन्हें विभाग से चलता कर दिया गया। दरअसल, मैडम जिस विभाग में थीं उस विभाग में रहते हुए उन्होंने 25 लाख रुपए की साड़ियां खरीद डालीं और बिल विभाग के मत्थे मढ़ दिया। अब विभाग के अधिकारी-कर्मचारी परेशान हैं कि इतनी बड़ी रकम का भुगतान कैसे किया जाए। या तो यह रकम अधिकारियों-कर्मचारियों को चुकानी होगी, या फिर इसकी भरपाई सरकारी खजाने से करनी होगी। अब मैडम की साड़ियों का यह किस्सा प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में चर्चा का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि मैडम जिस भी विभाग में रही है, वहां उनसे कोई न कोई विवाद जुड़ा ही रहा है। बताया जाता है कि मैडम के शौक तो भले ही बड़े-बड़े हैं, लेकिन पैसे खर्च करने में वे काफी कंजूस हैं। इसलिए वे अपने खर्च को विभाग के हिसाब-किताब में ही जोड़ने की कोशिश करती रहती हैं।

आखिर क्या है घालमेल ?

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने अनुपयोगी सरकारी जमीनों को बेचने का सिलसिला शुरू कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक करीब 6 हजार करोड़ की जमीनें बेच दी गई हैं। वहीं प्रदेशभर में ऐसी जमीनों को चिन्हित कर सूचीबद्ध किया जा रहा है। इस बीच इस पूरी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की बू आने लगी है। यह बू आम आदमी को भले ही न आए, लेकिन वल्लभ संप्रदाय में जो महामंडलेश्वर बैठे हैं, उन्हें आने लगी है। वे यह सोचने लगे हैं कि आखिरकार इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार की गुंजाइश कैसे है। उधर, प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इसको लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कानाफूसी तो यह हो रही है कि सरकार की बिकने वाली जमीनों के प्रबंधन का जिम्मा जिस नवगठित विभाग को दिया गया है, उसमें बैठे अधिकारी ही भ्रष्टाचार का घालमेल कर रहे हैं। दरअसल, जिन जमीनों को बेचा जा रहा है, उनकी दरें कलेक्टर गाइडलाइन से कम हो रही हैं। इसको लेकर कई मामले अदालत में चले गए हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिरकार जमीनों की बिक्री में घालमेल क्या है? कौन इस धंधे में मलाई खा रहा है।



सब धान बाईस पसेरी...

यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, सब धान बाईस पसेरी... यानी सबको एक समान समझना। ऐसा ही कुछ हाल मप्र के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का है। 1996 बैच के ये आईएएस अधिकारी प्रदेश के एक बड़े महकमे की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। साहब का विभाग के मंत्रीजी से छत्तीस का आंकड़ा रहता है। यानी मंत्रीजी डाल-डाल तो साहब पात-पात चलते हैं। ऐसे में साहब की स्थिति ऐसी हो गई है कि वे अब सभी को एक ही नजर से देखने लगे हैं। इससे साहब की जमकर छीछालेदर हो रही है। दरअसल, विगत दिनों एक संसदीय दल मप्र के दौरे पर आया हुआ था। यह दल प्रदेश के पंचायतों का सर्वे करने आया था। बताया जाता है कि दल विभाग के बड़े साहब के साथ बैठक करके रणनीति बनाना चाहता था, लेकिन साहब ने बिना सोचे-समझे विभाग के सचिव को भेज दिया। हालांकि दल ने सचिव के साथ ही बैठक कर ली, लेकिन जिस तरह साहब अपने जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं, उससे मप्र की साख भी गिर रही है। बताया जाता है कि साहब की इस मनमानी पर संसदीय दल के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री तक शिकायत कर दी है कि आपके अधिकारी का व्यवहार ठीक नहीं है। हम दिल्ली से मप्र की पंचायतों का सर्वे करने यहां तक आ गए, लेकिन अफसर को हमसे मिलने की फुर्सत तक नहीं मिली। बताया जाता है कि संसदीय दल की शिकायत को सरकार ने गंभीरता से लिया है। देखा है आगे क्या होता है।

टीआई का इकबाल बुलंद

राजधानी में पदस्थ एक टीआई का इन दिनों इकबाल इस कदर बुलंद है कि उनके आगे अच्छे-अच्छे पानी भरने को मजबूर हो रहे हैं। दरअसल, टीआई साहब एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा की स्थिति से गुजर रहे हैं। यानी टीआई की दोस्ती इन दिनों राजधानी के एक पड़ोसी जिले के विधायक के साथ हो गई है। दोनों की दोस्ती इस कदर परवान चढ़ी है कि दोनों ने मिलकर जमीनों की खरीद-फरोख्त और प्लॉट काटने का धंधा शुरू कर दिया है। धंधा इस कदर जोर पकड़ लिया है कि टीआई साहब थाने में बैठकर भी प्लॉट की खरीदी-बिक्री में ही लगे रहते हैं। यहां बता दें कि टीआई साहब ने यह धंधा अपनी पत्नी के नाम से शुरू किया है। धंधे में ऊंच-नीच तो होता ही रहता है। ऐसे में अगर कोई कुछ उल्टा-पुल्टा करता है तो टीआई साहब उसे सबक सिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। बिना सोचे-समझे आरोप लगाकर टीआई साहब मुकदमा दायर कर लेते हैं। वह भी उस थाने में जिसमें वे पदस्थ हैं। बताया जाता है कि साहब की इस कारस्तानी से परेशान लोग राजधानी के साथ ही पड़ोसी जिले के भी हैं।

विधायक या शहंशाह ?

माना जाता है कि जनप्रतिनिधि होने के कारण कोई भी विधायक वैधानिक बाध्यता और स्थिति-परिस्थिति को अच्छी तरह जानता है। लेकिन राजधानी की एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक माननीय का व्यवहार न उनकी पार्टी के मंत्रियों और नेताओं को पसंद आ रहा है और न ही अफसरों को। दरअसल, माननीय को परिस्थितियों के कारण सरकार ने कुछ समय के लिए एक बड़ा ओहदा दे दिया था। इस ओहदे ने माननीय में ऐसा गुरूर भर दिया है कि वे प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं कर रहे हैं। बताया जाता है कि माननीय के क्षेत्र में फोरलेन सड़क का निर्माण होना है। इसको लेकर माननीय इस कदर उत्सुक हैं कि उन्हें शुभ-लाभ की भी चिंता नहीं रही और उन्होंने कड़वे दिन में ही इस प्रोजेक्ट के भूमिपूजन के लिए सीएम से समय मांग लिया है। वह भी विभागीय मंत्री को बिना बताए। हद तो उस समय देखने को मिली, जब माननीय अफसरों की टोली लेकर प्रोजेक्ट के भूमिपूजन स्थल पर पहुंच गए और अनावश्यक दिशा-निर्देश देने लगे। माननीय का यह रूप देखकर लोगों के मुंह से बरबस यह सुनने को मिला कि ये विधायक हैं या शहंशाह।

जिस विंध्य अंचल ने बीते आम विधानसभा चुनाव में प्रदेश भाजपा की झोली में एक तरफा जीत डालते हुए कांग्रेस के दिग्गजों को घर बैठने पर मजबूर कर दिया था, वही अंचल अब भाजपा संगठन व सत्ता के लिए मुसीबत बन चुका है। इस जीत के बाद इलाके के कई ऐसे नेता हैं जो अब सत्ता व संगठन के लिए मुसीबत के सबब बन चुके हैं। शायद यही वजह है कि नगरीय निकाय चुनावों में पार्टी को अपने गढ़ रीवा, सिंगरौली में महापौर पद के लिए हार का मुंह देखना पड़ा है। यही नहीं इसके पहले पार्टी को उपचुनाव में भी पराजित होना पड़ा था, लेकिन इसके बाद भी शायद पार्टी ने सबक नहीं लिया है। अंचल में पार्टी के नेताओं से लेकर विधायक तक इतने स्वच्छंद हो चुके हैं कि वे पार्टी लाइन को तोड़ने में भी नहीं चूकते हैं।

इसका उदाहरण हाल ही में जारी एक नेता का पिटाई करने वाला वीडियो ही नहीं है, बल्कि एक विधायक का आडियो भी है। ऐसे नेताओं के खिलाफ पार्टी कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आई है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। यह तो वे मामले हैं जो सार्वजनिक हुए हैं, लेकिन और कई ऐसे मामले भी होंगे जिसकी जानकारी भोपाल तक आती ही नहीं है। यही नहीं इस अंचल में सत्ता में भागीदारी नहीं मिलने की वजह से भी नाराजगी की खबरें आना आम बात है। इनमें विधायक भी शामिल हैं। इस अंचल के दो विधायकों के जिस तरह के तेवर बने हुए हैं, उससे सत्ता और संगठन दोनों ही परेशानी बने हुए हैं। खास बात यह है कि इस परेशानी से **बाहर आने का उपाय न तो** संगठन को मिल रहा है और न ही सत्ता कोई उपाय तलाश पा रही है।

इस अंचल के दो विधायक तो पहले से ही पार्टी की परेशानी की वजह बने हुए थे, लेकिन अब उसमें दो नए नाम जुड़ने की वजह से यह परेशानी अब और बढ़ गई है। यही वजह है कि इन दिनों इस मामले में सत्ता और संगठन सहमा हुआ नजर आ रहा है। दरअसल विंध्य में विधायकों के विरोध के सुर तो पहले से उठ चुके हैं। हाल-फिलहाल विंध्य के भाजपा के कुछ विधायक अपने तीखे तेवर अब तो पार्टी की किसी बैठक अथवा बंद कमरे की जगह सार्वजनिक तौर पर दिखाने लगे हैं। हाल ही में रीवा जिले के सिरमौर से भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह का नया मामला सामने आया है। रीवा राजपरिवार से आने वाले सिंह बेहद शांत और सौम्य माने जाते हैं। हाल ही में उनके द्वारा अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन कर उमरिया जिला प्रशासन को झुकाने का काम किया है। वे कृष्ण जन्माष्टमी पर बांधवाधीश मंदिर में पूजा करने के लिए जाने पर अड़े थे। उनका कहना था कि मंदिर को जनता के लिए



विंध्य बिगाड़ न दे खेल

नारायण त्रिपाठी लगातार खोले हुए हैं मोर्चा

अपने बगावती तेवरों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहने वाले मैहर से भाजपा के विधायक नारायण त्रिपाठी तो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। वे चार माह पहले भी विंध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाकर शिवराज सरकार को एक बार फिर से खुली चुनौती दे चुके हैं। नारायण ने अपने मंसूखे जाहिर करते हुए यहां तक कह डाला था कि अगर 2023 तक विंध्य प्रदेश न बना तो तीसरा मोर्चा बनेगा। पिछले कई महीनों से पृथक विंध्य प्रदेश की मांग उठाकर सरकार की मुश्किलें बढ़ाते आ रहे त्रिपाठी ने सियासी बिसात पर एक बड़ी चलते हुए यहां तक कहा डाला था कि यह तीसरा मोर्चा विंध्य की सभी 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और भोपाल पहुंचकर विंध्य प्रदेश का गठन कराएगा। उनका कहना था कि मैहर माता शारदा की धरा है, यहां लिया गया कोई संकल्प अधूरा नहीं रहता। विंध्य की भूमि मयार्दा पुरुषोत्तम भगवान राम की तपोभूमि है, यहां गोस्वामी तुलसीदासजी ने रामचरित मानस की रचना की, यह भूमि निर्विवाद है, इसका उत्थान होना ही चाहिए। इसके पहले भी वे कई मौकों पर पार्टी व सरकार के लिए खुलकर संकट खड़ा कर चुके हैं।

खोला जाए। प्रशासन की ओर से बांधवगढ़ में जंगली हाथियों का हवाला देकर मंदिर में दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। दिव्यराज ने भाजपा नेता गगनेंद्र सिंह के साथ राज्य सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन वे झुके नहीं। आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा। प्रशासन की ओर से उन्हें मंदिर ले जाया गया और दर्शन कराया गया। बताते हैं कि दिव्यराज इससे भी संतुष्ट नहीं हैं। उनका मानना है कि बरसात में जब नेशनल पार्क बंद रहता है, तो एक दिन के लिए प्रशासन व्यवस्था कर दर्शन करा सकता है।

गगनेंद्र ने सत्ता और संगठन को सीधी चेतावनी दी थी कि अस्मिता के लिए सौ सरकारें कुर्बान कर सकता हूं। दूसरा मामला रीवा जिले के सेमरिया से भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी का है। त्रिपाठी का जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय मिश्रा के साथ दुर्व्यवहार किए जाने का आडियो वायरल हुआ था उसके बाद दुर्दांत तरीके से सीईओ के साथ मारपीट भी की गई थी। त्रिपाठी का एक अफसर के प्रति किया गया व्यवहार कतई उचित नहीं है, इसे पार्टी ने भी माना है। इसके लिए त्रिपाठी को नेतृत्व की फटकार भी सुननी पड़ी है। बहरहाल संगठन में यह मैसेज भी गया है कि मैदानी अफसर विधायकों की नहीं सुन रहे हैं, जिसके कारण इस तरह के हालात बने हैं। तीसरा मामला मैहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी का है। त्रिपाठी ने एक दलित महिला सरपंच पर अत्याचार का मामला उठाया और अपनी ही पार्टी के मंत्री रामखेलावन पटेल और सतना सांसद गणेश सिंह को परिणाम भुगतने की चेतावनी दे डाली।

नारायण त्रिपाठी और शहडोल जिले के ब्यूँहारी से भाजपा विधायक शरद कोल पार्टी लाइन से हटकर पहले भी काम करते रहे हैं। दोनों नेता विधानसभा में पार्टी लाइन के इतर जाकर **क्रॉस वोटिंग** भी कर चुके हैं। दोनों विधायकों को लेकर पार्टी मानसिक रूप से पहले से तैयार हैं। दोनों नेता पार्टी के रडार पर भी हैं। यह बात अलग है कि इन दोनों ही विधायकों पर पार्टी अब तक कोई ठोस कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखा सकी है। बहरहाल दिव्यराज सिंह और केपी त्रिपाठी के मामलों ने सरकार और संगठन की चिंता को और बढ़ा दिया है। त्रिपाठी ने जिस तरह का व्यवहार सीईओ के साथ किया है, वह भी सत्ता में रहते हुए, भाजपा की रीति-नीति के खिलाफ है। पार्टी की परेशानी इसलिए भी है कि भाजपा विधायक पहले भी लामबंद होकर **तीखे तेवर अपना चुके** हैं। पहली बार विंध्य के भाजपा विधायक लामबंद हुए और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला को मंत्री नहीं बनाए जाने का विरोध किया था। आखिरकार इस विरोध के आगे सत्ता और संगठन को झुकना पड़ा था।

● डॉ. जय सिंह सेंधव

आ खिरकार विन्ध्य क्षेत्र के राजनेताओं और जनता के विरोध के बाद सरकार ने सिद्धा पहाड़ पर खनन की अनुमति देने से मना कर दिया है। मामला संज्ञान में आने के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिद्धा पहाड़ को किसी

भी प्रकार की क्षति न पहुंचाने की घोषणा की। गौरतलब है कि प्रभु श्रीराम की कर्मभूमि 84 कोषीय चित्रकूट क्षेत्र स्थित सिद्धा पहाड़ जहां रामायण काल में श्रीराम ने राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा ली थी उसे खोदने की तैयारी हो गई थी। राज्य शासन ने इस पूरी पहाड़ी पर खनन अनुमति देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। इसके लिए मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने पर्यावरणीय अनुमति के लिए 30 सितंबर को जनसुनवाई आयोजित की जानी थी। इस अनुमति के बाद इस पहाड़ से हर वर्ष लगभग 43 हजार टन खनिज की खुदाई करने की तैयारी थी। अगर इस सिद्धा पहाड़ की खुदाई की अनुमति मिल जाती तो अगले कुछ सालों में धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का यह पहाड़ नक्शे से गायब हो जाता और प्रभु श्रीराम के प्रतिज्ञा स्थल का कोई अस्तित्व नहीं बचता। इस मामले के सामने आने के बाद जिलेभर में आक्रोश की स्थितियां निर्मित हो गई थीं। चित्रकूट के कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी और मैहर के भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इस पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा। उधर कांग्रेस ने भी इस मामले में प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला।

रामचरितमानस में अरण्य कांड में उल्लेख है कि भगवान राम जब चित्रकूट से आगे की ओर बढ़े तो सिद्धा पहाड़ मिला, यह पहाड़ अस्थियों का था। तब राम को मुनियों ने बताया कि राक्षस कई मुनियों को खा गए हैं और यह अस्थियां उन्हीं मुनियों की हैं। भगवान राम ने यहीं पर राक्षसों के विनाश की प्रतिज्ञा ली थी।

निसिचर हीन करउं महि भुज उठाइ पन कीन्ह। सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ भावार्थ यह है कि इसके बाद श्रीराम ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा-जाकर उन्होंने ऋषि मुनियों को दर्शन एवं सम्भाषण का सुख दिया। स्थानीय लोगों में इस पहाड़ को लेकर बहुत आस्था है। यहां खनन अनुमति की तैयारी की जानकारी मिलते ही चित्रकूट के साधु-संतों में भी आक्रोश फैल गया है।

धार्मिक महत्व के सिद्धा पहाड़ पहाड़ पर खनन करने के लिए मे. राकेश एजेन्सीज, पार्टनर श्याम बंसल ने पर्यावरणीय अनुमति (ईसी) के लिए आवेदन दिया था। लेकिन जिला स्तर पर इस पहाड़ के धार्मिक महत्वों की अनदेखी करते हुए प्रकरणों को बिना रोक-टोक के शासन स्तर तक पहुंचाया गया। इसके बाद अब ईसी के लिए



एक बार फिर बच गया सिद्धा पहाड़

दो कलेक्टर ने खनन पर लगाई थी रोक

जानकारों के अनुसार तत्कालीन कलेक्टर सुखबीर सिंह ने सिद्धा पहाड़ से लगी खनन लीजों को निरस्त कर दिया था। इनके बाद आए तत्कालीन कलेक्टर केके खरे ने इस पूरे क्षेत्र को खनन मुक्त क्षेत्र घोषित किया था। ऐसे में आज की स्थिति में किस तरह यहां खनन सक्रियता के लिए प्रस्ताव चला गया अपने आप में बड़ा सवाल है। चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने कलेक्टर अनुराग वर्मा को पत्र लिखकर सिद्धा पहाड़ में खनन परियोजना पर रोक लगाने की बात कही थी। रामायण काल में इस पहाड़ पर राम की प्रतिज्ञा का उल्लेख करते हुए बताया कि मान्यता है कि यह पहाड़ ऋषियों की अस्थियों के ढेर से बना है। यह भी बताया कि बाघों के विवरण स्थल में शामिल इस क्षेत्र में अभयारण्य प्रस्तावित है। यह राम वन गमन पथ का हिस्सा है। ऐसे में यहां खनन अनुमति मिलने से भारतीय हिंदू सनातनियों की आस्था पर चोट होगी। चेतना है कि अगर यहां प्रस्तावित खनन अनुमति की कार्यवाही को नहीं रोका गया तो इसके विरोध में विशाल जन आंदोलन किया जाएगा जिसकी पूरी जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी।

क्षेत्रीय कार्यालय मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोक सुनवाई की सूचना जारी कर दी, जिसमें बताया गया है कि इस पहाड़ को खोद करके बाक्साइड, लेटराइट, ओकर एवं वाइट क्ले निकाली जाएगी। प्रतिवर्ष 43713 टन खुदाई का माइनिंग प्लान बताया गया है। जैसे ही यह सूचना सार्वजनिक हुई लोगों में आक्रोश फैल गया।

जिस धार्मिक महत्व के सिद्धा पहाड़ पर खनन अनुमति देने की तैयारी शासन स्तर से चल रही है वह राम वन गमन पथ का हिस्सा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले भी मझगावां के अपने कार्यक्रम में इसे संरक्षित करने की बात कह चुके हैं। ऐसे में जिला स्तर से विभिन्न विभागों और अधिकारियों ने किस तरीके से इसे खनन अनुमति के लिए आगे तक भेजा अपने आप में बड़े सवाल है। पुरातत्व विभाग ने इसके धार्मिक महत्व को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है। खुद संचालनालय पुरातत्व विभाग ने नवंबर 2015 को जारी राम वन गमन पथ परिक्रमा मार्ग का पुरातत्वीय सर्वेक्षण प्रतिवेदन जो जारी किया था उसमें इसके महत्व को प्रमुखता से उल्लेखित किया था। प्रभारी अधिकारी सर्वेक्षण आशुतोष उपरीत और प्रभारी अधिकारी प्रकाशन एवं संरक्षण डॉ. रमेश चंद्र यादव ने अपने प्रतिवेदन में सिद्धा पहाड़ के बारे में स्पष्ट लिखा है। कहा है कि इसी स्थल पर श्रीराम ने भुजा उठाकर निश्चर विहीन पृथ्वी करने का प्रण लिया था। आगे यह भी जोड़ा है कि यह पहाड़ धार्मिक महत्व का है। किंतु इस पर हुए खनन कार्यों से पूरा पहाड़ ही विनष्ट हो रहा है। जिससे न केवल धार्मिक आस्थाएं प्रभावित होंगी अपितु पर्यावरणीय असंतुलन की भी संभावना है।

जिला कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा भगवान राम की तपोभूमि सिद्धा पहाड़ में लीज स्वीकृत करना आस्था पर हमला है। प्रदेश सरकार ने इस पवित्र स्थल पर लीज स्वीकृत कर उसे नष्ट करने की जो साजिश रची है उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश की भाजपा सरकार ने उक्त धार्मिक स्थान पर लीज स्वीकृत कर उसे नष्ट करने की जो स्वीकृति प्रदान करने जा रही है की है वह देश के करोड़ों करोड़ राम भक्तों की छाती पर कुदाली चलाने जैसा है। मुख्यमंत्री से यह लीज निरस्त करने की मांग की है।

● जितेंद्र तिवारी

पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की तरफ से बड़ी संख्या में नेताओं ने बगावत की थी। उस समय दोनों पार्टियों ने अपने-अपने नेताओं को हिदायत दी थी कि अगर वे पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में नहीं उतरे तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद अब दोनों पार्टियां दागियों और बागियों पर कार्यवाही करने से हिचक रही है। इसकी वजह यह है कि पार्टियां नहीं चाहती हैं कि मिशन 2023 में किसी प्रकार का खलल पड़े और पार्टी में किसी को नाराज किया जाए।

म प्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और भाजपा ने किसी को भी नाराज नहीं करने की रणनीति बनाई है। इस रणनीति के तहत दोनों पार्टियों ने दागियों और बागियों पर कार्यवाही न करने का फैसला किया है। यानी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में जिन नेताओं ने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ काम किया है उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। दरअसल, विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां पूरी तरह सजग हैं। दोनों का लक्ष्य है कि 2023 में सरकार बनाई जाए।

इस लक्ष्य को पाने के लिए लगातार रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि 2018 की तरह 2023 में भी उसकी लॉटरी लग सकती है। इसलिए पार्टी समन्वय के साथ काम कर रही है। वहीं भाजपा प्रीतम लोधी को पार्टी से निकालने के बाद उसके परिणाम पर लगातार मंथन कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा भी मिशन 2023 तक दागी और बागी पर कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस आर्थिक असमानता, सामाजिक विभाजन जैसे मुद्दों पर जनता से सीधा संवाद कर हर वर्ग में पैठ बनाने का प्रयास करेगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मप्र कांग्रेस भी पार्टी नेताओं के साथ ही हर वर्ग को पार्टी से जोड़ने के लिए कोशिश कर रही है। यही वजह है कि जुलाई में पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले अपने विधायकों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने के मूड में नहीं है। उनको लेकर प्रदेश कांग्रेस का रुख नरम है। राष्ट्रपति चुनाव में अंतरात्मा की आवाज पर कांग्रेस के 19 आदिवासी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया था, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस के आदिवासी विधायकों ने चुनाव में क्रॉस वोटिंग तब की थी, जब भोपाल में यशवंत सिन्हा की मौजूदगी में कमलनाथ ने उनसे सिन्हा के पक्ष में मतदान करने को कहा था और सभी विधायकों ने इस पर सहमति दी थी। चुनाव में मप्र से



दागियों-बागियों को अभयदान!

जल्द ही जिलों के दौरे शुरू करेंगे प्रभारी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी 52 जिलों में प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। उन्हें जिलों में समन्वय बनाने और ग्राउंड रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रभारी और सह प्रभारी जल्द ही अपने-अपने प्रभार के जिलों में जाकर काम शुरू करेंगे। कमलनाथ ने जिला प्रभारियों से सीधे उन्हें रिपोर्ट करने को कहा है। बालाघाट जिले के प्रभारी व पूर्व मंत्री तरुण भनोत का कहना है कि वे पूर्व से ही बालाघाट के दौरे करते रहे हैं। चुनाव को देखते हुए वे बालाघाट में और सक्रियता बढ़ाएंगे। हमारा काम जिले के सभी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर समन्वय स्थापित करना है। सागर जिले के प्रभारी अवनीश भार्गव का कहना है कि वे सागर का एक बार दौरा कर चुके हैं। सागर जिले के खुरई, गढ़ाकोटा व करीपुर में निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए वे ज्यादातर समय वहां दे रहे हैं।

एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 146 वोट मिले थे, जो एनडीए की वोट संख्या से 19 ज्यादा थे। मप्र में एनडीए की वोट संख्या 127 है। कांग्रेस विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग करने से

पार्टी को बड़ा झटका लगा था। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने स्तर पर क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के नाम पता करवा लिए हैं, लेकिन अभी वे उनके खिलाफ कार्यवाही करने के मूड में नहीं हैं। वे इन विधायकों से जवाब-तलब करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई भी विधायक या नेता पार्टी लाइन से बाहर न जाए। दरअसल, इस समय कमलनाथ का पूरा फोकस विधानसभा चुनाव पर है। वे किसान, व्यापारी, मजदूर, नौकरीपेशा सभी वर्गों को पार्टी से जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। नाथ यह भी नहीं चाहते कि पुराने कार्यकर्ता पार्टी से दूर हों। पिछले दिनों प्रदेश कार्यालय में हुई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, जिलाध्यक्षों व अन्य पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में कमलनाथ ने नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव में भितरघात करने वाले पार्टी नेताओं पर नरम रुख अपनाते हुए विधायकों, जिलाध्यक्षों से उन्हें हाथ-पैर जोड़कर मनाने की बात कही थी। इससे कमलनाथ की मंशा को समझा जा सकता है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर कहते हैं कि फिलहाल कांग्रेस कमेटी विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रही है। पार्टी हर वर्ग को जोड़ने में जुटी है। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कार्यवाही को लेकर वे कुछ नहीं कह सकते, इस बारे में अंतिम फैसला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे।

सख्त अनुशासन के लिए ख्यात भाजपा ने भी

अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए अनुशासन की डोर कुछ ढीली कर दी है। जहां पार्टी को हार मिली है वहां उसने पिछले दिनों अपने नेताओं को रायशुमारी के लिए भेजा था और बागियों से भी बात करने को कहा था। इन नेताओं की रिपोर्ट पार्टी को मिल गई है पर वह बागियों के खिलाफ सख्त तेवर अपनाने से बच रही है। गौरतलब है कि नगरीय निकाय चुनावों में टिकट न मिलने के कारण कई कार्यकर्ता बागी हो गए थे और उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा था। इनमें कई को जीत भी मिली थी। जीत के बाद कई नगरीय निकाय चुनावों में इन्होंने भाजपा के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी का समर्थन कर दिया। ऐसे नेताओं पर पार्टी ने कार्यवाही नहीं करने का फैसला किया है। इसके अलावा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कई नेताओं से माफीनामा लेकर उन्हें बक्शा जाएगा। इसी तरह कांग्रेस से बागी होकर भाजपा का समर्थन करने वाले पार्षदों को भी आने वाले समय में भाजपा में शामिल किया जाएगा।

जिला और जनपद पंचायतों में भाजपा ने जिन उम्मीदवारों को अपना समर्थन दिया था। उनके खिलाफ पार्टी के ही कई नेता बागी होकर मैदान में उतर गए थे। इनमें से कई ने जीत दर्ज की है। विधानसभा चुनाव में महज एक साल रह जाने के कारण पार्टी अब इन बागियों पर कार्यवाही नहीं करना चाहती। उसने इनसे चर्चा कर इन्हें फिर से पार्टी के पक्ष में काम करने का सुझाव जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों को दिया है। वहीं भाजपा ने मिशन 2023 के लिए अभी से कांग्रेस के तीन दिग्गज नेताओं को उनके ही गढ़ में घेरने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इन तीन नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह शामिल हैं। दरअसल यह वे नेता हैं, जो तमाम प्रयासों के बाद भी अपने इलाकों में अजेय बने हुए हैं। भाजपा सूत्रों के मुताबिक इस बार पार्टी छिंदवाड़ा को कांग्रेस नेता कमलनाथ से मुक्त कराकर भगवा झंडा फहराना चाहती है। इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपने तीन मंत्रियों को छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर ली है। खबर है कि रणनीति के तहत कमलनाथ का प्रभाव समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार के तीन मंत्रियों के अलावा प्रदेश के प्रभारी मंत्री को



इस काम में लगाने की पूरी तैयारी है।

इसके तहत जहां जिला प्रभारी मंत्री कमल पटेल हर माह छिंदवाड़ा का दौरा करेंगे, तो वहीं तीनों केंद्रीय मंत्री में से हर माह एक मंत्री विधानसभा चुनाव तक छिंदवाड़ा के प्रवास पर आएंगे। दरअसल प्रदेश का छिंदवाड़ा क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बेहद मजबूत गढ़ माना जाता है। इस लोकसभा सीट पर आज तक एक बार ही भाजपा को सफलता मिली है, जबकि जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो अधिकांश सीटों पर कमलनाथ के प्रभाव की वजह से कांग्रेस ही जीतती आ रही है। अगर बीते विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इस जिले की सभी सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी विजयी रहे थे। यही नहीं मुख्यमंत्री बनने के पहले तक नाथ छिंदवाड़ा सीट से लगातार सांसद निर्वाचित होते रहे हैं। उनका प्रभाव ऐसा है कि संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाली सातों विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस को ही विजय मिलती है। हाल ही में हुए निकाय चुनाव में भी यहां पर महापौर के पद पर कांग्रेस की ही जीत हुई है। खास बात यह है की मोदी लहर में भी नाथ का यह गढ़ नहीं ढह सका है। यही वजह है कि अब भाजपा आलाकमान ने इस गढ़ को ढहाने का तय कर लिया है। हाल ही में भोपाल प्रवास पर आए क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने भी जब प्रदेश की लोकसभा और विधानसभा सीटों पर पार्टी की स्थिति की पड़ताल की, तो उसमें भी छिंदवाड़ा सहित महाकौशल क्षेत्र में पूर्व

मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रभाव पर मंथन किया गया था। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का राधौगढ़ विधानसभा क्षेत्र भी भाजपा के निशाने पर है। यहां से पहले दिग्विजय तो बाद में उनके पुत्र जयवर्धन दो बार से लगातार जीतते आ रहे हैं। इसके अलावा पड़ोस वाली सीट से उनके भाई लक्ष्मण सिंह विधायक निर्वाचित होते हैं। समय के साथ हालांकि सिंह का प्रभाव कम हुआ है, लेकिन आज भी उनका परिवार यहां पर अजेय माना जाता है। राधौगढ़ भाजपा के लिए 45 साल से मुश्किल बना हुआ है। 1977 से यह दिग्विजय का गढ़ है।

तीसरे नेता है नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह। भाजपा की लहर हो या फिर कांग्रेस विरोधी, उनकी जीत में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तमाम विरोध और राजनीतिक झंझावातों के बाद भी चुनावी परिणाम उनके ही पक्ष में आता है। वे भिंड जिले की लहार विधानसभा सीट से लगातार निर्वाचित होते आ रहे हैं। 1990 में गोविंद सिंह यहां से पहली बार विधायक बने थे, जिसके बाद से भाजपा कभी भी इस सीट पर नहीं जीत सकी है। यही तीन बड़े चेहरे प्रदेश कांग्रेस में हैं। इनके ही जिम्मे चुनावी कमान रहने वाली है, लिहाजा भाजपा इन्हें इनके ही गढ़ों तक सीमित रखने की रणनीति पर काम कर रही है। खास बात यह है कि इस काम में भाजपा की मदद पूरी तरह से पदों के पीछे से संघ भी कर रहा है।

● कुमार राजेन्द्र

टिकट के लिए कांग्रेस ने तय किया फॉर्मूला

कांग्रेस जिन सीटों पर लगातार पांच बार से चुनाव हार रही है, वहां टिकट देने के पहले पिछले चार विधानसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा करेगी। पार्टी ने भोपाल संभाग के चार जिलों भोपाल, विदिशा, रायसेन और सीहोर की समीक्षा शुरू कर दी है। इसके तहत देखा जा रहा है कि पिछले चार चुनावों में वहां किसने टिकट दिलवाए थे। साथ ही इन जिलों में पिछले 15 सालों में कौन अध्यक्ष रहे। टिकट के बंटवारे में इस बार तीन बातें अहम रहेगी। साफ सुथरी छवि, जातीय आधार और अन्य जातियों में स्वीकारोक्ति। कांग्रेस ने अंगला विधानसभा चुनाव अभी नहीं तो कभी नहीं के तहत लड़ने का निर्णय लिया है। इसी के चलते कमलनाथ टिकटों के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। पार्टी यह भी देख रही है कि किन कांग्रेस नेताओं के भाजपा नेताओं से संबंध हैं और धंधों में भी पार्टनरशिप है।

प्रदेश में अच्छी बारिश की वजह से भले ही बांध छलक रहे हैं, लेकिन फिर भी मप्र पावर जनरेशन कंपनी जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली बनाने को तैयार नहीं दिख रही है। दरअसल कंचनी और विभाग के अफसरों को आम आदमी की जेब की कोई चिंता ही नहीं रहती है। यही नहीं कंपनी को पूरा जोर ताप विद्युत घरों पर रहता है। इसकी वजह उनके आर्थिक हित बताए जाते हैं। दरअसल जल परियोजनाओं से बनने वाली बिजली की लागत एक यूनिट की महज 25 पैसा आती है, जबकि कोयले से उत्पादित बिजली की लागत एक यूनिट करीब साढ़े तीन रुपए आती है। इसके बाद भी मप्र की बिजली कंपनियां जल विद्युत परियोजना से पैदा की जाने वाली सस्ती बिजली से परहेज कर रही हैं। यही वजह है कि प्रदेश में कई जल विद्युत इकाइयों से बिजली उत्पादन ठप पड़ा हुआ है। यह स्थिति तब बनी हुई है जबकि लबालब भरे बांध के पानी को निकालना पड़ रहा है जिससे पानी भी बर्बाद हो रहा है और बिजली भी नहीं बन रही है। मौजूदा समय में जल विद्युत परियोजनाओं से उनकी क्षमता से 70-80 फीसदी तक कम बिजली का उत्पादन हो रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में जल विद्युत प्रोजेक्टों की क्षमता 921 मेगावाट है। इसके मुकाबले केवल 300 मेगावाट ही उत्पादन किया जा रहा है। यह उत्पादन भी मप्र जेनको के स्वामित्व वाली जल विद्युत इकाइयों द्वारा किया जा रहा है। जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली बिजली की लागत महज 25 पैसा प्रति यूनिट आती है, जबकि उसे लगभग 4 रुपए प्रति यूनिट में बेचा जाता है। ऐसे में इस बिजली से 3.75 रुपए तक प्रति यूनिट तक की बचत होती है। उधर, ताप विद्युत प्रोजेक्ट्स से बनने वाली बिजली 3 से 4 रुपए प्रति यूनिट में पड़ती है। पानी से उत्पन्न होने वाली बिजली पर ध्यान नहीं देने की वजह से प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को महंगा टैरिफ चुकाना पड़ता है। अगर जल विद्युत गृहों से पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन किया जाए तो बिजली के टैरिफ को 50 से 60 फीसदी तक कम किया जा सकता है। दरअसल बिजली कंपनियों के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की वजह से कई जल बिजली इकाइयां लंबे समय से बंद हैं। इनमें सबसे प्रमुख टोंस हाइडल प्रोजेक्ट की 105 मेगावाट की तीन नंबर इकाई भी है। यह इकाई प्रतिदिन 25 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन कर सकती है, लेकिन बांध



सस्ती बिजली नहीं भा रही अफसरों को

मप्र देश में सबसे अधिक बिजली उत्पादन राज्यों में से एक है। लेकिन विडंबना यह है कि यहां के उपभोक्ताओं को सबसे महंगी बिजली मिलती है। इसकी वजह यह है कि बिजली विभाग के अफसर मौके का फायदा उठाने में पिछड़े जाते हैं। इस बार मानसून की संभावना बढ़ गई है, लेकिन बिजली विभाग उत्पादन पर ध्यान नहीं दे रहा है।

भरे होने के बाद भी दो साल से इसमें उत्पादन ही नहीं हो रहा है। सस्ती बिजली उत्पादन करने वाली इकाइयां अगर एक बार बंद हो जाती हैं तो अफसरों द्वारा उन्हें फिर चालू तक नहीं किया जाता है। यही वजह है मप्र में हर साल बिजली टैरिफ बढ़ रहा है, जिसका असर बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है।

टोंस हाइडल प्रोजेक्ट रीवा सिरमौर की 105 मेगावाट की यूनिट नंबर तीन में 17 जून 2020 को जेनरेटर स्टेटर जल गया था, जो दो वर्ष एक महीने में बनकर तैयार हुआ था। इस तरह इकाई से लगभग 25 महीने बिजली उत्पादन नहीं हो

सका। इकाई शुरू होने के मात्र 25 दिन बाद फिर जनरेटर स्टेटर जल गया है। इससे यह इकाई एक बार फिर बंद हो गई। माना जा रहा है कि इस इकाई के बंद होने से अब तक लगभग 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का विद्युत उत्पादन में नुकसान हुआ है। इसी संयंत्र की 105 मेगावाट वाली दो नंबर इकाई 5 जनवरी 2022 से बंद है। इसी तरह से गांधी सागर जल विद्युत केंद्र की यूनिट 115 मेगावाट की इकाई 14 सितंबर 2019 से पानी भर जाने के कारण खराब हो गई थी, जो आज तक बंद है। उधर, पेंच हाइडल पावर स्टेशन में 80 मेगावाट की दो इकाई हैं। इसमें से एक नंबर इकाई 20 जुलाई 2022 से 22 सितंबर 2022 तक के लिए एनुअल ओवरहालिंग के नाम पर बंद कर दी गई, जबकि बरसात में सस्ती बिजली आसानी से बनाई जा सकती है।

प्रदेश में पावर जनरेशन कंपनी की देखरेख में बिजली का उत्पादन होता है। इसके लिए 19 विद्युत उत्पादन केंद्र हैं। इनमें ताप विद्युत इकाइयों की संख्या 9 है। इन इकाइयों की बिजली उत्पादन क्षमता 5400 मेगावाट है। वहीं प्रदेश में 10 जल विद्युत इकाइयां हैं। इनकी उत्पादन क्षमता 915 मेगावाट है। अगर सही तरीके से इन जल विद्युत इकाइयों से बिजली उत्पादन किया जाए, तो प्रदेश में ताप विद्युत इकाइयों से उत्पादित बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकेली जल विद्युत परियोजनाएं मप्र के उपभोक्ताओं की जरूरत की बिजली का उत्पादन कर सकती हैं।

● अरविंद नारद

हर साल फिक्स चार्ज के नाम पर लगती है 4200 करोड़ की चपत

प्रदेश सरकार ने जिन कंपनियों से बिजली खरीदी का अनुबंध किया हुआ है, उन्हें बिजली नहीं खरीदने पर भी हर साल फिक्स चार्ज के रूप में 4200 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता है। एग्रीमेंट के मुताबिक, यदि सरकार ने निजी कंपनियों से बिजली नहीं खरीदी तो उन्हें डेढ़ रुपए प्रति यूनिट की दर से फिक्स चार्ज का भुगतान करना पड़ता है। 2019-20 में नियामक आयोग में दाखिल की गई टैरिफ पिटीशन में निजी कंपनियों को 14 हजार करोड़ रुपए का भुगतान करने का जिफ्र किया गया है।



दिल्ली
और पंजाब में सरकार
बनाने के बाद आम आदमी पार्टी
के नेता केजरीवाल का फोकस
गुजरात पर है। वे वहां चुनाव जीतने
नहीं, बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी को
घेरने के लिए सक्रिय हो
रहे हैं।

मनीष सिसोदिया के घर पर हुई सीबीआई रेड से भाजपा और आम आदमी पार्टी के नफे-नुकसान का आंकलन किया जाए तो ज्यादा फायदे में अरविंद केजरीवाल ही लगते हैं। बाद में हो सकता है भाजपा का पलड़ा भारी नजर आए, लेकिन अभी तो अरविंद केजरीवाल ही बीस पड़ रहे हैं। 19 अगस्त, 2022 को हुई सीबीआई की छापेमारी से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल ने ऐसा एक भी मौका गंवाया नहीं है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की जरा सी भी गुंजाइश हो। एक तरफ सीबीआई की छापेमारी चल रही थी और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और उनके साथी लोगों को ये समझाते रहे कि 2024 के आम चुनाव में मुकाबला भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी होगा। हंसी-ठहाकों के बीच मजाक में ही सही, अब अरविंद केजरीवाल को ये कहते भी सुना गया है कि अगर मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाते हैं तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी और फिर वो गुजरात दौरे पर निकल जाते हैं। मुफ्त की चीजें गिनाते-गिनाते कई चीजों की गारंटी भी दे डालते हैं।

देखा जाए तो मुफ्त की चीजों को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो भी कोशिश हो रही है, मौका तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दे डाला है। ये प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जिन्होंने रेवड़ी कल्चर की राजनीति के बहाने अरविंद केजरीवाल को कठघरे में खड़ा किया था और मौके पर ही वो भविष्य के चुनावों के वादों का हलफनामा पेश करने लगे। भाजपा के एक आंतरिक सर्वे के बाद खबर आई है कि आने वाले कई चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पार्टी का चेहरा होंगे, न कि भाजपा के सत्ता में होने के बावजूद राज्यों के मुख्यमंत्री। ऐसे ही एक सर्वे में पता चला है कि गुजरात चुनाव में भाजपा को तो कोई मुश्किल नहीं होने वाली, लेकिन कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल की पार्टी काफी डैमेज कर सकती है और उसका असर सिर्फ गुजरात तक ही सीमित नहीं रहने वाला है।

अरविंद केजरीवाल के लिए ये सब रणनीति निर्देशक तत्व साबित हो रहे हैं और वो उसी

केजरीवाल का लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं

कांग्रेस के लिए आप बनी खतरा

सर्वे के मुताबिक, आज की तारीख में चुनाव होने की सूरत में भाजपा को 115 से 125 सीटें तक मिल जाने की संभावना है। मतलब, भाजपा बड़े आराम से पूर्ण बहुमत हासिल करने जा रही है। लेकिन कांग्रेस बहुमत से बहुत दूर नजर आ रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी से भी उसे ही टक्कर मिल रही है। सच तो ये है कि अरविंद केजरीवाल गुजरात में भी कांग्रेस की ही सीटों पर कब्जा जमाने की कोशिश में हैं। कांग्रेस को, सर्वे के मुताबिक, 39-44 सीटें और आम आदमी पार्टी को 13-18 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये तो यही बता रहा है कि कांग्रेस को गुजरात में इस बार भाजपा से ज्यादा अरविंद केजरीवाल से डर लग रहा है। देखा जाये तो ये सर्वे कांग्रेस को डरा रहा है जबकि अरविंद केजरीवाल की खुशी के राज भी बता रहा है। असल में कांग्रेस को गुजरात में हार का डर नहीं है। कांग्रेस में राहुल गांधी को छोड़कर गुजरात का कोई भी नेता सरकार बना पाने के बारे में नहीं सोच रहा होगा। राहुल गांधी ऐसा इसलिए सोच रहे होंगे क्योंकि कांग्रेस के चिंतन शिविर में मंत्र ही यही दिया था, बस सोच लो... चुनाव जीत रहे हो... और भाजपा को हरा दोगे।

हिसाब से विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस गुजरात पर ही रहने वाला है। जैसे इस साल हुए पांच राज्यों के चुनाव में पहला फोकस पंजाब पर ही रहा। गोवा सहित उप्र और उत्तराखंड तो बस माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि गुजरात में नतीजे इकाई में भी आते हैं तो आगे के चुनावों के लिए दहाई संख्या जैसे असरदार होंगे और यही वजह है कि

अरविंद केजरीवाल का ज्यादा जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात के मैदान में आमने-सामने चैलेंज करने का है, न कि सरकार बनाने की कोई उम्मीद होगी। ट्विटर, सोशल मीडिया और वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस स्कोप तो अब 24x7 हो गया है, फिर भी अरविंद केजरीवाल भाजपा को घेरने के लिए नए-नए इवेंट तैयार कर ले रहे हैं। सीबीआई रेड के बाद मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि भाजपा की तरफ से उनको मुख्यमंत्री बना देने का ऑफर मिला है। फिर क्या था, एक-एक करके कई विधायक दावा करने लगे कि उनको पाला बदलने के लिए 20 करोड़ और रेफरल स्कीम में शामिल होने पर 25 करोड़ ऑफर किया गया है।

भाजपा को तो नहीं, लेकिन गुजरात में केजरीवाल ने कांग्रेस को जरूर हरा दिया है। जब ये बात प्रचारित हो गई तो अरविंद केजरीवाल ने विधायकों की मीटिंग बुलाई। मीटिंग के दौरान ही खबर आने लगी कि 40 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप की तरफ से दावा किया गया कि भाजपा उन विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। मीटिंग के बाद अरविंद केजरीवाल विधायकों के साथ राजघाट पहुंच गए और गांधी प्रतिमा के पास से भाजपा को खूब खरी खोटी सुनाई। और आखिर में ये साबित करने के लिए कि भाजपा उनके विधायकों को नहीं खरीद पाई, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। कोई शक शुबहा भी नहीं था और वो जीत भी गए। सदन के पटल से ही अरविंद केजरीवाल ने तरह-तरह से भाजपा पर हमला बोला और वहां भी मनीष सिसोदिया के यहां सीबीआई की छापेमारी के फायदे गिनाने लगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सीबीआई ने सबसे मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी की है, गुजरात में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर चार फीसदी बढ़ गया है। कहने लगे, मुझे लगता है जिस दिन मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा, उस दिन हमारा 6 प्रतिशत वोट और बढ़ जाएगा।

● इंद्र कुमार

विधानसभा चुनाव में भले ही अभी सवा महीने का समय बाकी है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर हैं। दोनों पार्टियों की कोशिश है कि 2023 में उनकी सरकार बने। लेकिन इस बीच विधायकों की खराब परफॉर्मेंस ने भाजपा और कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल, दोनों पार्टियों के

अंदरूनी सर्वे में उनके अधिकांश विधायकों की स्थिति खराब बताई गई है। ऐसे में पार्टियों में बदलाव की संभावनाओं पर चर्चा चल रही है, वहीं विधायक हार के डर से सुरक्षित सीट तलाशने लगे हैं। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उन विधायकों का टेंशन बढ़ गया है जिनका पार्टी सर्वे रिपोर्ट में परफॉर्मेंस खराब निकला है। भाजपा और कांग्रेस के आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में कई विधायकों को डेंजर जोन में बताया गया है। कांग्रेस में ऐसे 27 और भाजपा में भी ऐसे ही कई विधायकों का टिकट संकट में पड़ गया है। ये विधायक अपने लिए सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं। इन्हें डर है कि इस बार कहीं टिकट ही न कट जाए।

मप्र में अगले साल 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी के आंतरिक सर्वे में मौजूदा 27 विधायकों की स्थिति खराब बताई गई है। कमलनाथ ने बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में हुई पार्टी की प्रदेश समिति प्रदेश बैठक में उन विधायकों को चेताया है जिनकी सर्वे रिपोर्ट में परफॉर्मेंस पुअर है। कांग्रेस के आंतरिक सर्वे के बाद अब कांग्रेस के कई मौजूदा विधायक सीट बदलने के मूड में आ गए हैं। स्थानीय स्तर पर एटीइनकमबेंसी के चलते पार्टी के कई सीनियर विधायक से लेकर नए विधायक सेफ सीट की तलाश में जुट गए हैं। यही वजह है कि कई विधायकों ने अपने विधानसभा से लगी दूसरी विधानसभा सीट पर भी अपनी सक्रियता तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि कमलनाथ के इस गोपनीय सर्वे में उनकी सरकार में मंत्री रहे 8 विधायकों की रिपोर्ट खराब आई है। बताया जा रहा है कि पहली बार में इन्हें अपना परफॉर्मेंस सुधारने की चेतावनी दी जाएगी और फिर भी सुधार नहीं हुआ तो इनके टिकट भी काटे जा सकते हैं।

कमलनाथ अगले साल होने वाले चुनावों को लेकर काफी गंभीर हैं। सभी जानते हैं कि कमलनाथ की एक निजी एजेंसी लगातार सर्वे करती है। सूत्रों का कहना है कि अभी जो सर्वे करवाया गया है, उसमें कांग्रेस के कई विधायकों का परफॉर्मेंस गड़बड़ आया है। इसको लेकर कमलनाथ ने उन्हें चेतावनी भी दी है। सोशल मीडिया पर दौड़ रही इस गोपनीय सर्वे रिपोर्ट में 8 पूर्व मंत्रियों के नाम शामिल हैं, जिनका प्रदर्शन खराब आया है। इनमें कमलेश्वर पटेल, लखन



हार से डरे दोनों पार्टियों के विधायक

नेताओं ने कराई मप्र भाजपा संगठन की किरकिरी

भाजपा का संगठन मप्र में सबसे मजबूत माना जाता है, लेकिन पार्टी के नेता संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। यही वजह है कि संगठन में बड़े औहदों पर बैठे नेताओं के एक के बाद एक कारणों सामने आ रहे हैं। संगठन की छवि बचाने के लिए कर्ता-धर्ताओं को इन नेताओं पर कार्रवाई भी करनी पड़ रही है। 5 महीने पहले ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष की कथित तस्वीरें सामने आने के बाद पार्टी से बाहर कर दिया था। हाल ही में अजा और महिला मोर्चा भी विवादों में पड़ गए हैं। हालांकि संगठन ने अभी इन दानों मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के नेता की वजह से संगठन की देशभर में किरकिरी हुई है। दरअसल, मोर्चा के सह मीडिया प्रभारी दीपक कुमारे की कार्यालय के भीतर घुसकर चप्पलों से जमकर मारपीट की गई है। दीपक ने खुद को भाजपाई और वरिष्ठ नेताओं का करीबी बताकर काम कराने के नाम पर 5 लाख रुपए लिए थे। जब काम नहीं हुआ तो दीपक ने पैसा भी नहीं लौटाया। पीड़ितों को चार साल तक अपने रसूख के दाम पर टालता रहा। आखिर पीड़ितों ने गुरसे में आकर दीपक की भाजपा कार्यालय में घुसकर फिल्मी स्टाइल में मारपीट कर दी। खास बात यह है कि इस मामले में मप्र भाजपा की ओर से पुलिस में किसी तरह की शिकायत दर्ज नहीं की गई है। अजा मोर्चा अध्यक्ष कैलाश जाटव की ओर से सिर्फ इतना कहा गया है कि दीपक को बाहर कर दिया है।

घनघोरिया, हर्ष यादव, सज्जन सिंह वर्मा, हुकुमसिंह कराड़ा, लाखन यादव, पीसी शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति शामिल हैं। इनकी रिपोर्ट आने के बाद कमलनाथ ने इन्हें अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने को भी कहा है।

सिर्फ कांग्रेस के अंदर ही विधायक सीट बदलने की तैयारी में नहीं हैं बल्कि भाजपा के अंदर भी आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में कई विधायकों को डेंजर जोन में बताया गया है। हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव में आधा दर्जन मंत्री ऐसे निकलकर आए हैं जिनके प्रभाव वाले जिले में भाजपा का प्रदर्शन खराब रहा है। पार्टी की सर्वे रिपोर्ट में भी कई विधायकों की स्थिति ठीक नहीं बताई गई है। यही वजह है कि भाजपा के अंदर भी कई विधायकों ने दूसरी सीट तलाशना शुरू कर दिया है। हालांकि भाजपा विधायक कृष्णा गौर का कहना है भाजपा के अंदर पार्टी आलाकमान का फैसला ही सर्वमान्य होता है। जिस विधायक को पार्टी जहां से बोलेगी वहां से वह चुनाव लड़ेगा। भाजपा और कांग्रेस के अंदर मौजूदा विधायकों के साथ और भी कई दावेदार सक्रिय हैं। इनमें तो कई नए चेहरे भी हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री भगवानदास सबनानी ने अपने जन्मदिन के बहाने

हुजूर विधानसभा सीट के कोलार क्षेत्र में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाकर 2023 के चुनाव की दावेदारी पेश कर दी है। भगवानदास सबनानी के होर्डिंग में क्षेत्र के मौजूदा विधायक रामेश्वर शर्मा का फोटो नहीं लगाया गया। मतलब साफ है कि नए चेहरों की दावेदारी और पुराने चेहरों की स्थिति को लेकर भाजपा के अंदर भी अब विधायक दूसरी सीट की तलाश में जुटे हुए हैं। जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे वैसे ही विधायक अपनी विधानसभा सीट पर अपनी स्थिति को भांपते हुए व पाला बदल दूसरी सीट पर किस्मत आजमाने की कोशिश कर सकते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के आंतरिक सर्वे में कई मंत्रियों के विधानसभा में चुनाव हारने की रिपोर्ट आई थी। कई मंत्रियों की सीट बदल दी गई थी। लेकिन अपनी परंपरागत सीट पर चुनाव लड़ने वाले कई मंत्री विधायकी से हाथ धो बैठे थे। अब यही वजह है कि पार्टी सर्वे के आधार पर विधानसभा में अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश में विधायक हैं। जहां स्थिति नहीं सुधरेगी वहां विधायक दूसरी विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं।

● सुनील सिंह

332 करोड़ की सड़कें खराब

प्रदेश में इस बार हुई रिकॉर्डतोड़ बारिश ने सड़कों की दशा बिगाड़ दी है। मप्र की 76000 किलोमीटर सड़कों में से 8 हजार किमी इस बार बारिश में खराब हो गई। ये सड़कें लोक निर्माण विभाग, मप्र सड़क विकास निगम और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की हैं। ऐसा पहली बार है जब मानसूनी बारिश में प्रदेश में इतनी ज्यादा सड़कें खराब हुई हों। अब तक 4 से 5 हजार किमी सड़कें ही खराब होती रही हैं।

55 हजार किलोमीटर का बड़ा हिस्सा लोक निर्माण विभाग के पास है, जिसमें से सबसे ज्यादा 5500 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें पूरी तरह उधड़ चुकी हैं। बाकी खराब सड़कों में 2500 किमी का हिस्सा आरडीसी और एनएचएआई का है। खास बात यह है कि सालभर पहले ही बनी भोपाल से होशंगाबाद जाने वाली सड़क औबेदुल्लागंज से बुदनी के बीच खराब हो गई है। इस मार्ग पर कई बड़े-छोटे गड्ढे हो गए हैं। प्रदेश के 52 जिलों से अब तक आई जानकारी के अनुसार सड़कों की मरम्मत के लिए 332 करोड़ रुपए की जरूरत है। निमाड़ में अभी बरसात जारी होने से वहां खराब हुई सड़कों का आंकलन नहीं हो पाया है।

अब तक की जानकारी के मुताबिक 1400 किलोमीटर की सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, जिनकी मरम्मत के लिए 300 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मप्र सड़क विकास निगम की सड़कों की मरम्मत के लिए 32 करोड़ रुपए की मांग की गई है। आरडीसी और एनएचएआई की खराब हुई टोल सड़कों की मरम्मत ठेकेदार द्वारा की जाएगी। सड़कें ठीक न होने की स्थिति में पेनाल्टी लगाई जाएगी। प्रदेश में पिछले 5 साल में 2500 करोड़ रुपए सड़कों की मरम्मत में खर्च हो चुके हैं। वहीं, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता नरेंद्र कुमार का कहना है कि प्रदेश में खराब हुई सड़कों की जानकारी इस महीने के अंत तक ही आ पाएगी। भोपाल में करीब 500 किमी सड़कें खराब हुई हैं। पिछले दो साल में नगर निगम ने सीवेज और पाइप लाइन डालने के लिए 300 किमी से ज्यादा सड़कें खोदीं, लेकिन इनका रेस्टोरेशन ठीक से नहीं किया। इसलिए ये बारिश भारी पड़ गई। चूनाभट्टी से मनीषा मार्केट, मेन रेलवे स्टेशन, नादरा बस स्टैंड को जोड़ने वाली हमीदिया रोड की सड़कें जर्जर हो चुकी हैं।

राजधानी भोपाल के कोलार सिक्स लेन प्रोजेक्ट को पीडब्ल्यूडी अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी है। यानी, अब कोई अड़चन नहीं है और बारिश के बाद काम की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले 11 किलोमीटर के दोनों ओर के अतिक्रमण को हटाया जाएगा। फिर सिक्स लेन बनना शुरू होगा। जुलाई में टेंडर खुले थे और अगस्त में अथॉरिटी को मंजूरी के लिए भेजा था। आखिरकार अथॉरिटी ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। पीडब्ल्यूडी अफसरों ने बताया, बारिश के बाद सिक्स लेन का

मप्र को मिलेगी 8 लेन एक्सप्रेस-वे की सौगात

अगले साल प्रदेश को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यह सौगात है दिल्ली-वडोरा एक्सप्रेस-वे की। यह एक्सप्रेस वे प्रदेश में गरोट से झाबुआ के बीच से होकर निकल रहा है। खास बात यह है कि यह आठ लेन का बनाया जा रहा है। इसका अब तक 85 फीसदी काम पूरा हो चुका है। इसी तरह से 13 अन्य सड़कों का काम भी अगले साल पूरा करने का लक्ष्य ठेकेदारों को दिया गया है। यह सड़कें भी प्रदेश के कई हिस्सों से होकर गुजरती हैं। यह बात अलग है कि इनमें से कई सड़कों का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है, जिसकी वजह से उनका काम समय पर पूरा होने की उम्मीद कम दिख रही है। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेस-वे को पूरा होने में करीब 10 माह का समय लग सकता है। यह एक्सप्रेस-वे ग्रीनफील्ड एलाइनमेंट रोड है। जिसका निर्माण जंगल, खेत, बंजर भूमि पर किया जा रहा है। खास बात यह है की इसके निर्माण में सभी तरह की सुविधाओं के साथ ही निगरानी के लिए हर एक किलोमीटर पर हाई रिजोल्यूशन कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस एक्सप्रेस-वे पर वीआईडीएस (वीडियो इंसेंट्रिडिटेक्शन सिस्टम) के जरिए गलत एंट्री और एग्जिट पर कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। यही नहीं प्रत्येक 5 किमी पर व्हीकल स्पीड डिटेक्शन सिस्टम के जरिए वाहनों की गति की निगरानी भी की जाएगी। गौरतलब है की इस एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य 2019 में शुरू किया गया था। यह देश के सबसे बेहतरीन मार्गों में एक माना जा रहा है। इस मार्ग को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की देखरेख में बनाया जा रहा है।

काम शुरू करेंगे। टेंडर लेने वाली कंपनी सर्वे करेगी और फिर डिटेल् रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी को सौंपी जाएगी। इसके बाद जिला प्रशासन के जरिए अतिक्रमण हटाया जाएगा। प्रोजेक्ट की लागत 233 करोड़ रुपए है। इसमें फुटपाथ और डिवाइडर बनेंगे, तो बीच में लाइट लगेगी। इसमें सर्व-धर्म ब्रिज का प्रोजेक्ट नहीं है। हालांकि, पुराने ब्रिज के पास एक और ब्रिज 5 करोड़ रुपए से बनेगा। इसके लिए भूमिपूजन 3 सितंबर को हो चुका है।

वहीं इंदौर ग्रामीण क्षेत्रों की 15 प्रमुख सड़कें लोक निर्माण विभाग जल्द बनाएगा। लंबे समय से उठ रही मांग के बाद इन्हें मंजूरी मिल गई है। यह सड़कें 28 करोड़ की लागत से बनेंगी। ग्रामीण क्षेत्र की इन सड़कों की लंबाई 23 किमी रहेगी। इसके लिए राज्य शासन ने 28 करोड़ 54 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इन सड़कों की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव को प्रोजेक्ट बनाकर भेजा गया था। ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख मार्गों व गांवों को जोड़ने वाली हैं। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि इनका निर्माण इसी साल शुरू होगा। इन्हें तय समय पर पूरा किया जाएगा। इनमें सबसे अहम सांवेर-शिप्रा मार्ग हैं। इसके अलावा सांवेर-गवला, रिंगनोदिया पहुंच मार्ग, लक्ष्मणखेड़ी पहुंच मार्ग, कायस्थखेड़ी पहुंच मार्ग, हातोद-अजोनोद और मुंडला बाग से पानोड मार्ग शामिल हैं। इसके अलावा कंपेल से पिवडाय व कंपेल से ही मोरोद मार्ग भी शामिल है। दरअसल बारिश के दौरान इनमें से कुछ सड़कों की स्थिति बेहद खराब हो गई थी। जिसे लेकर ग्रामीणों ने मंत्री सिलावट को जानकारी दी थी। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर से भी ग्रामीणों ने मुलाकात कर इन सड़कों के कारण आने-जाने में हो रही परेशानी के बारे में बताया था। इसके बाद सिलावट ने मुख्यमंत्री से चर्चा कर प्रोजेक्ट सौंपा था।

● विकास दुबे



9 दिन में चले अढ़ाई कोस...

मप्र विधानसभा को न जाने किसकी नजर लग गई है। विधानसभा को सुचारू और संगठित तौर पर चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम द्वारा जितने नवाचार किए जा रहे हैं, वे केवल कागजी साबित हो रहे हैं। यानी विधानसभा सत्र एक तो छोटे हो रहे हैं, वह भी पूरे नहीं चल रहे हैं। इन छोटे सत्रों में सरकार अपने सारे कामकाज निपटा लेती है, लेकिन जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती है। इसके लिए सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं।

मप्र में बड़ी उम्मीदों के साथ 5 दिवसीय मानसून सत्र 13 सितंबर को शुरू हुआ, लेकिन तीसरे दिन ही विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल, सदन में न तो सत्तापक्ष और न ही विपक्ष सदन चलाने के मूड में दिखा। सदन की कार्यवाही देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों पक्ष केवल जनता के बीच अपनी सक्रियता को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि मानसून सत्र की अवधि कम होने को लेकर विपक्ष के हमलों के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने बड़ा फैसला लिया था और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने रोज करीब साढ़े तीन घंटे का टाइम बढ़ाया था। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि दोपहर में डेढ़ घंटे के लंच को खत्म किया गया है। शाम को 5.30 बजे की जगह 7.30 बजे तक सदन चलेगा। ऐसा कर साढ़े तीन घंटे का टाइम बढ़ाया गया और कहा कि जरूरत हुई तो 7.30 के आगे भी समय बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 3 दिन तक चलने वाले मानसून सत्र में एक दिन भी आधे समय से अधिक सदन नहीं चला।

मप्र विधानसभा का मानसून सत्र अप्रत्याशित हंगामे के साथ शुरू हुआ। जो इस बात का संकेत है कि यह सत्र भले ही छोटा है, लेकिन इससे बड़े लक्ष्य साधने की तैयारी सत्तापक्ष और विपक्ष ने की है। 15 सितंबर तक सदन के अंदर और बाहर जो राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिली हैं, उससे यह साफ है कि यह मानसून सत्र चुनावी झलक वाला है। यानी दोनों पार्टियां चुनाव के मद्देनजर एक-दूसरे को घेरने में लगी हुई हैं। जनता के काम के मुद्दे पर चर्चा के नाम पर दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर आरोप लगा रही हैं।

भारी हंगामे के बीच 11 विधेयक पारित

मप्र विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन गुरुवार को भी हंगामे के साथ शुरू हुआ। इससे पहले ही विधानसभा के बाहर तीसरे दिन भी कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया। किसानों की लहसून के दाम नहीं मिलने, पोषण आहार घोटाले के बाद आदिवासी विधायकों के साथ अभद्रता के आरोप को लेकर कांग्रेसी धरने पर बैठ गए। सदन के भीतर भी जमकर हंगामा हुआ, जहां आदिवासी विधायक पांचीलाल मेढ़ा ने अपनी जान का खतरा बताया। वे मीडिया के सामने फूट-फूटकर रोए। इधर, भारी हंगामे के बीच 11 विधायक पारित कर दिए गए और विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए खत्म कर दी गई। उल्लेखनीय है कि विधानसभा का मानसून सत्र 13 सितंबर से शुरू हुआ था, जो 17 सितंबर तक चलने वाला था।

9 दिन में चले अढ़ाई कोस की कहावत को एक बार फिर मप्र विधानसभा ने चरितार्थ किया और 5 दिन का सदन 3 दिन में ही सिमट गया। इस तीन दिन के सत्र में सरकार ने 11 विधेयक पारित करने के साथ ही मौजूदा वित्तीय सत्र का पहला अनुपूरक बजट भी पेश किया। इसके तहत 9784.95 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। इसमें सबसे ज्यादा राशि लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के लिए प्रस्तावित है जिसे बरसात से बर्बाद हुई सड़कें सुधारने के लिए बड़ी धनराशि चाहिए। अब इस पर विधानसभा में

चर्चा होगी। इसके बाद इसे पारित किया जाएगा। अनुपूरक बजट में कृषि, सड़क, बिजली पेयजल पोषण सहित अन्य अधोसंरचना से संबंधित विभागों के लिए ज्यादा राशि रखी गई। पहले अनुपूरक बजट में कृषि सड़क, बिजली पेयजल पोषण सहित अन्य अधोसंरचना से संबंधित विभागों के लिए ज्यादा राशि रखी गई है। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास और एनवीडीए के लिए राशि रखी गई है। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के लिए 1229 करोड़ प्रस्तावित हैं। इसमें से अधिकांश राशि खासतौर पर राज्यभर की बर्बाद सड़कें संवारने पर खर्च की जानी है। इस बार प्रदेश में मानसून के सीजन में जोरदार बारिश हुई है जिसमें राज्यभर में कई हजार किमी सड़कें उखड़ चुकी हैं। विभाग को इनकी मरम्मत के लिए ही कई करोड़ रुपए की दरकार है। पहले अनुपूरक बजट को मिलाकर 2.88 लाख करोड़ पार का बजट हो गया। बता दें कि मौजूदा वित्तीय वर्ष का मुख्य बजट 2.79 लाख करोड़ का है। सामान्यतः सरकार एक वित्तीय सत्र में तीन अनुपूरक ले आती है। अभी पहले अनुपूरक बजट को

मिलाकर 2.88 लाख करोड़ पार का बजट हो जाएगा। अनुपूरक बजट में सरकार ने सड़क, खेती और पोषण पर फोकस किया है। इसमें पीडब्ल्यूडी के लिए 1229 करोड़, कृषि विभाग के लिए 1100 करोड़, महिला एवं बाल विकास के लिए 1076 करोड़, एनवीडीए के लिए 930 करोड़ और ऊर्जा विभाग के लिए 750 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मानसून सत्र के लिए दोनों पक्षों ने जमकर तैयारी की थी। सत्र के पहले दिन से ही हंगामा शुरू हो गया। विधानसभा के सामने कांग्रेस नेताओं ने लहसून लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने लहसून को विधानसभा के गेट पर फेंक दिया और सरकार पर जमकर आरोप लगाए। इस बार नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, बाढ़ और अतिवृष्टि से परेशान किसानों को मुआवजा नहीं मिलने और कानून व्यवस्था समेत कैंग की रिपोर्ट को लेकर सदन में भी हंगामे के संकेत दे दिए। कांग्रेस के विधायकों का कहना था कि आज किसानों को अपनी उपज सड़कों पर फेंकने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्हें एक रुपए किलो दाम मिल रहे हैं। तमाम किसानों की योजनाएं बंद की जा रही हैं। आज परिस्थितियां किसानों के सामने हैं, आप विधायक खरीद रहे हैं, लेकिन किसानों की उपज खरीदने की बात आती है तो उसकी लागत का भी दाम नहीं दे पा रहे हैं। अब लागत मूल्य दोगुनी हो गई है। इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सचिन यादव, विधायक कुणाल चौधरी समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। सचिन यादव का आरोप है कि भाजपा सरकार विधायक खरीद सकती है, लेकिन किसानों का लहसून नहीं खरीद सकती है। कुणाल चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ नारेबाजी भी की। कांग्रेस विधायक सचिन यादव और कुणाल चौधरी ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया।

दूसरे दिन पोषण आहार के संदर्भ में आई कैंग की रिपोर्ट को लेकर हंगामा हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में अपनी बात रखी और बताया कि पोषण आहार में सरकार ने दोषियों पर लगातार कार्यवाही की है। पोषण आहार में कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन विपक्ष मुख्यमंत्री को सुनने के लिए तैयार नहीं था और बार-बार हंगामा करते रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी। तीसरे दिन भी विपक्ष हंगामे पर उतारू रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेसियों ने विधानसभा के मेन गेट पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। यही नहीं कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेड़ा फूट-फूटकर रो पड़े। उन्होंने रोते हुए आरोप लगाया कि विधानसभा में पुलिस वालों ने उनसे मारपीट की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सिरोंज से



230 में से सिर्फ 15 विधायकों ने दी संपत्ति की जानकारी

मद्र में भाजपा-कांग्रेस के विधायक अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने से परहेज कर रहे हैं। विधानसभा के संकल्प को ही विधायक टेंगा दिखा रहे हैं। 230 में से सिर्फ 15 विधायकों ने संपत्ति की जानकारी सौंपी है। जिसमें 6 कांग्रेस और 9 भाजपा विधायक शामिल हैं। विधानसभा के पत्र के बाद भी जानकारी नहीं दी। जबकि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और नेता प्रतिपक्ष ने खुद संपत्ति का ब्यौरा दिया है। संपत्ति की जानकारी को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि कई विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसलिए जानकारी नहीं दी। बाइक पर विधायक बनते हैं, फिर अपार संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। सबको नैतिकता के आधार पर पूरी जानकारी सौंपनी चाहिए, जो सालभर कमाया उसका ब्यौरा देना जरूरी है। कमलनाथ पर जानकारी नहीं देने का आरोप लगाना गलत है। सरकार में रहते हुए भी उन्होंने सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल नहीं किया। वो खुद अपना निजी हेलीकॉप्टर और वाहन से घूमते थे। ऐसी छोटी-मोटी चीजों में वो गड़बड़ी नहीं करते, बल्कि लोगों की मदद करते हैं। विधायकों की तुलना कमलनाथ से करना बिलकुल गलत है।

भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा ने धक्का-मुक्की करते हुए मेरा गला दबा दिया। मेरी जान को खतरा है...। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने पांचीलाल के आंसू पोंछे। कांग्रेस ने सदन की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने भाजपा विधायक पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस के विधायक पांचीलाल मेड़ा को जान का खतरा है। उन्होंने सरकार से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। प्रश्नकाल के शुरुआत में ही नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने विधायक के साथ बदसलूकी का मुद्दा उठाया। इस बात पर संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा और नेता प्रतिपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष ने इस पर चर्चा करवाने की मांग की। भारी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को थोड़ी देर के लिए स्थगित करना पड़ा। इसके बाद हंगामा होता देख मंत्री भूपेंद्र सिंह के अनुरोध पर अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना

है, जैसा कांग्रेस का गाना होगा, वैसा हमारा बजाना होगा। विपक्ष सदन चलने नहीं देना चाहता, इसका कारण विपक्ष का एक्सपोज होना है। उनके पास कोई वक्ता भी नहीं है, इसलिए सिर्फ हंगामा कर सदन के संचालन में अवरोध उत्पन्न करते हैं।

मानसून सत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों की उपस्थिति और उनके रुख को देखकर साफ लग रहा था कि माननीय विधानसभा चलाने के पक्ष में नहीं हैं। इस कारण सरकार ने जहां फटाफट अपने सारे काम निपटा लिए, वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। इस कारण प्रदेश की जनता के लिए उठाए जाने वाले मुद्दे हंगामे में दब गए। सदन में न तो महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध, बाढ़-बारिश से हुए नुकसान पर चर्चा हो पाई और न ही आगामी योजनाओं का खाका तैयार हो पाया। इसके साथ ही विधानसभा का एक और सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया है और माननीय अपने घरों को लौट गए हैं।

● लोकेंद्र शर्मा

2024 तक हर घर में नल से जल



जल मिशन के कामों में अचानक तेजी

2024 तक काम पूरा करना है। कोरोना के दो साल व कांग्रेस के कार्यकाल में काम नहीं हुए, इसलिए रुके कामों को तेजी से पूरा करवा रहे हैं। इस जल्दबाजी के पीछे आम चुनाव 2024 तो नहीं? समय पर योजना का लाभ मिलने लगेगा तो सरकार को चुनाव में फायदा तो मिलेगा ही। 15 हजार गांवों की जमीनें सूखी है, वहां क्या करेंगे? ये सही है लेकिन प्राथमिक तौर पर 5 हजार गांव ऐसे हैं जहां 1 से 3 किमी की दूरी पर पानी है। वहां से पाइप लाइन डालकर पानी घर-घर तक पहुंचाएंगे। शेष 10 हजार गांवों का क्या? इन गांवों में गांवों तक पानी पहुंचाने में ज्यादा राशि की जरूरत होगी। इस संबंध में केंद्र से सकारात्मक मार्गदर्शन जल्द मिल जाएगा।

मोदी सरकार ने देश के सभी गांवों में हर घर तक साफ और सुरक्षित पानी पहुंचाने की संकल्पना के साथ 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक पानी की बचत करके भारत के ग्रामीण इलाकों में नल के जरिए स्वच्छ जल पहुंचाना है। जल जीवन मिशन के तहत चलाए गए इस कार्यक्रम को हर घर जल का नाम दिया गया है। इसके तहत प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। 3.6 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना पूरे देश में तेजी से लागू की जा रही है। जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 15 अगस्त, 2019 को सिर्फ 3.23 करोड़ परिवारों तक पेयजल का कनेक्शन था। अब यह संख्या बढ़कर 9.85 करोड़ तक पहुंच गई है। अर्थात् मात्र तीन वर्षों में नल से जलापूर्ति वाले ग्रामीण घरों की संख्या में 203 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार देश के कुल 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से आधे से अधिक (51 प्रतिशत) परिवारों तक नल से जल का कनेक्शन पहुंचा दिया गया है।

इस योजना के सामने एक बड़ी चुनौती जल

उपलब्धता की है। सूखती नदियों-झीलों, लगातार घटते भूजल स्तर, विलुप्त होते तालाबों और बढ़ते जल प्रदूषण के बीच सभी ग्रामीण घरों तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति आसान नहीं है। इसी को देखते हुए यह योजना जनभागीदारी से चलाई जा रही है और इसमें जल संरक्षण पर भी बराबर ध्यान दिया गया है। अब तक स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में 14 लाख से अधिक जल संग्रहण पिट बनाए जा चुके हैं।

यह योजना महिला सशक्तीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है, क्योंकि घर में पानी की व्यवस्था की जिम्मेदारी आमतौर पर महिलाओं की होती है। कई इलाकों में पीने के पानी के लिए महिलाओं को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। एक आंकड़े के अनुसार भारतीय महिलाएं हर साल औसतन 15 करोड़ काम के दिन पानी लाने में खर्च करती हैं, जिसका इस्तेमाल उनकी शिक्षा, हुनर विकास या किसी मानसिक-शारीरिक विकास में हो सकता है। प्रधानमंत्री उज्वला योजना के तहत जहां महिलाओं को परंपरागत चूल्हे के धुएँ के बीच खाना बनाने की मजबूरी से मुक्ति मिली, उसी तरह अब उन्हें पेयजल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

● राकेश ग्रोवर

भाजपा विधानसभा के साथ-साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जोर-शोर से जुटी है। केंद्र सरकार का टारगेट है कि राष्ट्रीय जल मिशन के तहत 2024 तक हर घर में पानी पहुंच जाए। इसके लिए मद्र, राजस्थान, उप्र सहित कुछ राज्यों में 40 हजार से ज्यादा पानी की टंकियां बनना है। अकेले मद्र के 26 हजार गांवों में 10 हजार पानी की टंकी बनाई जाना है। इस काम में लेबर की कमी, बनाने की लागत ज्यादा हो चुकी और कंपनियों पुराने रेट पर काम करने को राजी नहीं, जैसी कुछ तकनीकी खामी सामने आ रही है, लेकिन केंद्र हर समस्या दूर करने के रोडमैप तैयार कर रहा है। इसके लिए हाल ही में भुवनेश्वर में भारत सरकार की मिशन डायरेक्टर सीनियर आईएएस विनी महाजन की मौजूदगी में एक वर्कशाप हुई थी। इसमें देशभर के राज्यों से आए मिशन से जुड़े अफसरों ने मंथन किया था। मिशन डायरेक्टर ने एक नोडल एजेंसी बनाई है, जो प्रोजेक्ट का हर स्तर पर सरकार के विभागों से क्लियरेंस करवाएगी, ताकि काम समय पर पूरा हो सके।

राज्यों में काम चल तो रहा है, लेकिन उसमें धीमापन है। समस्या लेबर की आ रही है। उप्र, बिहार और गुजरात के लेबर दूसरे राज्यों में नहीं जा रहे हैं। मद्र के पीएचई व जल निगम के पास 200 लेबर गैंग हैं जबकि जरूरत एक हजार लेबर गैंग (एक लेबर गैंग में 10 से 15 श्रमिक) की है। कोरोना के बाद निर्माण लागत भी बढ़ गई है। अब कई कंपनियां पुराने रेट पर काम करने को तैयार नहीं हैं। इसका समाधान यह निकाला गया कि जहां टंकियां बनने में समय लगेगा, वहां संपवेल से नलों तक पानी सप्लाई करने के लिए पाइप लाइन बिछाई जाएगी। वहीं, नए प्रोजेक्ट का टेंडर लेने वाली कंपनी मार्च 2024 तक काम पूरा कर देगी, उसे इंसेंटिव भी मिलेगा।

बड़े टैंकों में पानी जमा कर सौर ऊर्जा के माध्यम से सप्लाय करेंगे। जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रिक पंप भी लगाएंगे। जहां संपवेल से पानी सप्लाई हो जाएगा, वहां पानी की टंकी का निर्माण निरस्त कर देंगे। लोहे की टंकी भी बनाएंगे और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या फिल्टर प्लांट की मदद से पानी नल तक सप्लाई करेंगे। 15 अगस्त 2019 को शुरु हुए जल मिशन के पूरा होने की डेटलाइन मार्च 2024 तय है। इसमें फोकस देश के 50 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को किया गया है। गांवों में महिलाओं को मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है। घर पर ही नल से उनकी दिक्कतें दूर होंगी। जल निगम मद्र के एमडी तेजस्वी नायक का कहना है कि शासकीय विभागों से समन्वय बनाकर समय पर एनओसी ले रहे हैं, ताकि 2024 तक काम पूरा हो सके। 7 व 8 जुलाई को निगम के अफसरों की बैठक कर रिव्यू किया गया था। जो सुझाव मिले हैं, उन पर भी काम जारी है।

म प्र में जमीन के कम्प्यूटरीकरण से आदिवासियों व दलितों की जमीन पर प्रभावशाली लोगों का कब्जा और उनका नाम दर्ज हो गया है। सागर जिले के बसा गांव में रहने वाले वीरसिंग गोंड उन आदिवासियों की सूची में शामिल हैं जिनकी पूंजी पर सेंधमारी हुई है। दरअसल उनकी 40 एकड़ (16.19 हेक्टेयर) जमीन किसी अन्य के नाम दर्ज हो गई है। सागर जिले में ऐसे दर्जनों किस्से हैं जो बताते हैं कि मप्र में हुए जमीन कम्प्यूटरीकरण मुहिम में कई ग्रामवासियों की जमीनों का नामांतरण किया गया। इससे असली मालिक की जमीन पर अनुचित व्यक्ति का मालिकाना हक और कब्जा हो गया है। जब लैंड कंप्लिक्ट वाच (एलसीडब्ल्यू) ने इस मामले की तफ्तीश के लिए सागर जिले का दौरा किया, तब कम्प्यूटरीकृत हुई जमीनों में गलत नामांतरण के कुछ दस्तावेज सामने आए। इस प्रकरण से परिचित समाजसेवकों और ग्रामीण स्तर के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि इस जमीन के हेर-फेर में कई आदिवासी और दलितों की जमीन कब्जाई गई है।

दलितों-आदिवासियों की जमीन दूसरों के नाम

अगस्त 2008 में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर भू-अभिलेखों के सुधार की पहल की। लेकिन इससे पहले 1999-2000 में मप्र सरकार ने पहले से चल रही केंद्र प्रायोजित स्कीम कम्प्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड (सीएलआर) के तहत राज्य में 55 हजार से अधिक गांवों के भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किया। इससे स्पष्ट है कि कम्प्यूटराइजेशन के मामले में मप्र शुरुआत से ही अन्य राज्यों से आगे था। सीएलआर योजना के अंतर्गत सागर जिले में भी जमीनों के रिकॉर्ड ऑनलाइन किए गए। इसमें सागर जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर स्थित केसली तहसील भी शामिल है। केसली में 100 एकड़ से अधिक जमीन का हेर-फेर पाया गया। जमीनी कार्यकर्ताओं व मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह फेरबदल करीब 1,000 एकड़ तक का हो सकता है।

एलसीडब्ल्यू के हाथ लगे दो दस्तावेजों में से एक पटवारी द्वारा तहसीलदार को लिखा गया प्रतिवेदन और न्यायालय उपखंड अधिकारी द्वारा दिया गया राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र है। दोनों पत्रों में दी गई सूचियों के अनुसार, केसली में कुल 30 लोगों की 126.56 एकड़ (51.21 हेक्टेयर) जमीन में नामांतरण का प्रकरण सामने आया। इनमें 20 प्रभावित गांव वालों की जमीनों



सुधार के लिए जारी है संघर्ष

जहां कुछ लोगों की गलत जमीन नामांतरण में सुधार हुआ तो वहीं कई ग्रामीण ऐसे हैं, जो अब भी जमीन अपने नाम वापस करवाने का संघर्ष कर रहे हैं। सेंटर फॉर लैंड गवर्नंस के असोसिएट डायरेक्टर व लैंड एक्सपर्ट प्रणव रंजन चौधरी बताते हैं, देश में हर जगह जमीन कम्प्यूटरीकरण अलग-अलग हो रहा है, जिसमें कहीं सरकार सरकारी कर्मचारियों से करवा रही तो कहीं किसी दूसरी कंपनी को ठेका दे रही है। ऐसे में जमीन विवरण में गलत टाइपिंग, स्पेलिंग से राज्य स्तर पर जमीन नामांतरण किया जा रहा है। उनके अनुसार, यह स्पष्ट नहीं कि देश के अनुमानित 3,200 करोड़ लैंड रिकॉर्ड में यह किस पैमाने पर हो रहा है। वह कहते हैं, जमीन कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। जिसकी जमीन का कम्प्यूटरीकरण हुआ है, उसे उसकी प्रतिलिपि दी जानी चाहिए, ताकि पता चल सके उसकी जमीन का नामांतरण तो नहीं हुआ।

में फर्जी नाम दर्ज हैं। वहीं 10 लोगों की जमीनों के रिकॉर्ड में सुधार किया गया है। एलसीडब्ल्यू ने जब केसली के तीन गांव का दौरा किया तो पाया कि जिन रिकॉर्ड्स में पहले आदिवासी और दलित भू-स्वामियों का नाम होता था, वहां अब स्थानीय व बाहरी प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम हैं। देश में आदिवासियों व दलितों की जमीनों पर कब्जा व विस्थापन की समस्या को सरकार और अदालतों ने भी स्वीकार किया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, मप्र की कुल जनसंख्या में 21.1 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है। वहीं राज्य सरकार के मुताबिक राज्य में 15.40 प्रतिशत अनुसूचित जातियां हैं।

केसली तहसील में पटवारी रहे शैलेंद्र सिंह के वर्ष 2018 के प्रतिवेदन (जो एलसीडब्ल्यू के पास है) के मुताबिक, पूर्व पटवारियों ने जमीन के अभिलेखों में अनुचित नाम दर्ज किए। पटवारी शैलेंद्र की सूची में 23 लोगों का नाम है जिनकी कुल 82.06 एकड़ जमीन (33.21 हेक्टेयर) में हुए गलत नामांतरण का विवरण है। इसमें अधिकतर आदिवासी और दलितों की जमीनें शामिल हैं। शैलेंद्र अपने इस पत्र में खसरो में हुए नामांतरण का ब्योरा देते हुए कहते हैं, खसरो का मिलान किया गया जिसमें विसंगतियां पाई गईं। इसकी बारीकी से जांच की गई है। बिना पीठासीन अधिकारी (तहसीलदार) के आदेश के कम्प्यूटर अभिलेख में खसरो की

दुरुस्ती की गई। नियमानुसार पीठासीन अधिकारी के आदेश पर ही जमीन नामांतरण किया जा सकता है। ऐसे में यह जमीन नामांतरण गैरकानूनी है। इस बात की पुष्टि पटवारी शैलेंद्र करते हुए कहते हैं कि ये मामले धारा 420 (भारतीय दंड संहिता) के अंतर्गत धोखाधड़ी और बेईमानी के हैं।

पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार, नाहरमाऊ गांव के मुलु गोंड की 7.11 एकड़ (2.88 हेक्टेयर) जमीन सेमरा गांव के विकास (उपनाम रिपोर्ट में मौजूद नहीं) के नाम हुई। इसी तरह मेहगुवा गांव की नर्मदा गोंड की 3.16 एकड़ (1.28 हेक्टेयर) जमीन रामनाथ (उपनाम रिपोर्ट में मौजूद नहीं) के नाम हो गई। ऐसे 21 लोगों के और उदाहरण इस रिपोर्ट में दर्ज हैं। लेकिन, यह नामांतरण कैसे हुए, इस पर शैलेंद्र सिंह बताते हैं, पहले एनआईसी साफ्टवेयर चलता था जिसमें किसी भी कम्प्यूटर ऑपरेटर को हल्का अधिकार दे दिए जाते थे। पटवारी या उसकी आईडी लेकर कोई भी कम्प्यूटर ऑपरेटर (जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर) काम कर सकता था। उनका कहना है कि कलेक्टर के आदेश से कार्रवाई हुई और शायद 16 के रिकॉर्ड्स में सुधार हुए। लेकिन एलसीडब्ल्यू ने जब खसरो की ऑनलाइन जांच की तब 23 में से 14 लोगों की जमीन का गलत रिकॉर्ड ज्यों का त्यों पाया।

● राजेश बोरकर

चंबल के बीहड़ों की सूरत बदलने के लिए अटल चंबल प्रगति पथ (एक्सप्रेस-वे) अब बीहड़ों से दूर हो जाएगा। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने बीहड़ में एक्सप्रेस-वे के निर्माण पर आपत्ति लगा दी है। इसके बाद एक्सप्रेस-वे का ले-आउट फिर से बनाया जा रहा है। चार साल पहले इस मेगा हाईवे की प्लानिंग पर काम शुरू हुआ, जब से पांच बार इसका नाम और चार बार ले-आउट बदला जा चुका है। बीहड़ों में एक्सप्रेस-वे के लिए सरकारी जमीन एनएचएआई को दे दी गई थी, निजी जमीनों के अधिग्रहण के लिए सरकार ने बजट स्वीकृत कर दिया। अब यह पूरी कवायद शून्य हो गई है। प्रोग्रेस-वे अब कहाँ से गुजरा जाए? इसके लिए नए सिरे से सर्वे होगा और पांचवी बार नया ले-आउट बनेगा।

भारतमाला परियोजना के तहत राजस्थान के कोटा जिले के दीगोद से शुरू होकर श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले से होते हुए उप्र सीमा के चिरगांव तक 404 किमी लंबा अटल प्रोग्रेस-वे स्वीकृत हुआ था। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार ने 6000 करोड़ रुपए का बजट भी पास कर दिया था। मप्र सरकार को इसके लिए जमीन देनी थी। मुरैना, श्योपुर और भिंड जिले में सरकारी जमीन तो एनएचएआई को करीब 6 महीने पहले ही आवंटित कर दी थी। इसके बाद पर्यावरण मंत्रालय की अनापत्ति (एनओसी) लेने की कार्रवाई चल रही थी। पर्यावरण मंत्रालय ने न सिर्फ एनओसी देने से मना किया है, बल्कि बीहड़ों में एक्सप्रेस-वे के निर्माण को पर्यावरण के लिए कई तरह से खतरनाक बताया है। इससे चंबल नदी के जलीयजीवों से लेकर हरियाली तक को खतरा बताया है। इस आपत्ति के बाद एनएचएआई ने इस प्रोजेक्ट को बीहड़ों से दूर निकालने के लिए दूसरे ले-आउट बनाने का निर्णय लिया है। माना जा रहा है कि यह प्रोग्रेस-वे अब जौरा, कैलारस, सबलगढ़, अंबाह कस्बों व एक सैकड़ से ज्यादा गांवों के पास से होकर गुजरेगा।

साल 2018 में बीहड़ में मेगा हाईवे की योजना बनी, तब इसका खर्च 3000 करोड़ रुपए आंका गया। पहले इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण का मप्र सड़क विकास प्राधिकरण (एमपीआरडीसी) के पास था, बाद में इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को सौंपा गया है। सबसे पहले बनी प्लानिंग में यह एक्सप्रेस-वे राजस्थान के सवाई माधोपुर को जोड़ने के लिए श्योपुर जिले के दांतरदा क्षेत्र से शुरू होकर मुरैना, भिंड होते हुए उप्र की सीमा तक जाना था। फिर इसका ले आउट बदला और सवाई माधोपुर की जगह राजस्थान के कोटा व अन्य महानगरों से जोड़ने के लिए दीगोद से बनाने की योजना बनाई। तीसरी बार ले-आउट तब बदलना पड़ा जब चंबल नदी घड़ियाल सेंक्चुरी के क्षेत्र में एक्सप्रेस-वे आ गया। चौथी बार ग्रामीणों के विरोध के कारण ले-



प्लानिंग में फंसा अटल प्रोग्रेस-वे

श्योपुर में अब भी 90 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण बाकी

अटल प्रोग्रेस-वे में जिन तीन जिलों की निजी जमीनें आ रही हैं, वहां किसानों को अधिग्रहण के लिए समझाना मुश्किल हो रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत श्योपुर जिले में है। यहां कुल जमीन 609 में से करीब 90 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण बाकी है। राज्य सरकार जल्द इस काम में कलेक्टरों को लगा सकती है। विभाग का प्रयास है कि इस साल अटल प्रोग्रेस-वे का काम शुरू हो जाए। केंद्र सरकार से भी जल्द ही बात होगी, ताकि एनएचएआई काम शुरू कर सके। अटल प्रोग्रेस-वे मप्र में भिंड जिले के पास उप्र के इटावा से राजस्थान के कोटा तक बनाया जाना है। इसके लिए 404 किमी लंबी सड़क चंबल के बीहड़ों से भी होकर गुजरेगी। इस परियोजना की घोषणा सन् 2013 में की गई थी। इसके लिए हाल ही में भिंड, मुरैना और श्योपुर कलां जिलों से कई भूस्वामियों को विस्थापित करने की भी कोशिश की गई थी। जमीन अधिग्रहण के नाम पर इन जिलों के करीब 10 हजार ग्रामीण परिवारों और किसानों को मुआवजा दिया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित अटल प्रोग्रेस-वे मप्र में चंबल नदी के किनारे-किनारे बना है।

आउट बदलने की मांग उठी पर उसे निरस्त कर दिया गया। लेकिन अब पर्यावरण मंत्रालय की आपत्ति के बाद चौथी बार ले-आउट बदला जा रहा है। चार साल पहले जब इसकी प्लानिंग बनी तब इसका नाम एक्सप्रेस-वे रखा गया, फिर चंबल एक्सप्रेस-वे, फिर चंबल प्रोग्रेस-वे, कभी अटल चंबल एक्सप्रेस-वे के नाम से इसकी फाइल चली और फिर अंत में अटल चंबल प्रगति पथ नाम रखा गया। मुरैना जिले में अटल चंबल प्रगति पथ के लिए 1043 हेक्टेयर सरकारी जमीन तो पहले ही एनएचएआई को दे दी गई थी। बीते छह महीने से

निजी जमीन के अधिग्रहण की तैयारी चल रही थी। मुरैना जिले में किसानों की 5500 किसानों की 453 हेक्टेयर जमीन ली जानी थी। जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों का जमीन के बदले दोगुनी कीमत की जमीन या फिर दोगुना नकद मुआवजा देने का प्रावधान रखा गया। इसके बाद 2300 किसानों ने जमीन के बदले मुआवजा मांगा, वहीं 3200 किसानों ने जमीन के बदले दूसरी जगह दोगुनी जमीन मांगी। यह सारी प्रक्रिया पर्यावरण मंत्रालय के बाद से जहां के तहां रोक दी गई है। जो सरकारी जमीन आवंटित हुई है, उसे एनएचएआई वापिस जिला प्रशासन को लौटाएगा।

मप्र का 'अटल प्रोग्रेस-वे' छह पैकेज में तैयार होगा। हर पैकेज में 40 से लेकर अधिकतम 61 किमी तक का हिस्सा रखा गया है और लागत भी तय कर दी गई है। इसकी मुख्य सचिव समीक्षा करने जा रहे हैं। इसमें तय हो जाएगा कि निजी जमीन के अधिग्रहण को जल्द से जल्द कैसे किया जाएगा। पूर्व में जमीन के बदले दो गुना तक जमीन देने का प्रावधान रखा गया था, लेकिन अब कंपनसेशन दिया जा सकता है। अटल प्रोग्रेस-वे मप्र का पहला एक्सप्रेस-वे होगा, जो सवा तीन सौ किमी लंबा है। केंद्रीय कैबिनेट से इस प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। अटल प्रोग्रेस-वे में 1623 हेक्टेयर सरकारी जमीन पूरी तरह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के सुपुर्द की जा चुकी है। फरिस्ट की 403 हेक्टेयर जमीन के लिए केंद्र सरकार के प्रस्ताव 14 जून 2022 को भेजा जा चुका है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में 1178 हेक्टेयर जमीन निजी क्षेत्र की आ रही है जो भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले की है। इसका अधिग्रहण भी जल्द किया जाएगा। मुरैना और श्योपुर में क्रमशः 455 व 609 सर्वाधिक निजी जमीन है। भिंड और मुरैना कलेक्टर ने 211 हेक्टेयर जमीन के बदले जमीन देकर उसका अधिग्रहण कर लिया है।

● बृजेश साहू

मप्र का वन विभाग यथा नाम तथा गुण को प्रदर्शित करने के मामले में कभी पीछे नहीं रहता है। इस विभाग की भर्शाहाही इससे समझी जा सकती है कि केंद्र सरकार द्वारा आधा दर्जन सिटी फॉरेस्ट बनाने की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन विभाग ने उससे दोगुने यानि की एक दर्जन बना डाले। दरअसल केंद्र सरकार ने दो साल पहले देश के बड़े शहरों के लिए करीब 100 सिटी फॉरेस्ट प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं। इनमें मप्र के लिए जिन आधा दर्जन शहरों के लिए स्वीकृति दी गई थी, उसमें भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, सागर तथा देवास शामिल हैं। इन नगर वनों को पर्यावरण की दृष्टि से विकसित कर नए करना और सिटी एक्शन प्लान के तहत एक एरिया विशेष में पौधरोपण केंद्र सरकार ने मप्र के लिए 6 शहरों को मंजूरी दी थी, लेकिन राजी सिटी फॉरेस्ट बना दिए गए। इनमें भोपाल, देवास में तो बेहतर कार्य हुआ, लेकिन ग्वालियर को ज्यादा फंड मिलने के बाद भी काम गति नहीं पकड़ पा रहा है। हद तो यह है कि ग्वालियर में फॉरेस्ट एरिया विकसित करने के लिए विभाग के अधिकारी वन भूमि का चयन तक नहीं कर सके हैं। यह हाल तब बने हुए जबकि हर सिटी फॉरेस्ट के लिए केंद्र की ओर से निर्धारित 2 करोड़ रुपए की धनराशि में से 1.40 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य सरकारों को दो साल पहले ही जारी की जा चुकी है।

देश के विभिन्न हिस्सों में सिटी फॉरेस्ट बनाने के पीछे आम लोगों को पौधों और जैव विविधता पर जागरूकता पैदा करना है। इसके अलावा वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण पर शिक्षा जिसमें खतरों की धारणा भी शामिल है। शहरों का पारिस्थितिक कायाकल्प करना और संबंधित इलाकों में प्रदूषण शमन, स्वच्छ हवा, शोर में कमी, जल संचयन और गर्मी द्वीपों के प्रभाव में कमी से शहरों के पर्यावरण की रक्षा करना है।

किसी भी शहर में सिटी फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के लिए 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वन विभाग राशि जारी करता है। अधिकतम 50 हेक्टेयर में सिटी फॉरेस्ट विकसित किया जाता है। भोपाल का सिटी फॉरेस्ट 50 हेक्टेयर में यह नगर वन विकसित किया गया है। उज्जैन और देवास के सिटी फॉरेस्ट प्रोजेक्ट का निरीक्षण केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की टीम कर चुकी है। टीम ने भोपाल और देवास के प्रोजेक्ट को बेहतर बताया है। भोपाल और ग्वालियर के सिटी फॉरेस्ट प्रोजेक्ट दो साल पहले मंजूर हो गए थे, इसमें से ग्वालियर में हालात बेहद खराब हैं। इसके तहत प्रत्येक सिटी फॉरेस्ट प्रोजेक्ट को 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राशि दी जाती है। एक नगर वन वनाच्छादित क्षेत्र होता है, जो शहरों के आसपास के क्षेत्रों में स्थित होता है। यह शहर में जंगल मनोरंजन, शिक्षा, जैव



दोगुने बना डाले सिटी फॉरेस्ट

अभी यह हैं प्रावधान

प्रदेश में मौजूदा समय में मप्र अभिवहन (वनोपज) नियम 2000 में बिना टीपी के लकड़ियां ले जाने पर एक वर्ष की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इसी तरह से मप्र काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 में आरा मशीनों का प्रावधान है। अवैध लकड़ियों का चिरान करने एवं हिसाब-किताब नहीं रखने पर एक साल का कारावास और 20 हजार रुपए का जुर्माना, मप्र तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 में बिना अनुमति तेंदूपत्ता का संग्रहण करने एवं उसका विक्रय करने पर 3 माह से एक साल की सजा तथा 50 हजार रुपए के अर्थदंड का और वन उपज (व्यापार विनियमन) 1969 में वनोपज के अवैध व्यापार पर दो साल का कारावास एवं 25 हजार का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

विविधता, जल और मिट्टी के संरक्षण के लिए संपूर्ण प्राकृतिक वातावरण प्रदान करते हैं और प्रदूषण, गर्मी को कम करते हैं। नगर निगम व वर्ग दो के शहरों वाले प्रत्येक शहर में सरकार कम से कम एक सिटी फॉरेस्ट का निर्माण व विकास करना चाहती है। यह पूर्ण स्वस्थ रहने का वातावरण प्रदान करेगा और स्मार्ट, स्वच्छ, हरित, सतत और स्वस्थ शहरों के विकास में भी योगदान देगा।

उधर मप्र का वन महकमा यथा नाम तथा गुण को अधिक चरितार्थ करता है। यही वजह है कि प्रदेश में लगातार वन क्षेत्र कम होता जा रहा है और नए पेड़ों की हालात बद से बदतर बनी हुई है, इसके बाद भी इस महकमे को जंगल बचाने की जगह राजनीतिक चिंताएं अधिक बनी रहती

हैं। इसका उदाहरण हाल ही में तैयार किया गया वह प्रस्ताव है, जिसमें वन क्षेत्र से बाहर किए गए वन कानूनों के उल्लंघन के मामलों में राहत देने की तैयारी की जा रही है। इस प्रस्ताव में जंगलों के बाहर किए जाने वाले वन अपराधों में सजा का प्रावधान समाप्त करने की तैयारी कर ली गई है।

अगर इस प्रस्ताव को सरकार मंजूर कर लेती है तो ऐसे मामलों में सिर्फ जुर्माना देकर छोड़ दिया जाएगा। खास बात यह है कि इसके पीछे विभाग की मंशा किसानों और आदिवासियों पर दर्ज होने वाले वन अपराधों में कारावास से मुक्ति दिलाने की है। राजनीतिक विश्लेषक इसे प्रशासनिक कम बल्कि राजनीति से प्रेरित अधिक मानकर चल रहे हैं। तैयार किए जा रहे प्रस्ताव में चार अधिनियमों में संशोधन करने की तैयारी वन मुख्यालय द्वारा की गई है। खासकर किसान अपनी निजी भूमि पर पौधरोपण कर टीपी (परमिट) लिए बिना ही वृक्षों का विक्रय कर देते हैं और बाद में उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यालय ने इन नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें अब जेल की सजा हटाए जाने के स्थान पर सिर्फ जुर्माना लगाकर किसानों और आदिवासियों को छोड़ा जा सके। वर्तमान में इन नियमों की वजह से सैकड़ों किसानों और आदिवासियों पर वन अपराध दर्ज हैं। विभाग का तर्क है कि राज्य सरकार ने विधि आयोग की सिफारिशों पर आईपीसी एवं सीआरपीसी में बदलाव कर कई धाराओं को समझौता योग्य बनाया है, इसलिए इन अधिनियमों में संशोधन करने की तैयारी है। उधर, इस मामले में वन कानूनों के जानकारों का कहना है कि फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन लोकसभा में बिल पेशकर ही किया जा सकता है। राज्य के साथ केंद्र की सहमति भी जरूरी है।

● श्याम सिंह सिकरवार

मप्र में लगभग एक दशक पहले पोषण आहार घोटाले की तरह ही बुंदेलखंड पैकेज घोटाला हुआ था। बुंदेलखंड पैकेज में भी कई टन पत्थर ढोने वाले वाहनों के नंबर स्कूटी और स्कूटर के निकले थे। ठीक ऐसा ही कुछ पोषण आहार मामले में हुआ है, जिसका खुलासा महालेखाकार की रिपोर्ट ने किया है। दरअसल, केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी, तब वर्ष 2007-08 में बुंदेलखंड के विकास के लिए लगभग साढ़े सात हजार करोड़ का विशेष पैकेज मंजूर किया गया था। इसमें से आधी राशि मप्र के बुंदेलखंड के हिस्से में आई थी।

मप्र वाले बुंदेलखंड के छह जिले अब वर्तमान में इनकी संख्या सात हो गई है। इन जिलों छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, निवाड़ी और दतिया पर लगे सूखा के दाग को मिटाकर बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने की कोशिश शुरू हुई थी। मप्र के बुंदेलखंड के हिस्से में आई राशि लगभग खत्म हो चुकी है, मगर हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। बुंदेलखंड में हुए विकास कार्यों की जांच की गई तो एक बात सामने आई कि पत्थर भी मोटरसाइकिल, स्कूटी और स्कूटर से ढोए गए थे। वहीं, एक मामला तो रोचक था, जब एक ट्रक से पांच टन पत्थर ले जाए जाने का सरकारी दस्तावेजों में जिक्र था, जब हकीकत जानी गई तो वह नंबर स्कूटर का निकला। इतना ही नहीं टैंकर, ट्रैक्टर के नंबरों की जांच हुई तो वह स्कूटर, स्कूटी और मोटर साइकिल के निकले थे। अब पोषण आहार मामले को लेकर महालेखाकार की जो रिपोर्ट सामने आई है, वह बुंदेलखंड पैकेज में हुई गड़बड़ियों की ही तरह है। कुल मिलाकर दोनों ही मामलों में गफलत एक ही तरह से हुई है, जिन वाहनों को ट्रक बताया गया, वे छोटे वाहनों बाइक और ऑटो के नंबर निकले हैं।

बुंदेलखंड पैकेज के तहत मिला 30 करोड़ रुपया लघु सिंचाई महकमे के अफसरों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। यहां हुए टेंडर घोटाले के चलते तालाब एवं चेकडैम बनाने का काम नहीं कराया जा सका। घोटाला पकड़ में आने के बाद पूरा पैसा सरकार को वापस भेज दिया लेकिन नए वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही खत्म हो जाने के बाद यह पैसा दोबारा वापस नहीं लौटा। बुंदेलखंड में पानी की समस्या को देखते हुए बुंदेलखंड पैकेज के तीसरे चरण के तहत झांसी में 30 करोड़ रुपए से काम कराने थे। इनमें 40 चेकडैम एवं 30 तालाबों का गहरीकरण करना था। इसमें कुरैचा, गुढ़ा, नोटा, लठेसरा, खिसनी, सरवां, डगरवाहा, अठौदना, बघौरा, दुरखरू, ककरबई, धनौरा, उरौं, लकारा, बसरिया, धमना, बसरिया, धौरा, वीरा, बिजरवारा, पूछ, शहजहांपुर, तालोड, बिठरी, पच्चरगढ़, फुलखिरिया, काडोर, बरहेटा, रानापुरा, कछीयामऊ, पसौरा, सुजवा एवं लकरा में चेकडैम बनवाए जाने थे जबकि घुराट, सिकार, सिद्धेश्वर, यारा तालाब, भुजरिया, पुतनीया बंधा, अशोक,



स्कूटर से पांच टन पत्थर की ढलाई

बुंदेलखंड पैकेज का 4 करोड़ का तालाब बारिश में फूटा

बुंदेलखंड के विकास के लिए 18 हजार करोड़ रुपए अनेक योजनाओं के तहत राशि आवंटित की गई थी। इसी क्रम में जल संसाधन विभाग द्वारा भी अरबों रुपए के काम बुंदेलखंड पैकेज के तहत कराए गए थे लेकिन इन निर्माण कार्यों में इतना भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की गई थी कि इसकी शिकायत होने पर आज भी यह मामले आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो में लंबित है। इसी योजना के तहत जल संसाधन विभाग द्वारा दमोह जिले के बटियागढ़ तहसील अंतर्गत बटियागढ़-केरवना मार्ग पर ग्राम शेखपुरा में बनाए गए शेखपुरा जलाशय के इस दो दिन की हुई बारिश में फूट जाने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। लेकिन इस बात की जानकारी अधिकारियों ने अपने स्तर पर ही रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत नहीं कराने की जानकारी प्राप्त हुई है। बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा इस शेखपुरा जलाशय का निर्माण वर्ष 2013-14 में 4 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से किया गया था। इसका निर्माण त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन पन्ना द्वारा किया गया था इस जलाशय से जहां 290 हैक्टियर कृषि भूमि की सिंचाई होना थी। वहीं इस तालाब की लंबाई 1228 मीटर है तथा इसमें पानी की कैपेसिटी 0.9 एमपीएम रखी गई है। तालाब में हुई अनियमितता इसी बात को प्रमाणित करती है कि जल संसाधन विभाग के अधिकारी ही बताते हैं कि इस तालाब में इतना सीपेज है कि इसमें जो पानी भरता है, वह आठ दिन के अंदर अपने आप खाली हो जाता है।

बड़ा तालाब, भमौरा, हनुमान मंदिर तालाब, सेमरी, शिव मंदिर तालाब, बुखारा, कुगा तालाब, फुटा तालाब, आदर्श तालाब, पलरा में तालाबों का

गहरीकरण होना था। पूरे काम में 30 करोड़ खर्च होने थे लेकिन काम शुरू होने से पहले ही ठेकेदार एवं अभियंताओं ने ठेके पूल करने का खेल शुरू कर दिया। मामले का भांडा फूटने के बाद तत्कालीन अधिशासी अभियंता को निलंबित करने समेत तीन दर्जन ठेकेदार ब्लैक लिस्ट कर दिए गए। 30 करोड़ रुपए भी सरकार को वापस कर दिए गए लेकिन अब यह पैसा दोबारा नहीं भेजा गया। इस वजह से इन गांवों में कराया जाने वाला कार्य अधर में लटक गया।

पोषण आहार को लेकर महालेखाकार की रिपोर्ट साफ बताती है कि 34 ऐसे नंबर पाए गए हैं जो कागजों में तो ट्रक के दर्ज हैं मगर वे छोटे वाहनों के हैं। पोषण आहार मामले को लेकर महालेखाकार की रिपोर्ट पर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने हैं। कांग्रेस जहां भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरने में लगी है, क्योंकि यह विभाग मुख्यमंत्री के पास ही है। वहीं, भाजपा इसे अंतिम रिपोर्ट मानने को ही तैयार नहीं है, बल्कि कांग्रेस के काल का घोटाला बता रही है। विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि एमपीएजी की रिपोर्ट प्रथम दृष्टया घपले की वास्तविकता दर्शाती है। इसमें जो भ्रष्टाचार दिख रहा है, वह तो बहुत कम है। सूक्ष्मता से जांच होने पर शिवराज सरकार का अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ जाएगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या न्यायिक जांच कराने की मांग की है ताकि प्रदेश की जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वहीं, मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, ये कैंग की अंतिम रिपोर्ट नहीं है। यह प्रारंभिक रिपोर्ट है, जिस पर अभी विभाग को अपना पक्ष प्रस्तुत करना है। कांग्रेस ने पोषण आहार संयंत्रों को महिला स्व-सहायता समूहों से वापस लेने की कार्रवाई की थी। कांग्रेस शासनकाल में निम्न स्तर का पोषण देने पर 35 करोड़ की राशि रोकी गई।

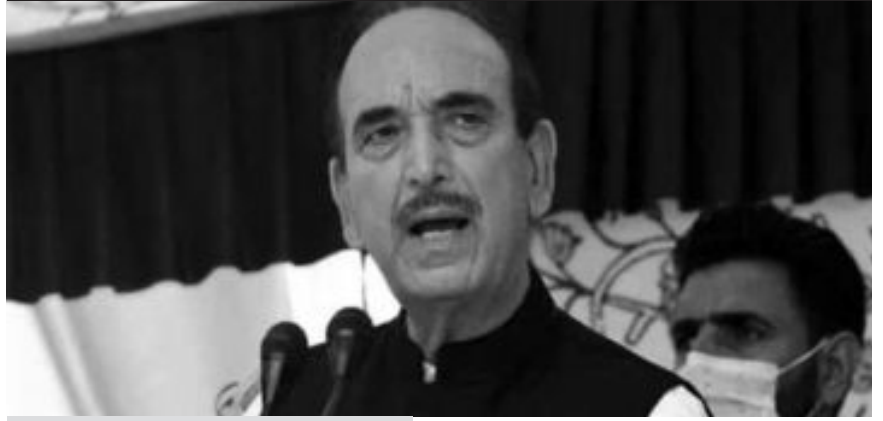
● सिद्धार्थ पांडे

कांग्रेस छोड़ने के साथ ही गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी बनाने की घोषणा भी कर दी है। आजाद नया राजनीतिक दल बनाने जा रहे हैं जिसका दायरा जम्मू-कश्मीर तक ही होगा। हो सकता है आजाद के इस्तीफे की टाइमिंग घाटी में तैयार होते चुनावी माहौल को लेकर तय की गई हो। अब अगर दिल्ली में कांग्रेस नेताओं को लगता है कि गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो एक बार जम्मू-कश्मीर के हिसाब से भी सोच और समझ लेना चाहिए। जम्मू-कश्मीर कांग्रेस पर आजाद के इस्तीफे का प्रभाव अभी से नजर आने लगा है। आजाद के सपोर्ट में अब तक कांग्रेस के आठ नेता इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफा देने वालों में दो कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जीएम सरूरी और आरएस चिब। जम्मू-कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष वी रसूल वानी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि निश्चित तौर पर आजाद के इस्तीफे का पार्टी पर असर पड़ेगा। काफी लोग कांग्रेस छोड़कर उनके साथ जा सकते हैं।

जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रीय दलों का गुपकार गठबंधन भी नेताओं के मतभेद का शिकार हो गया है। गुपकार गठबंधन का हाल भी तकरीबन वैसा ही है जैसे दिल्ली में विपक्षी दल। कांग्रेस का जम्मू-कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल काँग्रेस से पुराना गठबंधन रहा है। एक महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी भी है और ऐसे ही माहौल में भाजपा अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही है। गुलाम नबी आजाद के पार्टी बनाने से कांग्रेस का तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन नेशनल काँग्रेस और पीडीपी पर भी कोई कम असर नहीं पड़ेगा, मानकर चलना होगा कि भाजपा की भी नजर गुलाम नबी आजाद की पार्टी पर ही टिकी होगी। देखा जाए तो गुलाम नबी आजाद ने भी करीब-करीब वैसा ही कांग्रेस छोड़ी है जैसे पंजाब चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ने के बाद पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से पार्टी बनाई थी और उसका भाजपा के साथ चुनावी गठबंधन हुआ था। लेकिन कैप्टन बुरी तरह पिट गए और भाजपा का भी वही हाल रहा।

कांग्रेस छोड़ने वाले ज्यादातर नेता जब भी पार्टी बनाते हैं नाम में कांग्रेस शब्द जरूर रहता है। जैसे शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई है, ममता बनर्जी की पार्टी का नाम भी तृणमूल कांग्रेस ही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पंजाब और कांग्रेस के बीच लोक रख कर पार्टी बना ली। हो सकता है गुलाम नबी आजाद के मन में भी ऐसे ही ख्यालालत चल रहे हों। भले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह और शरद पवार ने अपनी पार्टियों में कांग्रेस नाम जोड़ रखा हो, लेकिन दोनों की राजनीतिक लाइन बिलकुल अलग लगती है। शरद पवार की एनसीपी पर जहां कांग्रेस की विचारधारा का असर है, वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस

कैसी होगी गुलाम की पार्टी



क्या आजाद कश्मीर पर स्टैंड बदलेंगे ?

अलग हो जाने के बाद भी गुलाम नबी आजाद अगर कांग्रेस की विचारधारा के साथ बने रहते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो भाजपा के साथ जाने का कोई इरादा रखते हैं तो काफी मुश्किल हो सकती है। जम्मू-कश्मीर पर गुलाम नबी आजाद का स्टैंड अब तक वही रहा है जो कांग्रेस का है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि कश्मीर पर कांग्रेस ने जो राजनीतिक लाइन तय की है उसके सूत्रधार भी गुलाम नबी आजाद ही रहे होंगे और वो मंजूर भी आसानी से इसीलिए हो गया होगा क्योंकि राहुल गांधी को उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध की झलक पहले ही दिख गई होगी। इसी साल उप चुनाव से पहले जब तमाम कश्मीरी नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी से मिलाने के लिए दिल्ली बुलाया गया था, तो कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद ने ही जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व किया था। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग में जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराए जाने से लेकर फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिए जाने जैसे तमाम मुद्दों पर बात हुई। बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल थे।

राष्ट्रवाद से प्रभावित नजर आती है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि गुलाम नबी आजाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की राह पकड़ते हैं या शरद पवार के रास्ते ही कांग्रेस की विचारधारा के साथ नई पार्टी शुरू करते हैं? कांग्रेस से निकलकर कई पार्टियां देश के अलग-अलग हिस्सों में बनती रही हैं। कई नेताओं ने तो पार्टी बनाने के बाद जब असफल रहे तो वापस लौटकर कांग्रेस में ही विलय भी कर लिया लेकिन शरद पवार की पार्टी एनसीपी और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस जैसी

पार्टियों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। नई राजनीतिक पार्टी तो पंजाब चुनावों के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बनाई थी, लेकिन वो पिट गई। हां, कैप्टन अमरिंदर सिंह ये सोच कर जरूर खुश हुए होंगे कि कांग्रेस छोड़ने के बाद उसकी सरकार तो नहीं ही बनने दिए। पंजाब चुनाव में भी दिल्ली की ही तरह प्रदर्शन करते हुए अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जीत हासिल की और भगवंत मान मुख्यमंत्री बने बैठे हैं।

अगर शरद पवार और कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस से अलग होने की तुलना करें तो दोनों के सामने अलग-अलग परिस्थितियां रहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिन हालात में पार्टी बनाई, शरद पवार की स्थिति तो तब उनसे भी खराब रही। सोनिया गांधी विदेशी मूल पर सवाल उठाने की वजह से शरद पवार को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से जरूर हटाया गया था, लेकिन कांग्रेस उन्होंने खुद छोड़ी थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पार्टी बनाने से पहले ही उनकी राजनीतिक लाइन साफ हो गई थी। कुछ इस तरह की कैप्टन की पार्टी भाजपा से गठबंधन के लिए ही बनी थी। जबकि शरद पवार खुद बता चुके हैं कि कांग्रेस की विचारधारा का उन पर गहरा असर रहा है, इसलिए नई पार्टी बनाने के बावजूद वो अपनी पॉलिटिकल लाइन वो नहीं बदले। गांधी परिवार के व्यवहार के कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह की राजनीति धीरे-धीरे कांग्रेस से ही नहीं बल्कि उसकी विचारधारा से भी दूर होती चली गई और राष्ट्रवाद की तरफ शिफ्ट हो गई थी और ये शायद संघ और भाजपा के बनाए हुए राजनीतिक माहौल का असर भी हो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वही राह चुनी जिसमें भाजपा के साथ चलना संभव हो सके। वैसे सेना की पृष्ठभूमि होने के चलते कैप्टन की राजनीति को पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा ही भाजपा के साथ खड़े देखा गया।

● धर्मद सिंह कथूरिया



भारत जोड़ी यात्रा का औचित्य?

महात्मा गांधी, इंदिरा, आडवाणी हाथी पर इंदिरा, ट्रेन में राजीव ने
की पदयात्राओं ने बदली भारत किया सफर, पैदल ही निकल
की सियासी तस्वीर पड़े राहुल गांधी

आजादी के पहले महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा निकालकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। आज गांधी के देश में राजनीतिक यात्राएं निकालने की परंपरा बन गई है। हर यात्रा का उद्देश्य जनहित ही बताया गया लेकिन दांडी यात्रा को अपवाद मानें तो शेष राजनीतिक यात्राएं देश हित के कितनी करीब रहीं, उससे देश का कितना भला हुआ, यह किसी से छिपा नहीं है। देश में अब तक जितनी भी यात्राएं निकाली गई हैं, उनका मकसद सत्ता रहा है। इसी कड़ी में राहुल गांधी भारत जोड़ी यात्रा पर हैं।

● राजेंद्र आगाल

देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ी यात्रा पर हैं। कांग्रेस ने भारत जोड़ी यात्रा के तीन उद्देश्य बताए हैं— पहला, केंद्र में एनडीए की सरकार के दौरान देश में बढ़ रहे आर्थिक असमानता के खिलाफ, दूसरा— जाति, धर्म, भाषा, नस्ल और रंग के आधार पर बढ़

रहे भेदभाव और अपराध के खिलाफ और तीसरा— केंद्र सरकार द्वारा सत्ता और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ। इनके अलावा महंगाई, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दे हैं, जिनको लेकर यह यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा के उद्देश्य भले ही जनहितैषी हैं लेकिन माना यह जा रहा है कि कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करने और कांग्रेस के जनाधार

को बढ़ाने के लिए राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलने का जोखिम उठाया है। राहुल की इस यात्रा के परिणाम क्या होंगे, यह तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन सत्तापक्ष के माथे पर बल जरूर पड़ गया है। क्योंकि अभी तक जितनी भी राजनीतिक यात्राएं निकाली गई हैं, उनके परिणाम दूरगामी रहे हैं।



भारत ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से लेकर आज तक अनेक राजनीतिक यात्राएं देखी हैं। हर यात्रा का उद्देश्य जनहित ही बताया गया लेकिन दांडी यात्रा को अपवाद मानें तो शेष राजनीतिक यात्राएं देश हित के कितनी करीब रहीं, उससे देश का कितना भला हुआ, यह किसी से छिपा नहीं है। चाहे 1982 की एनटी रामाराव की चैतन्य रथम यात्रा रही हो, या फिर लालकृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से शुरू हुई राम रथयात्रा, वाईएस राजशेखर रेड्डी की 2004 की यात्रा रही हो या फिर उनके पुत्र जगहमोहन रेड्डी की 2017 की राजनीतिक यात्रा अथवा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की यात्रा, सबके अपने राजनीतिक अभीष्ट रहे हैं। इसका लाभ उक्त राजनीतिक दलों को तो मिला लेकिन जनता को तो छलावे के सिवा कुछ भी नहीं मिला। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कोई बड़ा निर्णायक चमत्कार करेगी, इससे देश की आर्थिक विषमता की खाई पट जाएगी, रामराज्य आ जाएगा, इसकी परिकल्पना तो नहीं की जा सकती।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 150 दिन की भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं। वे कन्याकुमारी से कश्मीर तक 12 राज्यों और 2 केंद्रशासित राज्यों का भ्रमण करेंगे। वे अपनी इस यात्रा में भारत और कांग्रेस को जोड़ेंगे। अरसे से एक बात कही जा रही है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। यह वह मणिमाला है जो आगे धागे से जुड़ी हुई है। सवाल यह है कि जब भारत एक है तो उसके टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो टूटा न हो, उसे जोड़ने का क्या औचित्य? अपने भी श्रम की बर्बादी और देश को भी परेशानी में डालने का उद्योग। इससे तो अच्छा यह होता कि राहुल गांधी देश को मजबूत करने की कोशिश करते। विचारणीय है कि क्या भारत टूट गया है। बिखर गया है जो उसे जोड़ने की बात हो रही है या कि वह गुलाम हो गया है जो दूसरा स्वतंत्रता संग्राम लड़ने की बात की जा रही है। पी चिदंबरम का दावा है कि स्वतंत्रता संग्राम की यह दूसरी जंग

हाथी पर चढ़कर सत्ता में लौटी इंदिरा गांधी

वर्ष 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह हार गई थीं और ये कहा जाने लगा था कि अब उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा। लेकिन तभी बिहार में 500 की आबादी वाले गांव में दलितों का नरसंहार हुआ था जिसके बाद इंदिरा गांधी ने बेलछी जाने का फैसला किया और दिल्ली से हवाई जहाज के जरिए सीधे पटना और वहां से कार से बिहार शरीफ पहुंच गईं। तब तक शाम ढल चुकी थी और मौसम बेहद खराब था। नौबत इंदिरा गांधी के वहाँ फंस कर रह जाने की आ गई लेकिन वे रात में ही बेलछी पहुंचने की जिद पर उटी रहीं। स्थानीय कांग्रेसियों ने बहुत समझाया कि आगे रास्ता एकदम कच्चा और पानी से लबालब है लेकिन वे पैदल ही चल पड़ीं। मजबूरन साथी नेताओं को उन्हें जीप में ले जाना पड़ा मगर जीप कीचड़ में फंस गई और फिर उन्हें ट्रैक्टर में बैठाया गया और जब ट्रैक्टर भी फंस गया तो इंदिरा गांधी ने वो किया जिसे देखकर साथी कांग्रेसी भी हैरान रह गए। इंदिरा गांधी अपनी साड़ी थामकर पैदल ही चल दीं तब किसी ने हाथी मंगाकर इंदिरा गांधी और उनकी महिला साथी को हाथी की पीठ पर सवार किया। बिना हौदे के हाथी की पीठ पर उस उबड़-खाबड़ रास्ते में इंदिरा गांधी ने बियाबान अंधेरी रात में जान हथेली पर लेकर पूरे साढ़े तीन घंटे लंबा सफर तय किया। जब वे जब बेलछी पहुंची तो खौफजदा दलितों को ये दिलासा हुआ कि कोई नेता है जिन्हें उनकी फिक्र है और जो सिर्फ दिल्ली में ही बैठकर भाषण नहीं देता बल्कि दिल्ली से चलकर उनके बीच पहुंच जाता है। बेलछी की इस यात्रा के बाद लोग आधी रोट्टी खाकर उन्हें सत्ता वापस लाने की बात करने लगे।

तब तक चलेगी जब तक विभाजनकारी ताकतें परास्त न कर दी जाएं। क्या कांग्रेस को दृढ़ विश्वास है कि वह 150 दिन की समय सीमा में तथाकथित विभाजनकारी ताकतों को परास्त कर देगी। जो कांग्रेस खुद को नहीं जोड़ पा रही है, वह देश जोड़ने चली है। सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने की जिद में भारत का विभाजन हुआ था। मतलब जो परिवार देश के विभाजन का खुद जिम्मेदार है, वह किसी और दल को जिम्मेदार ठहराकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो लेना चाहता है। कांग्रेस अगर आज राजनीतिक पराभव के शीर्ष पर है, उसके अपने लोग उसे छोड़ रहे हैं, तो यह उसकी अपनी रीति-नीति की परिणति है। कांग्रेस देश जोड़ने की बात कर रही है लेकिन वास्तविकता से मुंह मोड़कर। जोड़ तो वहाँ लगता है, जहां टूटन हो। कांग्रेस को अपनी ऊर्जा भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक करने पर खर्च करनी चाहिए। चीन द्वारा हड़पे गई भारतीय जमीन को छुड़ाने के लिए होनी चाहिए। राहुल, सोनिया और उनके समर्थकों को इन देशों में पदयात्राएं करनी चाहिए लेकिन उन्होंने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोध के फेर में गलत मार्ग चुन लिया है।

राजनीतिक अवसर की तलाश

कांग्रेस दरअसल इस यात्रा में अपने लिए राजनीतिक अवसर तलाश रही है। कभी वह तर्क देती है कि संघ और भाजपा तिरंगे का सम्मान नहीं करते। अपने कार्यालयों पर तिरंगा नहीं फहराते और जब भाजपा और संघ ही नहीं, हर घर पर तिरंगा लहराने लगा तो कांग्रेसियों के स्वर बदल गए। अब वे भाजपा और संघ पर तिरंगे पर एकाधिकार का आरोप लगाने लगे। कांग्रेस के नेता बात तो संविधान की करते हैं लेकिन उन्हें अपने ही देश में दो देश दिखते हैं। देश को टुकड़ों में देखने की आदती हो चुकी आंखें उसकी मजबूती देखेंगी भी तो किस तरह। यह



पदयात्राओं ने बदल दी भारत की सियासी तस्वीर

एक यात्रा आज से 39 साल पहले एक नेता ने की थी जिसे इंदिरा गांधी का युवा तुर्क कहा जाता था। उसने भी बिखरती पार्टी और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भारत एकता यात्रा की थी। जिसके बाद वो आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बना। चंद्रशेखर ने 6 जून 1983 को कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक से भारत यात्रा की शुरुआत की। गुलाम भारत में जैसे गांधी ने पदयात्राओं के जरिए भारत की थाह लिए उसी तरह आजाद भारत की समस्याओं को चंद्रशेखर ने अपने पैरों से नापने की कोशिश की थी। जब चंद्रशेखर साल 1983 में तमिलनाडु के एक गांव से गुजर रहे थे तो वहां पगडंडी पर एक बुजुर्ग महिला लालटेन लेकर खड़ी थी। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने पूछा- पानी कब मिलेगा? पीने का पानी गांव में आता नहीं है। चंद्रशेखर ने कहा कि दिल्ली जाकर कहूंगा। जब संसद में वो भाषण देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने 6 चीजें ही बताईं- रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और पानी। चंद्रशेखर ने संसद में कहा कि सरकारें चाहे जो आंकड़े पेश कर लें लेकिन देश की अधिकांश आबादी आज भी इन बुनियादी चीजों से महरूम है। गांव की पगडंडियों और करबों से होते हुए करीब 3700 किलोमीटर की ये पदयात्रा 25 जून 1984 को दिल्ली के राजघाट पर समाप्त हुई। चंद्रशेखर ने भारत यात्रा की शुरुआत 3500 रुपए से की थी। इस दौरान खर्च यात्रा में शामिल लोग उठाते थे। वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद कांग्रेस ने चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन किया और 10 नवंबर 1990 को वो प्रधानमंत्री बने। 1989 में चुनाव में हार मिलने के बाद राजीव गांधी ने साल 1990 में भारत यात्रा की शुरुआत की थी। 1990 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत रेल यात्रा की। उन्होंने ट्रेन के दूसरे दर्जे में बैठकर देशभर का दौरा किया, जिसके बाद उनका सियासी कद काफी बढ़ गया। हालांकि उनकी यात्रा उम्मीदों के मुताबिक परिणाम देने में कारगर साबित नहीं रही। कांग्रेस के अंतर्विरोध की वजह से यात्रा को सफल बनाने में उतनी कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। जितनी उम्मीद की जा रही थी। राजीव आम लोगों के साथ अपनी यात्रा के जरिए जुड़ना चाह रहे थे। लेकिन पार्टी के भीतर गुटबाजी की वजह से भारत यात्रा को सफल बनाने में कामयाब नहीं हो पाए।

देश भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीयता जैसे विविधताओं से युक्त है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को इस देश को जोड़ने और उसे मजबूत करने का अवसर नहीं मिला, खूब मिला। उसे 6 दशक तक खुलकर खेलने का मौका मिला लेकिन उसने कुछ खास लोगों का ही भला किया। सबका साथ तो लिया लेकिन कांग्रेस का हाथ सबके साथ कभी रहा नहीं, वर्ना आज इस तरह की यात्राएं निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कांग्रेस देश को जोड़ना चाहती है। देश जुड़ जाए तो क्या कांग्रेस उससे अलग है या कांग्रेस खुद को देश से जुड़ा नहीं मानती। यह आज नहीं तो कल उसे सुस्पष्ट करना ही होगा। समुद्र बनने के लिए बूंद को आत्मोत्सर्ग करना पड़ता है। अपने अस्तित्व, अपनी पहचान और अहमन्यता को खोना पड़ता है। बूंद अपना अलग वजूद रखे और अपार जलराशि का हिस्सा भी बने, यह संभव नहीं है। जुड़ना दिमाग का नहीं, दिल का विषय है। और विडंबना इस बात की है कि कांग्रेस खासकर गांधी-नेहरू परिवार आजादी

से आज तक दिमाग का ही खेल खेल रहा है। दिल के किसी भी तल पर वह आज तक देश के साथ जुड़ा ही नहीं। राहुल गांधी का मानना है कि नफरत में उन्होंने अपने पिता को खोया है, देश को नहीं खोना चाहते। वे नफरत पर प्यार की विजय चाहते हैं। शायद इसलिए जनता के बीच हैं। सच तो यह है कि वे **भाजपा और संघ से** नफरत की बिना पर ही यह यात्रा निकाल रहे हैं। कीचड़ से कीचड़ धोने की परंपरा नहीं है। कांग्रेस को अगर वाकई देश के लिए कुछ करना है तो उसे अपना नजरिया बदलना होगा। विकास के मामले में भाजपा से बड़ी रेखा खींचनी पड़ेगी। जिन किन्हीं राज्यों में उसकी सरकार बची है, जहां उसके सांसद, विधायक, पार्षद हैं, वहां विकास को अंजाम तक पहुंचना होगा। उसे जनता का विश्वास जीतना होगा जिसे वह बहुत पहले खो चुकी है और इसके लिए उसे आत्मबल तलाशना होगा। अपनी नेतृत्व क्षमता में धार देनी होगी। उसे प्रामाणिक बनाना होगा, अपने रणनीतिकार और सलाहकार बदलने होंगे।

राजनीतिक पदयात्राओं का इतिहास काफी लंबा

भारत में राजनीतिक पदयात्राओं का इतिहास काफी लंबा है। असल में जब भी कोई पार्टी या कोई नेता चुनावी राजनीति में कमजोर होता है तो वो इस तरह की पदयात्राओं पर निकल पड़ता है। क्योंकि ऐसी यात्राओं में नेताओं का जनता से सीधा संवाद होता है और वो ज्यादा से ज्यादा इलाकों में अपनी पहुंच बना पाते हैं। यानी आज जो राहुल गांधी कर रहे हैं, वैसी पदयात्राएं पहले भी हमारे देश में हुई हैं। और इनमें कुछ पदयात्राएं तो उनकी दादी इंदिरा गांधी और उनके पिता राजीव गांधी द्वारा भी की गई थी। इमरजेंसी हटने के बाद जब वर्ष 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह हार गई थीं और ये कहा जाने लगा था कि अब उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा। तब उन्होंने बिहार के बेलछी जाने का फैसला किया था। उस समय बेलछी में भयानक जाति संघर्ष हुआ था, जिसमें 14 लोग मारे गए थे। बेलछी की यात्रा से इंदिरा गांधी को काफी फायदा हुआ और वर्ष 1980 में वो फिर से चुनाव जीतकर सरकार बनाने में सफल हुईं। वर्ष 1990 में भाजपा ने राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बना दिया था और इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए एक रथयात्रा की शुरुआत की थी, जिसका नेतृत्व लालकृष्ण आडवाणी कर रहे थे। ये रथयात्रा गुजरात के सोमनाथ से उग्र के अयोध्या तक प्रस्तावित थी। लेकिन उस समय बिहार में इस रथयात्रा को रोक दिया गया था। और इसके पीछे कानून व्यवस्था को वजह बताया गया था। हालांकि इस रथयात्रा से तब भाजपा को जबरदस्त फायदा हुआ। और उसने 1989 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 1991 में 35 सीटें ज्यादा जीतीं। और 120 सीटों के साथ कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसी तरह की एक यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने भी की थी। ये बात वर्ष 1983 की है, जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और विपक्ष बहुत कमजोर हो गया था। उस समय चंद्रशेखर ने कन्याकुमारी से दिल्ली के राजघाट तक 4 हजार 260 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा की थी। और इस यात्रा के जरिए वो देश के लोगों और उनकी समस्याओं को समझना चाहते थे। ताकि वो राष्ट्रीय राजनीतिक के मंच पर कांग्रेस पार्टी को चुनौती दे सकें। इसके अलावा वर्ष 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी कांग्रेस की संदेश यात्रा निकाली थी। राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 1984 के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीती थीं। और इस यात्रा का मकसद कांग्रेस के संगठन को और मजबूत करना था। इसे इतिहास में राजीव गांधी की रेल यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि तब राजीव गांधी यात्रा के दौरान ट्रेन की सेकंड क्लास की बोगी में यात्रा करते थे।

टी शर्ट-निक्कर की राजनीति

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत को जोड़ने और देश की आत्मा के अन्वेषण के जिस मकसद से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पर निकले हैं, उसके बीच कपड़ों की घटिया राजनीति समूची यात्रा को लक्ष्य से भटकाएगी। हालांकि इसकी शुरुआत भी भाजपा ने ही राहुल की कथित मंहगी टीशर्ट को लेकर की थी, तो जवाबी हमले में कांग्रेस ने भाजपा की मातृ संस्था आरएसएस का गणवेश रही निक्कर पर ही हमला बोल दिया। हालांकि खुद आरएसएस ने अब उसे पहनना छोड़ दिया है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस के मानस में अभी भी उसकी छह साल पुरानी छवि कायम है। कांग्रेस के अधिकृत टिवटर हैंडल से जलती हुई खाकी निक्कर की तस्वीर वायरल करना संघ और भाजपा को भड़काने वाला था, वही हुआ भी। कांग्रेस ने कमेंट किया कि संघ देश को जलाने का काम करता रहा है। इसका ठेठ जवाब यह आया कि कांग्रेसियों के बाप-दादा भी संघ को नहीं रोक पाए तो ये क्या रोकेंगे। भाजपा ने पलटवार में कांग्रेस से सवाल किया कि- क्या वो देश में हिंसा चाहती है?

भारतीय राजनीति में अगर सत्ता में मिले तो हर पार्टी हिंसा का औचित्य भी ढूंढ लेती है। इसलिए यह कहना कि फलां पार्टी ही हिंसा की नसैनी पर सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहती है, अर्द्ध सत्य होगा, लेकिन यहां असल मुद्दा राहुल गांधी की मंहगी टीशर्ट अथवा आरएसएस की निक्कर नहीं है। अगर इसे **फोकस में लाया जाता है** तो इसका संदेश यही जाएगा कि यात्रा अपने मूल उद्देश्य से भटक रही है। इसमें दो राय नहीं कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले देश में लड़खड़ा रही कांग्रेस को फिर से खड़ा करना, पार्टी में राहुल गांधी की सत्ता को पुनर्स्थापित करना और संभव हुआ तो अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल के चेहरे को प्रोजेक्ट करना इस चार माह की यात्रा का राजनीतिक उद्देश्य है। इसमें भावना भी है और पार्टी की भाग्य रेखा को बांचना भी है। इस अर्थ में यह यात्रा अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कितनी सफल होती है, यह यात्रा को मिलने वाले जनसमर्थन और स्वयं राहुल के एटीट्यूड पर निर्भर करता है। यह अपने आप में विरोधाभासी है कि वो एक तरफ पैदल यात्रा भी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हें क्या करना है या भविष्य में वो क्या करने वाले हैं, इसके पते खोलने में भी झिझक रहे हैं। हो सकता है यह उनकी रणनीति का हिस्सा हो या फिर उनके अस्थिर मानस की एक और दुविधा हो, लेकिन जब तक वो इस महत्वाकांक्षी यात्रा में साफ-साफ अपने इरादों को, संकल्प को व्यक्त नहीं करेंगे, देश का जनमानस इस यात्रा को बहुत संजीदगी से शायद ही लेगा।



अपने प्रदेश में जब नेता पदयात्रा पर निकले

कांग्रेस नेता वार्डएस राजशेखर रेड्डी ने अप्रैल, 2003 में आंध्र प्रदेश में 1400 किलोमीटर की यात्रा निकाली थी। इस यात्रा का व्यापक असर हुआ और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा एक धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा थी, हालांकि अपनी 3300 किलोमीटर लंबी पदयात्रा के दौरान उन्होंने मप्र की 230 विधानसभा सीटों में से 100 से अधिक सीटों का दौरा किया। इस दौरान सिंह जनता से भी मिले और उनकी समस्याएं भी सुनी। इस यात्रा के बाद 2018 के आखिर में हुए मप्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 15 साल बाद जीत मिली। भाजपा ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। इसमें 39 केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया और उन्होंने 22 राज्यों के 212 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा किया और केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में लोगों को बताया। आंध्रप्रदेश में वार्डएसआर कांग्रेस पार्टी के जगनमोहन रेड्डी ने अपने पिता की तरह ही राज्यव्यापी पदयात्रा निकाली और इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की शानदार विजय हुई। इसके अलावा वर्ष 2007 में जब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी, तब नंदीग्राम की घटना के बाद ममता बनर्जी ने सिंगूर से नंदीग्राम तक पैदल यात्रा की थी। और इसके चार वर्ष बाद 2011 में वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई थीं। इसी तरह वर्ष 2013 में चंद्रबाबू नायडू ने भी विपक्ष में होते हुए 1700 किलोमीटर की यात्रा की थी और अगले साल 2014 में वे आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। फिर आंध्र प्रदेश में 2017 में ही जगनमोहन रेड्डी ने भी 3400 किलोमीटर की यात्रा की थी और 2019 में वो मुख्यमंत्री बन गए थे। यानी आप देखेंगे तो ये राजनीतिक यात्राएं अक्सर वो पार्टियां और नेता निकालते हैं, जो सत्ता से बाहर होते हैं, और वो इन यात्राओं के जरिए वोटों की रेलगाड़ी में सवार होना चाहते हैं।

देश सच में जुड़ पाएगा ?

राहुल गांधी की यात्रा के नक्शे को देखें तो जिन 12 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों से यह गुजरने वाली है, उनमें से 5 राज्य भाजपा शासित हैं और एक केंद्रशासित और एक पूर्ण राज्य में आम आदमी पार्टी का शासन है। कांग्रेस शासित राज्य केवल राजस्थान है, जहां से होकर यह यात्रा निकलेगी। इस हिसाब से यह यात्रा दक्षिण से उत्तर को तो जोड़ेगी। लेकिन पश्चिम से पूर्व को जोड़ने का इसमें प्रावधान नहीं है (शायद आगे हो)। बेशक सुदीर्घ यात्राएं भारत को समझने में हर किसी की मददगार रही हैं। राजनेताओं से लेकर संतों तक और कलाकारों से लेकर यायावरों तक। महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करने के पहले समूचे भारत की यात्रा की। स्वामी विवेकानंद ने की। हाल के वर्षों में चंद्रशेखर और बाबा आमटे ने भी कीं। इस अर्थ में राहुल गांधी को ऐसी यात्रा पर बहुत पहले ही निकल जाना था। पिछला लोकसभा चुनाव हारने के बाद उनके लिए जनता से जुड़ने और देश की आत्मा से साक्षात्कार का बेहतरीन मौका था। तब उसके राजनीतिक उद्देश्यों पर सवाल भी कम उठते। लेकिन उस वक्त उन्होंने केवल पद से इस्तीफा देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली, जबकि राजनीतिक रण में हार-जीत चलती रहती है, लेकिन अर्जुन की तरह कुरूक्षेत्र में आपको लड़ते ही रहना पड़ता है। सेनापति की **संघर्षशीलता सैनिकों** में भी जोश भरती है, लेकिन राहुल गांधी तब भी इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं थे कि उन्हें क्या और कैसे करना है और अभी भी इस बात का कोई साफ संकेत वो नहीं दे रहे कि यह यात्रा अंततः उनकी निजी छवि को उजली करने के लिए है या फिर दिशाहीनता और मुद्दों के जंजाल में भटकती कांग्रेस के लिए दृढ़ संकल्प मशाल की तरह है।

हिंदी भाषी राज्यों में क्या होगा असर ?

राहुल गांधी की 12 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों में साढ़े तीन हजार किमी की यह यात्रा फिलहाल दक्षिणी राज्यों से गुजरी है, जिनमें से केरल में ही कांग्रेस बेहतर स्थिति में है। लग रहा

भारत जोड़ो यात्रा का 'भारत' कौन सा है ?

अभी तक कांग्रेस ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि भारत जोड़ो यात्रा का 'भारत' नया अर्थात् निगम-भारत है, या संविधान-सम्मत वास्तविक भारत है। जो निगम-भारत के निर्माण में दिन-रात मरता-खपता और उसके हाशियों पर जीवन बसर करता है। कहने की जरूरत नहीं कि यह निगम-भारत को जोड़ने की यात्रा है। यह भी कहने की जरूरत नहीं कि निगम-भारत पहले से ही लोहा-लाट मजबूती के साथ आपस में एकजुट है। उसके निर्माता और संरक्षकों ने उसे किसी भी आक्रमण के खिलाफ अभेद्य बनाया हुआ है। 13 सालों से सत्ता से बाहर रहने वाली कांग्रेस निगम-भारत को अपने पक्ष में एकजुट करना चाहती है। एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उसकी यह आकांक्षा और प्रयास स्वाभाविक हैं। इस नाते और भी ज्यादा कि वह नब्बे के दशक में निगम-भारत की बुनियाद डालने वाली पार्टी है। नागरिक समाज के सदस्य निगम-भारत के नागरिक समाज के सदस्य हैं। विश्व समाज मंच (वर्ल्ड सोशल फोरम) से लेकर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, आम आदमी पार्टी तक वे बार-बार खुद ही यह सिद्ध कर चुके हैं। आज वे फिर से कांग्रेस के साथ एकजुट हो रहे हैं। एक कांग्रेस को पीछे धकेलकर भाजपा-आरएसएस के साथ सत्ता की लड़ाई में अरविंद केजरीवाल आगे आने की कोशिश करेंगे, तो वे उनके साथ एकजुट होंगे। कोई क्षेत्रीय क्षत्रप अपनी राजनीतिक सत्ता सुरक्षित करने की नीयत से भाजपा-आरएसएस का रणनीतिक विरोध करेगा तो वे उसके साथ एकजुट होंगे। इस तरह निगम-भारत के लिए ऐसे लोगों की सेवाएं हमेशा उपलब्ध रहेंगी। ये सभी प्रचन्न नवउदारवादी होते हैं और वर्तमान सांप्रदायिक फासीवाद नवउदारवाद का उपोत्पाद (बाइ-प्रोडक्ट) है। दरअसल, इन लोगों ने अहद किया हुआ है कि देश के लोगों को देश के राजनीतिक यथार्थ से सीधे सामना नहीं करने देना है। इसीलिए वास्तविक भारत पर उनकी दावेदारी में कभी दम नहीं रहा। जब किसी देश, समाज के नागरिक समाज की भ्रामक भूमिका के चलते राजनीति से विचारधारा और प्रतिबद्धता का दान-पानी उठ जाता है, तो वहां नित्य-प्रति इसी तरह के विद्रूप प्रस्तुत होते हैं!



है कि लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी नेता देश जोड़ने की बात नहीं कर रहा है। लेकिन इस यात्रा का असल प्रभाव उन हिंदी भाषी राज्यों में देखा जाएगा, जहां कांग्रेस अभी भी दूसरी बड़ी सियासी ताकत है। उधर भाजपा भी इस यात्रा को बहुत बारीकी से देख और बूझ रही है कि क्या राहुल देश की राजनीतिक धारा को बदल पाते हैं या नहीं। क्योंकि उनके अलावा बाकी विपक्ष देश के बजाय दलों को जोड़ने की बात कर रहा है। हालांकि समूचे विपक्ष का एका बहुत दूर की कौड़ी है, जिसे विश्वसनीयता की कागजी आंच पर पकाने की कोशिश हो रही है। अगले लोकसभा चुनाव के पहले कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों के नतीजे भी सत्तापक्ष और विपक्ष के राजनीतिक हौसलों पर असर डालेंगे। यह सही है कि राहुल बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई जैसे शाश्वत मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन इन्हें चुनावी मुद्दों में बदलना टेढ़ी खीर है। अगर वो ऐसा कर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। भारतीय राजनीति में जनता के दैनंदिन जीवन से जुड़े मुद्दे कभी चुनाव जिताऊ मुद्दों में तब्दील नहीं हो पाते। केवल एक बार 1971 में ऐसा हुआ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ' का लुभावना नारा देकर भारी बहुमत से लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन उसके पीछे और भी दूसरे बहुत से कारण थे।

दुर्भाग्य से यह हकीकत है कि जनता जिस पीड़ा को भोग रही होती है, वह वोट में बहुत कम अनूदित होता है। इसका कारण शायद यह है कि बहुसंख्य भारतीय वोटर वोट देते समय कई दूसरे तत्वों और आग्रहों को भी ध्यान में रखता है या बहकता है। भाजपा और आरएसएस यह बात बखूबी जानते हैं। लिहाजा अगले लोकसभा चुनाव का कोर मुद्दा क्या होगा और उसे कौन तय करेगा, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राहुल और कांग्रेस के पास ऐसा कोई गेम चेंजर मुद्दा दिखाई नहीं पड़ रहा। भाग्यवश ऐसा कोई मुद्दा हाथ लग जाए तो बात दूसरी है। देश के बहुसंख्यकों का बड़ा वर्ग मोदी और उनकी कार्यशैली का समर्थक है। इस स्थिति में जल्द कोई बदलाव होगा, ऐसा नहीं लगता। 'भारत जोड़ने' का राहुल गांधी का राजनीतिक लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है, जब बहुसंख्यक वोट मोदी मोह से टूटे और कांग्रेस के पास आए। केवल सदृच्छ राजनीतिक पथ पर बैटरी का काम तो कर सकती है, इंजन नहीं बन सकती। राहुल के पास उम्र का मार्जिन है, लेकिन वो देश का नेतृत्व पूरी प्रामाणिकता, संजीदगी और निरंतरता के साथ करना चाहते हैं, यह स्थापित हुए बगैर यह यात्रा अपने अभीष्ट को शायद ही प्राप्त कर पाए। इस यात्रा को अपने लक्ष्य से भटकाने की खुद कांग्रेस को जरूरत नहीं है। लोगों को जो और जितना समझना है, वो समझ रहे हैं।

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दे

यात्रा के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों (डर, कटटरता और पक्षपात की राजनीति, आजीविका नष्ट करने वाली अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, बढ़ती असमानता) में कुछ भी नया नहीं है। ये मुद्दे कांग्रेस और कुछ अन्य भाजपा-विरोधी पार्टियों के वक्तव्यों और प्रेसवार्ताओं में, धर्मनिरपेक्ष खेमे के सोशल मीडिया पर, कुछ लघु पत्र-पत्रिकाओं में निरंतर बने रहते हैं। बिना किसी सुझाव अथवा प्रस्ताव के यात्रा में शामिल होने वाले नागरिक समाज के सदस्य कह सकते हैं कि यात्रा के जरिए इन मुद्दों का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन ऐसा कहना जनता में और ज्यादा भ्रम की सृष्टि करना होगा। 150 दिन बीतते देर नहीं लगेगी। भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद निगम-भारत कारपोरेट-कम्प्यूनल गटजोड़ से नियंत्रित और संचालित होता रहेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि यह पदयात्रा उनके लिए तपस्या है और वे लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। तपस्या एक अर्थ-गर्भित शब्द है। राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए अपनी पार्टी के पक्ष में जनता को लामबंद करने की कवायद का महत्व बताने के लिए अन्य कई शब्द हो सकते हैं। इस कवायद के लिए तपस्या शब्द का प्रयोग करने से उसका अर्थ-संकोच होता है।

केंद्र की भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इससे पहले महंगाई और ईडी समेत अन्य जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ भी कांग्रेस नेताओं ने देशभर में सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के प्रदर्शन, रैली और यात्रा में उसके दो मुख्यमंत्रियों की भूमिका काफी अहम होती है - राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल।

राजस्थान और छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और दोनों ही मुख्यमंत्री कांग्रेस आलाकमान या यूँ कहें कि गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं। भाजपा, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के जिस सपने को साकार करना चाहती है उसके लिए इन दोनों राज्यों में कांग्रेस को हराना बहुत जरूरी है। इसलिए भाजपा के कुशल रणनीतिकार एवं गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इन राज्यों में मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इन दोनों राज्यों में बैठक कर माहौल बनाने और अपने कैंडिड को सक्रिय करने का पूरा प्रयास कर रहा है।

राजस्थान में अमित शाह ने भाजपा के अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात् ओबीसी मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करने के साथ-साथ जोधपुर में बूथ अध्यक्ष संकल्प महा सम्मेलन की बैठक को भी संबोधित करते हुए राहुल गांधी, उनकी भारत जोड़ो यात्रा और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कन्हैया लाल की हत्या, दलितों की हत्या, अवैध खनन को रोकने के लिए महंत विजय दास द्वारा आत्मदाह के लिए मजबूर होने, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 56 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने और प्रदेश की लगातार खराब होती जा रही कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा।

गहलोत सरकार पर किसानों और बेरोजगारों के साथ किए गए वायदे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए शाह ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हिंदुओं के त्योहारों को मनाने पर प्रतिबंध लगाने का काम कर रही है और हिंदू संस्कृति का अपमान करने वाली ऐसी सरकार को हम सहन नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस आलाकमान के करीबी मुख्यमंत्री पर पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कम नहीं करने और तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए अमित शाह जिस अंदाज में अशोक गहलोत पर हमला बोल रहे थे उससे यह साफ-साफ नजर आ रहा था कि राजस्थान का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए कितना अहम होने जा रहा है।

दरअसल, राजस्थान के चुनावी परिदृश्य को



संघ ने संभाली कमान

चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने बदला प्रभारी

छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में भाजपा लगातार राज्य में बदलाव की ओर बढ़ रही है। यही वजह है कि पहले प्रदेश अध्यक्ष, फिर नेता प्रतिपक्ष और अब पार्टी प्रभारी को राष्ट्रीय नेतृत्व ने बदल दिया है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी को बदलकर ओम माथुर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। माथुर, पहले संघ के राष्ट्रीय प्रचारक थे। यही नहीं राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता ओम माथुर को गुजरात, उप्र और महाराष्ट्र का प्रभारी भी बनाया जा चुका है। माना जा रहा कि ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाना संघ की रणनीति का भी एक हिस्सा हो सकता है। ये बदलाव इसलिए भी देखा जा रहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार भाजपा की परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठते रहे हैं। जिसको लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व काफी नाराज चल रहा था। ऐसा कहा जा रहा कि छत्तीसगढ़ में भी भाजपा गुटीय प्रबंधन का शिकार हो रही। ऐसे में 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी और नेताओं की एकजुटता को बनाने के लिए भाजपा ने कई बदलाव किए हैं। साथ ही दिग्गज नेताओं का भी छत्तीसगढ़ दौरा तेज हो गया है।

देखते हुए राज्य के ओबीसी मतदाताओं को साधना काफी अहम हो जाता है। इसके साथ ही गुटों में बटे पार्टी के सभी नेताओं को एक साथ लाकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जीत के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है और इन तीनों ही मोर्चों पर शाह की इस बार की यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह स्वयं लगातार राजस्थान के दौरे पर जा रहे हैं और

ओबीसी मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले भाजपा और संघ दोनों ही संगठन प्रदेश में कई अहम बैठक कर चुके हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान राजस्थान में भाजपा और संघ की सक्रियता की बात करें तो इसी वर्ष मई में भाजपा ने अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जयपुर में की थी वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक जुलाई में राजस्थान के झुंझुनू में हुई थी।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को चुनाव हराने के लिए भाजपा पुरजोर कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है पिछले कई दिनों से संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ-साथ संघ के कई नेता राज्य में विचार विमर्श कर रहे हैं तो वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी छत्तीसगढ़ पहुंचकर भव्य रोड शो किया और उसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस आलाकमान पर जमकर निशाना साधते हुए यह आरोप लगाया कि बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस पार्टी का एटीएम बना दिया है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल, भाई-बहन की पार्टी को चला रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के रायपुर में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण-अखिल भारतीय समन्वय बैठक की है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में हुई इस अति महत्वपूर्ण बैठक में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत संघ से जुड़े 36 संगठनों के अध्यक्ष या संगठन महासचिव अपने-अपने संगठन के कामकाज और उपलब्धियों की रिपोर्ट दी। तीन दिनों तक चली इस बैठक में भाजपा समेत संघ से जुड़े सभी संगठनों ने भविष्य की रणनीति भी तय की। छत्तीसगढ़ में अगले वर्ष यानी 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और भाजपा कांग्रेस को हराने का दावा कर रही है।

● रायपुर से टीपी सिंह

मिशन 2024 के लिए विपक्षी एकता की लगातार कवायद हो रही है। पहले ममता बनर्जी, फिर अरविंद केजरीवाल, उसके बाद केसीआर और अब नीतीश कुमार इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन यह प्रयास अभी तक नेताओं की मेल-मुलाकात से आगे नहीं बढ़ पाया है। दरअसल, कोई भी पार्टी इस बात पर समझौता करने को तैयार नहीं है कि अमुक नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यानी हर पार्टी का प्रमुख नेता अपने आपको प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करना चाह रहा है। इस कारण विपक्षी एकता की खिचड़ी पक नहीं पा रही है।



एकता की न पकने वाली खिचड़ी...

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा भाजपा से नाता तोड़कर राजद, कांग्रेस और अन्य दलों के साथ सरकार बनाने के बाद तीन मुद्दे राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आ गए हैं। एक, क्या नीतीश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी होंगे? दूसरा, भाजपा को हराने के लिए क्या विपक्षी दल राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन बनाने में सफल हो सकेगा? तीसरा, क्या नरेंद्र मोदी 2024 में अपनी सत्ता बचा पाएंगे? कई विश्लेषकों ने अपने अद्भुत ज्ञान-कौशल और चुनावी आंकड़ों द्वारा जनता से पूछे बिना ही मोदी और भाजपा के विरुद्ध अपना सांकेतिक निर्णय भी सुना दिया है। अभी लोकसभा चुनाव दो वर्ष दूर हैं। ऐसे में पार्टियों द्वारा तैयारी करना उचित है। फिर भी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम के आधार पर भाजपा को खारिज करने का बौद्धिक प्रलाप समझ से परे है। राष्ट्रीय पार्टियां लोकसभा में बहुमत के लिए विभिन्न राज्यों में अपने प्रदर्शन पर निर्भर होती हैं। चूंकि बिहार से लोकसभा के 40 सदस्य चुनकर आते हैं तो इस लिहाज से वह एक बड़ा राज्य है। इसीलिए भाजपा को अगर सत्ता में वापसी करनी है तो बिहार में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। कुछ विश्लेषक मान रहे हैं कि जदयू और राजद के साथ आने से भाजपा को भारी नुकसान होगा। ऐसे लोग असल में उग्र का

उदाहरण भूल जा रहे हैं। वर्ष 2019 के आम चुनाव में सपा और बसपा ने भाजपा के विरुद्ध गठबंधन किया था। मीडिया के बड़े हिस्से और विश्लेषकों ने भाजपा को भारी नुकसान की भविष्यवाणी की थी, लेकिन परिणाम क्या हुआ? भाजपा-अपना दल गठबंधन ने 80 में 64 सीटें जीतीं। वहीं बसपा 10 और सपा पांच सीटों पर सिमट गई।

बिहार की जनता को राष्ट्रीय चुनाव और विधानसभा चुनाव का फर्क करना आता है। 2019 के लोकसभा चुनावों में बिहार की जनता ने मोदी के नेतृत्व में भरोसा जताया था। तब भाजपा-जदयू-लोजपा गठबंधन ने राज्य की 40

में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब मतदान जातीय गणित से आगे निकल चुका है। जनता कानून-व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और लोक-कल्याण को ध्यान में रखकर वर्गीय हितों के अनुसार मतदान कर रही है। जातीय आधार पर अस्मिता की राजनीति करने वाले दल और नेता अभी इस परिवर्तन को भांप ही नहीं पाए हैं। इसी कारण अपनी हार के लिए ईवीएम, चुनाव आयोग या सत्तारूढ़ दल को दोष देते हैं।

वहीं भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से लगातार जुड़ाव बढ़ा रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम द्वारा हर महीने जनता से संवाद करते हैं। लोकतंत्र में यह एक

राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं...

राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन विपक्षी एकता न पकने वाली खिचड़ी इसलिए है, क्योंकि आज न तो कोई जयप्रकाश नारायण है, न हरिकिशन सिंह सुरजीत और न ही वीपी सिंह। अब जो भी विपक्षी नेता विपक्ष को एकजुट करना चाह रहा है, वह प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं। यह सपना देखने का अधिकार हर नेता को है, लेकिन जो दल मोदी सरकार को हटाने के लिए सक्रिय हैं, वे यह नहीं बता पा रहे कि वह इस सरकार को हटाने और केंद्र की सत्ता पाने के बाद करेंगे क्या? इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि देश में महंगाई, बेरोजगारी जैसी तमाम समस्याएं हैं, लेकिन कोई विपक्षी दल यह बताने की स्थिति में नहीं कि वह इन समस्याओं से कैसे पार पाएगा? वादे करना अलग बात है और उन्हें पूरा करना अलग बात। इसे इससे समझा जा सकता है कि दस लाख सरकारी नौकरियां देने के अपने चुनावी वादे पर तेजस्वी यादव अगर-मगर कर रहे हैं। स्पष्ट है कि बिना वैकल्पिक एजेंडे, देश का भरोसा जीतने वाले समर्थ चेहरे और टोस विमर्श के विपक्षी एकता संभव नहीं।

नया प्रयोग है। विकास और लोक-कल्याण की समावेशी योजनाओं का धन टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में मिल रहा है, जो उनके लिए अकल्पनीय था। इसमें बिचौलिये बाहर हो गए हैं। मोदी ने जिस तरह गरीबों को वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, किसानों को फसल बीमा सुरक्षा, महिला सुरक्षा और दैनिक जीवन में जीवन सुरक्षा दी है, वह वर्ग राजनीति का अद्भुत उदाहरण है।

इसमें कोई शक नहीं कि आज राष्ट्रीय राजनीति मोदी केंद्रित हो गई है। अधिकतर राजनीतिक दल और नेता अभी भी परंपरागत अस्मितावादी, जातिवादी और अवसरवादी चश्मे से चुनावों को देखते हैं, लेकिन मोदी ने राष्ट्रीय राजनीति का संपूर्ण व्याकरण ही बदल दिया है। उन्होंने अस्मितावादी राजनीति की जगह गरीबों के सपनों को साकार करने वाली जनाकांक्षावादी राजनीति को बढ़ावा दिया है।

जातिवादी-राजनीति के मकड़जाल से परे जनता को वर्ग-राजनीति से जोड़ा है और बहिर्वेशी-राजनीति को तिलांजलि देकर समावेशी-राजनीति को तरजीह दी है।

जो विश्लेषक विगत लोकसभा के राज्यवार आंकड़ों के आधार पर बिहार, झारखंड और बंगाल को आधार बनाकर अभी से मोदी के विरुद्ध चुनाव परिणाम के संकेत देने लगे हैं, वे भी अपने बचाव के लिए चतुराई से कुछ गुंजाइश बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जनता सशक्त सरकार चाहती है जो साफ-सुथरी, पारदर्शी, प्रतिबद्ध और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान रखती हो। मोदी सरकार ने ऐसी छवि अर्जित की है जिसका गौरवगान करते पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी नहीं थकते। इसीलिए मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ने तीन लोगों मोदी, पोप और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस की एक समिति का प्रस्ताव दिया है, जो वैश्विक संघर्षों को रोकने के लिए प्रयास करे।

आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी और भाजपा जीतें या हारें, लेकिन उसकी थाह तभी मिलेगी जब हम जमीनी स्तर पर अध्ययन करेंगे। हमारे शोध केंद्र सीएसएसपी ने 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के 45 प्रतिशत वोट (272 सीटें) और सपा के लिए 35 प्रतिशत वोट का आंकलन किया था, जो सही निकला। इसी प्रकार 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रदेश

में भाजपा-अपना दल गठबंधन के लिए 60 से 65 सीटों का आंकलन किया था और उन्हें 64 सीटें मिलीं। ये अध्ययन मतदान के बाद किए गए थे जो मतदाता के मतदान-व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे अध्ययन गलत भी हो सकते हैं, लेकिन यदि अध्ययन में सच्चाई एवं पारदर्शिता रखी जाए तो संकेत स्पष्ट मिल जाते हैं। ऐसे में चुनाव से दो वर्ष पहले के पूर्वानुमान विश्लेषकों की इच्छा व्यक्त करते हैं, जनता की नहीं।



मोदी को सत्ता से हटाने की चाह

एक वक्त था जब गुजरात माडल के जवाब में बिहार माडल का बखान होता था, लेकिन अब तो खुद नीतीश कुमार भी अपने गवर्नेस माडल के बारे में बात नहीं करते। क्यों नहीं करते, यह वही जानें, लेकिन यह सबको और विशेष रूप से राज्य की जनता को भी पता है कि बिहार विकास के पैमानों पर अन्य राज्यों से पीछे है। जद-यू और राजद के नेता कुछ भी कहें, बिहार के महागठबंधन में शामिल कांग्रेस भी नीतीश को पीएम पद लायक कहने से बच रही है। कांग्रेस से ऐसी आशा भी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि यदि नीतीश पीएम पद के प्रत्याशी बनेंगे तो फिर राहुल गांधी क्या करेंगे? गांधी परिवार से सबसे केंद्र की सत्ता छिनी है, तबसे वह यह माने बैठा है कि इस देश पर शासन करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि किसी मजबूरी और विशेष रूप से नरेन्द्र मोदी को सत्ता से हटाने की चाह में कांग्रेस नीतीश के पीछे खड़ी हो जाती है, तो भी इसकी गारंटी नहीं कि ममता बनर्जी, के. चंद्रशेखर राव, शरद पवार आदि उन्हें पीएम बनाने के लिए एकजुट हो जाएं। यदि ये नेता भी किसी विवशता में नीतीश को समर्थन देने के लिए तैयार हो जाएं तो भला अरविंद केजरीवाल ऐसा क्यों करेंगे?

राष्ट्रीय नेतृत्व चयन में सबसे महत्वपूर्ण घटक तो मतदाता होता है, लेकिन अधिकतर विश्लेषक राजनीतिक दलों की उठापटक को ही तरजीह दे रहे हैं। क्या वे जनता को मूर्ख समझते हैं? विपक्ष के पास न भाजपा का कोई राष्ट्रीय विकल्प है, न समरूप विचारधारा। न कोई सर्वमान्य नेतृत्व, जहां राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, मायावती और अखिलेश यादव आदि अनेक दावेदार हों, वहां जनता के मन में सवाल उठता है कि

लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन तो होना चाहिए, लेकिन क्या विपक्ष के पास मोदी और भाजपा का कोई विकल्प है भी? फिर चुनाव जीतकर आप करेंगे क्या? या केवल मोदी को हटाना ही एक मुद्दा है? मोदी का जनता से जुड़ाव, साफ-सुथरी छवि, देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता, विकास योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, बेहतर चुनाव-प्रचार एवं चुनाव-प्रबंधन आदि अनेक ऐसे घटक हैं, जो विश्लेषकों

की इच्छाओं पर पानी फेर सकते हैं।

बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने के साथ ही विपक्षी एकता के अभियान को फिर से धार देने के प्रयास हो रहे हैं। जदयू नेता तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का पात्र बताने में लगे ही हुए हैं, राजद नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी उनकी पैरवी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव यही चाहेंगे कि नीतीश कुमार जितनी जल्दी संभव हो, प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हों और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उन्हें बैठने का अवसर मिले।

यह अवसर उन्हें मिलना भी चाहिए, क्योंकि राजद बिहार का सबसे बड़ा दल है। जदयू नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए गुणवान बताने के साथ यह भी कहने में लगे हुए हैं कि वह भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम करेंगे। कठिनाई यह है कि जदयू और राजद के अलावा अन्य कोई प्रमुख दल न तो इस पर उत्साह दिखा रहा है और न ही यह कहा रहा है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को चुनौती देने में सबसे समर्थ नेता होंगे। नीतीश बिहार के बड़े नेता अवश्य हैं, लेकिन अब उनकी छवि सुशासन बाबू की नहीं रही। जब तक जदयू का राजद में विलय नहीं हो जाता, तब तक यकीन के साथ यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह फिर से पालाबदल नहीं करेंगे।

● विपिन कंधारी

शि वसेना में उद्भव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान आने वाला है। महाराष्ट्र कांग्रेस से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके अशोक चव्हाण और उपमुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस के बीच एक खास ठिकाने पर गोपनीय रूप से मुलाकात हुई है। यह मुलाकात 15 से 20 मिनट के करीब हुई है। ना सिर्फ अशोक चव्हाण बल्कि कांग्रेस के कुछ और विधायक भी भाजपा के संपर्क में बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अक्टूबर में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में वे शिंदे सरकार में शामिल हो सकते हैं और इन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है। अभी तक फडणवीस की ओर से मुलाकात के बारे में अधिकृत रूप से कुछ नहीं बताया गया है लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि 1 सितंबर की शाम गणेश उत्सव के बहाने दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक मामलों को लेकर चर्चाएं हुई हैं। यह मुलाकात भाजपा समन्वयक आशीष कुलकर्णी के घर हुई।

इस बीच अशोक चव्हाण की इस मुलाकात को लेकर सफाई भी सामने आ गई है। उन्होंने मुलाकात से तो इनकार नहीं किया है लेकिन यह कहा है कि उनके और फडणवीस के बीच कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। बता दें कि कुछ दिनों पहले महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री रहे कांग्रेसी नेता असलम शेख भी भाजपा नेता मोहित कंबोज के साथ देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके सागर बंगले गए थे। लेकिन इसके बाद यह बात निकलकर आई कि भाजपा नेता किरीट सोमैया ने उन पर मालाड के मालवाणी इलाके में मड में अवैध फिल्म स्टूडियो बनाने का आरोप लगाया है, वे इस संबंध में सफाई देने गए थे। पिछले कई ऐसे मौके आए हैं जिनसे यह साफ होता है कि कांग्रेस के कुछ नेता भाजपा और शिंदे गुट को सपोर्ट करते रहे हैं। राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों में क्रॉस वोटिंग की बातें सामने आईं। इस बारे में 6 कांग्रेसी नेताओं द्वारा पार्टी लाइन से हटकर वोट किया गया, जिनसे भाजपा उम्मीदवार की जीत हुई। इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग उठाई गई। लेकिन कांग्रेस ने शिवसेना में हुई शिंदे गुट की बगावत को देखते हुए अपनी पार्टी में संभावित विस्फोट की आशंकाओं के डर से इसे नजरअंदाज किया। फ्लोर टेस्ट के दौरान भी अशोक चव्हाण सदन में लेट पहुंचे और वोटिंग में भाग नहीं ले सके। बहुमत जीतने के बाद फडणवीस ने उन्हें गैरहाजिर रहने के लिए धन्यवाद भी दिया था।

दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात पर महाराष्ट्र भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा,



महाराष्ट्र में राजनीतिक तूफान

राजनीति में अचानक प्रासंगिक हो गए हैं राज ठाकरे

शिवसेना में ऐतिहासिक फूट के बाद राजनीतिक तौर पर कमजोर हो चुके उद्भव ठाकरे के सितारे गर्दिश में हैं। इन सब के बीच उनके चचेरे भाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे सूबे की राजनीति में अचानक प्रासंगिक हो गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी राज ठाकरे के आवास पर जाकर मिल चुके हैं। एशिया की वैभवशाली नगर निकाय बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में अक्टूबर महीने में चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में शिवसेना (उद्भव गुट) के मराठी मतों की काट के लिए राज ठाकरे सत्ताधारी दल शिवसेना (शिंदे गुट) और भाजपा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। हाल के दिनों में हिंदुत्व की राजनीति की ओर लौटने के कारण भाजपा और मनसे के बीच नजदीकी बढ़ी है।

गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के फैसले के बाद कुछ भी हो सकता है। भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि बस प्रतीक्षा करें और देखें, फिलहाल हम किसी निष्कर्ष पर न जाएं। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, जो लोग कांग्रेस में अपने राजनीतिक कैरियर को लेकर चिंतित हैं, उनके बेहतर विकल्प तलाशने की संभावना है। इसलिए आने वाले महीनों में बहुत कुछ हो

सकता है। वहीं, दूसरी ओर अशोक चव्हाण ने भाजपा से अपनी निकटता के दावों को निराधार कहकर खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के दौरान एक-दूसरे के घर जाने की परंपरा है। इसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस में हैं और पार्टी के भारत जोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे।

भाजपा नेताओं का कहना है कि जून में विधान परिषद चुनाव के दौरान कम से कम सात कांग्रेस विधायकों ने भाजपा उम्मीदवारों की मदद के लिए क्रॉस वोटिंग की थी। इससे कांग्रेस के दलित उम्मीदवार चंद्रकांत हंडोरे को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं, अशोक चव्हाण के नेतृत्व में 11 विधायकों के एक समूह ने एकनाथ शिंदे के विश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान नहीं किया, जिससे भाजपा-शिंदे गुट को विश्वास मत के दौरान प्रचंड जीत मिली। वोटिंग के दौरान भाजपा-शिंदे गठबंधन सरकार को 164 वोट मिले, जबकि विपक्ष को सिर्फ 99 वोट मिले। हालांकि, वोट न देने वाले कांग्रेसी नेताओं में से कुछ ने कहा कि उन्हें ट्रैफिक के कारण देरी हुई। किसी नेता ने कहा कि उन्हें लगा कि भाषणों के बाद फ्लोर टेस्ट होगा। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने सवाल उठाया कि क्या अशोक चव्हाण जो एक पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री विश्वास मत की गंभीरता को नहीं समझते? वहीं, भाजपा के राजनीतिक प्रबंधकों का कहना है कि इस घटनाक्रम को कांग्रेस के कमजोर होने और विकल्प तलाशने वाले नेताओं से जोड़ा जा सकता है।

● बिन्दु माथुर

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद म्यूजिकल चेयर बन गया है। कांग्रेस अध्यक्ष का पद कांग्रेस नेताओं के इर्द-गिर्द घूम रहा है। मगर सभी नेता अध्यक्ष बनने से इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के हर बड़े नेता चाहते हैं

कि राहुल गांधी ही एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनने से लगातार इनकार कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी नेताओं को साफ शब्दों में कह दिया है कि वह किसी भी सूरत में कांग्रेस अध्यक्ष बनना नहीं चाहते हैं। वह बिना पद के ही पार्टी का काम करना चाहते हैं। राहुल गांधी के इनकार के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक, वर्किंग कमेटी की सदस्य कुमारी शैलजा सहित कई नेताओं के नाम अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं। मगर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी चाहती है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष का पद संभाले। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता है। जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ काम कर चुके हैं। ऐसे में वह सब के साथ तालमेल बिठाकर काम कर सकते हैं। जैसे ही कांग्रेसी हलकों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अशोक गहलोत का नाम आगे आया जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। गहलोत का कहना है कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष के रूप में पार्टी को मजबूत कर सकते हैं।

अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कई कार्य प्रारंभ किए थे। जिसका लाभ आने वाले समय में कांग्रेस को मिलेगा। गहलोत राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए 250 से अधिक बड़े नेताओं से समर्थन लेकर राहुल गांधी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। गहलोत का कहना है कि मुझे राजस्थान की जिम्मेवारी मिली हुई है। जहां मेरा कार्यकाल बाकी है। अभी मैं राजस्थान की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। गहलोत का कहना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ ही गुजरात में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें सोनिया गांधी ने वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ऐसे में वह अपनी दोनों जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर कर कांग्रेस की सरकार बनाएं। अभी वह इसी मिशन में लगे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभालना उनके लिए अनुकूल नहीं है। यह सभी को पता है कि राजस्थान के

जादूगर का अध्यक्षी से परहेज !



असफलता का ठीकरा फूटने का डर

यदि विधानसभाओं के चुनावी नतीजे कांग्रेस पार्टी के मनमोहक नहीं रहते हैं तो पूरी जिम्मेदारी अशोक गहलोत की मानी जाएगी। तब असफलता का ठीकरा उनके सर ही फूटेगा। गहलोत किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं। इसीलिए वे दिल्ली जाने के लिए आनाकानी कर रहे हैं। कांग्रेस की राजनीति में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की अपनी-अपनी वफादारों की मंडली है। जिनकी सलाह पर यह नेता काम करते हैं। यदि गहलोत दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इन वफादार नेताओं की बातों को अनसुना करते हैं तो उन्हें उनकी साजिशों का शिकार होना पड़ेगा। और उनका दिल्ली की राजनीति में टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। अभी गहलोत राजस्थान में जैसा चाहते हैं वैसा ही पार्टी करती है। राजस्थान के अधिकांश मंत्री व विधायक उनके ही वफादार हैं। राजनीतिक नियुक्तियों में भी ज्यादातर गहलोत समर्थकों को बनाया गया है। पिछले दिनों राजस्थान से राज्यसभा की तीन सीट के चुनाव हुए थे। जिनमें गहलोत ने कांग्रेस आलाकमान की पसंद को तवज्जो देते हुए तीनों ही बाहरी लोगों को चुनाव जिताकर भेजा था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केशी वेणुगोपाल, कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला व प्रमोद तिवारी राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता है। वे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी व नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री रह चुके हैं।

कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव, सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही गहलोत तीन बार राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता, तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं। बहुमत नहीं मिलने पर भी जोड़-तोड़ कर वह दूसरी बार सरकार बनाकर सफलतापूर्वक चला रहे हैं ऐसे में वह किसी भी स्थिति में मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। गहलोत को पता है कि यदि वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर जयपुर से दिल्ली जाते हैं तो उनके स्थान पर कांग्रेस आलाकमान उनके कट्टर विरोधी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना सकता है। जो गहलोत किसी भी स्थिति में नहीं होने देना चाहते हैं। अशोक गहलोत व सचिन पायलट के बीच छत्तीस का आंकड़ा किसी से छुपा हुआ नहीं

है। दोनों नेता एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते रहते हैं। कांग्रेस आलाकमान द्वारा अपने स्तर पर दोनों नेताओं के मध्य सुलह करवाने के उपरांत भी दोनों नेताओं के मन अभी तक नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं चाहेंगे कि उनके बाद पायलट राजस्थान में मजबूत होकर अपने पैर जमा सके।

गहलोत को पता है कि राजस्थान की राजनीति व दिल्ली की राजनीति में बड़ा फर्क है। राजस्थान की राजनीतिक को तो वह वर्षों से अपनी अंगुली पर नचा रहे हैं। मगर दिल्ली जाने के बाद ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा। उनको पता है कि यदि वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन भी जाते हैं तो पार्टी तो गांधी परिवार के नियंत्रण में रहेगी। ऐसे में वह मात्र कठपुतली बनकर रह जाएंगे। ऊपर से राजस्थान भी उनके हाथ से निकल जाएगा। अगले कुछ महीनों में गुजरात, हिमाचल प्रदेश की विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। उसके बाद अगले साल कर्नाटक, राजस्थान, मप्र और छत्तीसगढ़ विधानसभाओं के चुनाव होंगे।

● जयपुर से आर.के. बिन्नानी

उप्र की राजनीति में अहम जगह रखने वाला यादव कुनबा फिर से बिखर चुका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही चाचा शिवपाल सिंह यादव को खुला खत भेजकर कह चुके हैं कि जहां सम्मान मिले, वहां चले जाइए। और, चाचा शिवपाल यादव भी इसके बाद से ही

भतीजे अखिलेश यादव पर काफी मुखर रहे हैं। बीते दिनों कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (प्रसपा) के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने यदुवंशियों से पिता को छल-बल से अपमानित कर पद से हटाने वाले कंस का जिक्र किया था। और, अब शिवपाल ने यादव तथा अन्य पिछड़ी जातियों को एकजुट करने के लिए यदुकुल पुनर्जागरण मिशन का ऐलान कर दिया है। आसान शब्दों में कहा जाए, तो शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के खिलाफ महाभारत छेड़ने का मूड बना लिया है। लेकिन, इस स्थिति में सवाल उठना लाजिमी है कि यदुकुल के सहारे चाचा शिवपाल क्या भतीजे अखिलेश के लिए चक्रव्यूह रच पाएंगे?

इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के जरिए शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक यानी यादव समाज को साधने की कोशिश करेंगे। ये अलग बात है कि शिवपाल यादव का ये मिशन केवल यादव वोट बैंक ही नहीं अन्य ओबीसी जातियों को भी साधने की जुगत है। शिवपाल सिंह यादव ने यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की नींव जातीय जनगणना, अहीर रैजिमेंट, युवाओं को सरकारी नौकरी या न्यूनतम 8 हजार रुपए प्रतिमाह का भत्ता और किसानों को एमएसपी देने समेत 10 मांगों पर रखी है।

वैसे, शिवपाल की यादव समाज पर पकड़ अच्छी-खासी है। और, वो पहले भी अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में झटका दे चुके हैं। तो, इस बार ओबीसी वर्ग की सभी जातियों का गठजोड़ बनाकर वो अखिलेश यादव को दांव तो दे ही सकते हैं। खैर, यहां ध्यान देने वाली बात ये भी है कि शिवपाल सिंह यादव के इस मिशन में ओमप्रकाश राजभर समेत भागीदारी संकल्प मोर्चा की अन्य पार्टियां भी शामिल हो सकती हैं। क्योंकि, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने से पहले ये तमाम पार्टियां इसी मोर्चे के साथ शिवपाल यादव से जुड़ी थीं।

यदुकुल के सहारे चक्रव्यूह



शिवपाल कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे

अब शिवपाल यादव कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ जाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब सपा से कोई संबंध नहीं रहेगा। वैसे, 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव ने फिरोजाबाद से चुनाव लड़कर इस सीट को भाजपा के खाते में पहुंचाने में काफी मदद की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में हारने के बावजूद शिवपाल यादव को करीब 84 हजार वोट मिले थे। लेकिन, इसकी वजह से सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को हार का सामना करना पड़ा था। तो, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यदुकुल के सहारे चाचा शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश के लिए चक्रव्यूह रचने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि, शिवपाल को अपने बेटे आदित्य यादव को भी राजनीति में स्थापित करवाना है। हो सकता है कि शिवपाल खुद मैनपुरी और आदित्य यादव को आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाने की कोई राह खोज लें। जो भाजपा के समर्थन से खुलती हो।

शिवपाल यादव ने हाल ही में इशारा कर दिया है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी से दावेदारी कर सकते हैं। दरअसल, संभव है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव स्वास्थ्य कारणों के चलते सपा के गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी से 2024 का लोकसभा चुनाव न

लड़ें। इसी वजह से शिवपाल यादव ने कहा था कि अगर नेताजी (मुलायम सिंह यादव) मैनपुरी से अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो वह इस सीट से चुनाव लड़ने का मन बना सकते हैं। बता दें कि शिवपाल यादव मैनपुरी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली ही जसवंतनगर विधानसभा सीट से विधायक हैं।

राजनीतिक रूप से देखा जाए, तो शिवपाल यादव मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़कर सीधे मुलायम सिंह की विरासत पर दावा ठोकेंगे। और, अखिलेश यादव के पास शिवपाल को रोकने के लिए कोई खास चेहरा भी नहीं है। वैसे भी आजमगढ़ की संसदीय सीट छोड़कर अखिलेश यादव ने उप्र की राजनीति पर ही ध्यान देने का संदेश

दिया था। इस स्थिति में अगर शिवपाल के सामने कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं होता है तो संभव है कि यादव वोट बैंक आसानी से शिवपाल के साथ चला जाएगा। और, अगर इसमें भाजपा के समर्थन का तड़का लग गया तो जीत निश्चित भी कही जा सकती है।

उप्र विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भाजपा का दामन थाम लिया था। हालांकि, अपर्णा यादव को उप्र विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपना प्रत्याशी नहीं बनाया था। लेकिन, चुनाव प्रचार में अपर्णा यादव काफी आगे रही थीं। इसका लब्बोलुआब यही रहा कि भले अपर्णा यादव अपने साथ कोई वोटबैंक न लाई हों। लेकिन, अपर्णा के सहारे भाजपा ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ अपने ही परिवार को न संभाल पाने का संदेश लोगों के बीच भेज दिया था।

वैसे, जब 2024 के लोकसभा चुनाव में दो साल से भी कम का समय बचा है तो भाजपा बिना किसी रणनीति के आगे बढ़ रही हो ये मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि, लोकसभा सीटों के लिहाज से उप्र सबसे बड़ा राज्य है। और, पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में भाजपा ने उप्र में दमदार प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि शिवपाल सिंह यादव के भाजपा के साथ आने की संभावना जताई जा रही है। वैसे भी राष्ट्रपति के चुनाव में शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी को दांव देते हुए भाजपा समर्थित प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया था।

● लखनऊ से मधु आलोक निगम

ए नडीए यदि बिहार के घटनाक्रम से फिलहाल स्तब्ध है, तो इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि वह बिहार सरकार को अपने मन से शासन करने के लिए संपूर्ण संवैधानिक अधिकार (राज्य-केंद्र के बीच) देकर चुप होकर बैठ जाएगी। यह कभी हो ही नहीं सकता कि उसके शीर्षस्थ अपने अपमान का

घूंट पीकर बिहार के वर्तमान सरकार को निर्बाध रूप से चलने दें। वैसे उसे कई राज्यों में अपने पराजय रूपी अपमान को झेलना पड़ा है, लेकिन अपमान को गांठ बांधकर आक्रमण-दर-आक्रमण करना उसकी एकमात्र आदत है। पश्चिम बंगाल में अपने षड्यंत्र के सारे घोड़े खोलने के बाद हाथ क्या आया! पंजाब में तिल का ताड़ बनाकर वहां अपने को इस तरह समूल नाश किया जिसके कारण आज वहां की विधानसभा में उसका नामलेवा भी नहीं है। यदि कोई एकाध ढूंढे से मिल भी जाए तो वहां यही कहावत चरितार्थ होती है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मप्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र इसके ताजा उदाहरण हैं जहां अपनी दुर्गति कराने के बाद फिर से सत्ता में आ गई। आज के राजनीतिज्ञों का उद्देश्य भी तो यही होता है कि येन-केन-प्रकारेण सत्ता उनकी हो जाए।

जनहित के लिए वे ऐसा चाहते हैं, यह मानना भूल होगी, क्योंकि स्वहित की रक्षा करना ही उनका मूलमंत्र है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दल बदलने के बाद बिहार भाजपा के ही कई नेताओं ने अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताने का प्रयास किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी पार्टी को ठगा है, जनता को भी ठगा है। अब यह तो मंथन का विषय कि सच में किसने किसे ठगा है। लगभग यही कुछ वर्ष पहले महाराष्ट्र में हुआ था, जब सुबह-सवरे राष्ट्रपति शासन को समाप्त करके देवेंद्र फडणवीस शपथ ग्रहण समारोह करके कुछ घंटों के लिए मुख्यमंत्री बन बैठे थे। लेकिन, इसके लिए कितनी आलोचनाओं का सामना भाजपा को सुनना पड़ा, यह वही जानती है। बिहार के लिए भी सत्ता परिवर्तन की बात की जा रही है। वहां भी तो यही कहा जा रहा है कि भाजपा ने नीतीश सरकार को गिराने या उनके कद को छोटा करने का प्रयास किया।

बिहार के लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार ने भाजपा को छोड़कर उसकी बढ़ती रफ्तार को रोकने का प्रयास किया है। इससे बिहार का विकास होगा। वैसे यह सच है कि लगभग 30 वर्ष से बिहार में जो कुछ हुआ, उसकी नाकामी और उपलब्धि का श्रेय लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को ही सदैव दिया जाता रहेगा, क्योंकि इतने लंबे समय तक बिहार में इन्हीं दोनों नेताओं का शासन रहा है। वैसे आदिकाल से ही बिहार पलायन के लिए मशहूर रहा है, लेकिन इन दोनों के कार्यकाल में जो पलायन हुआ, उसे आप देश के किसी शहर में किसी कस्बे में देख सकते हैं। कहते हैं इतने वर्षों

पलटवार की ताक में भाजपा



बिहार की स्थिति जस की तस

बिहार के साथ भी तो यही हुआ। ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने वाले बिहार को उसी काल से पिछड़ा और उपेक्षित घोषित करके किसी का भी लाभ नहीं हुआ। न तो बिहार आत्मनिर्भर बन सका, न किसी ने उसकी गरीबी को दूर करने का प्रयास किया। पिछली सरकार में उपमुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी उस दिन बहुत खुश हुए थे जिस दिन जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटा लिया गया था। उन्होंने प्रसन्नता जताते हुए कहा था कि अब बिहारियों को वहां भी नौकरियां मिल जायें करंगी। उनके इस शर्मनाक बयान का आज भी देश में उपहास उड़ाया जाता है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, दोनों लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए राजनेता हैं। नीतीश कुमार गांधीवादी भी है, यह उनके कार्यकलापों से दिखता है। बिहार में शराबबंदी उसी का उदाहरण है। गांधीजी शराब के विरोधी थे। आज नीतीश कुमार भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं, लेकिन इससे राजस्व का राज्य में जो नुकसान हो रहा है, पता नहीं उसकी भरपाई सरकार कैसे कर पा रही है। बिहार वैसे भी गरीब और पिछड़ा राज्य है। राजस्व की इतनी बड़ी हानि बार-बार गले के नीचे नहीं उतरती है।

में राज्य के विकास के लिए कोई कार्य किया ही नहीं गया। सभी अपना स्वार्थ सिद्धि करते रहे। परिणाम यह हुआ कि राज्य में रहकर कुछ धनपति बन गए और कुछ अपनी जिंदगी किसी प्रकार गुजारते रहे। काफी लंबे काल तक बिहार में सत्तासीन एनडीए का दावा है कि वह देश का विकास करना चाहते हैं, लेकिन उनकी सोच बिहार के विकास के लिए आक्रामक क्यों नहीं है, जैसा कि अन्य राज्यों में उनके शासनकाल में देखा गया। न तो इतने लंबे कार्यकाल में कोई उद्योग लगाए गए, न ही रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए कोई नई योजना बनाई जा सकी। यदि कोई योजना सरकार ने बनाई भी होगी तो उसे धरातल पर किसी ने उतरते ही नहीं देखा। आज नई सरकार के गठन के बाद राज्य में जो उज्वल भविष्य की

खुशी दिख रही है, उसका कारण भी तो यही है। लोगों में एक आशा की किरण जगी है कि शायद अब कुछ राज्य में रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाएं। वैसे, सरकार की योजना भी अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार देने की है, लेकिन उसमें उन्हें कितनी सफलता मिलती है, यह देखने की बात होगी। लेकिन, क्या इस नई सरकार को इतना समय मिल पाएगा कि वह अपने वादे पूरे करते हुए युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा सके। ऐसा इसलिए, क्योंकि कहा तो यह जा रहा है कि अपनी खुन्नस कहिए या अपमान का बदला लेने के लिए भाजपा सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करे। दिल्ली में चर्चा है कि बहुत जल्द प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग को इस सरकार को तहस-नहस करने के लिए अपने हथकंडे अपनाने के आदेश दिए जा सकते हैं।

गांधीजी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, वे ताजा फैशन के मुताबिक बेदाग पोशाक पहनने वाले वकील हुआ करते थे। लेकिन, जब उनकी भारत वापसी हुई तो उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने आदेश दिया था कि पहले वर्ष कान खुले, लेकिन मुंह बंद रखकर पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करें। महात्मा गांधी ने यही किया। हिंदुस्तान की यात्रा में जो हृदयविदारक दृश्य उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने अर्द्धनग्न रहकर देशहित में काम करना शुरू किया। क्या आज के हमारे नेतागण इस तरह कार्य कर सकते हैं! हां, समय बदला विकास के नए-नए आयाम बनते गए। विश्व की तरक्की हो रही है, लेकिन हम निश्चित रूप से उनमें बहुत पीछे चल रहे हैं। यह ठीक है कि आजादी के सैनानियों के महानतम बलिदान से हमें स्वतंत्र जीने का रास्ता बना गए, लेकिन उन रास्तों को सही करना हम जीवित लोगों का है। जबकि, हम एक-दूसरे का पैर खींचने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। इससे यही होता है कि दुनिया विकास के झंडे गाड़ती रहती है और हम पिछड़ते रहते हैं।

● विनोद बक्सरी

ANU SALES CORPORATION



When time matters,
Real 200 t/h throughput

Even with double reagent reactions, the analyzer keeps its speed. Up to 4 volumes can be handled in every cycle.

1	2	3	•	17	18	19	20	•	33	34	35	36	37	•	45	46
R1+S	L1				R2	L2					WS1				WS2	

Dispensation
 Aspiration



We Deal in Pathology & Medical Equipment



 Biosystems
 The Highest Flexibility



Address : M-179, Gautam Nagar,
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

 9329556524, 9329556530
  Email : ascbhopal@gmail.com

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई के मुखिया इमरान खान ने आखिरकार वह हद पार कर दी, जिसके बारे में पाकिस्तान में सोचा तक नहीं जाता। उन्होंने फैसलाबाद की एक रैली में पाकिस्तान के अगले सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर जो कुछ कहा, उसकी गुंजाइश पाकिस्तान की ताकतवर सेना कभी नहीं की होगी कि राजनीतिक बिरादरी का कोई व्यक्ति उसके विषय में ऐसी टीका-टिप्पणी करे। इमरान ने भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ ही पूरे शरीफ खानदान के अलावा आसिफ अली जरदारी को भी निशाने पर लिया, जिनके बेटे मौजूदा सरकार में विदेश मंत्री हैं। उन्होंने अपने सियासी तख्तापलट के बाद बनी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उसके शासन में लोगों की दुश्वारियां बढ़ी हैं। ये बातें उनके समर्थकों को रास आ रही थीं। उनका जनाधार बना हुआ था।

ऐसी राजनीतिक टिप्पणियों के बारे में कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन फैसलाबाद में इमरान कुछ ज्यादा आगे ही बढ़ गए। उन्होंने कहा कि नए चुनाव कराने की उनकी मांग इसीलिए खारिज कर दी गई, क्योंकि शरीफ परिवार और जरदारी एक दब्बू सेना प्रमुख की नियुक्ति करना चाहते हैं। ज्ञात हो कि सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है। इमरान ने कहा कि ये भ्रष्ट नेता किसी मजबूत और देशभक्त सेना प्रमुख को नहीं चाहते, जो उनकी संपत्ति के स्रोत के बारे में उनसे सवाल कर सके। उन्होंने कहा कि अगले सेना प्रमुख की नियुक्ति पूरी तरह योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। उनकी ऐसी टिप्पणियां किसी राजनीतिक बम की तरह थीं, जिन्हें मौजूदा सैन्य नेतृत्व के साथ ही वर्तमान सरकार को निशाना बनाकर फेंका गया।

इमरान की टिप्पणी पाकिस्तानी सेना को अखरना स्वाभाविक है। पाकिस्तानी सेना ने खुद को देशभक्ति के पर्याय रूप में कुछ ऐसे पेश किया है कि केवल वही एकमात्र संस्थान है, जो देश के स्थायी शत्रु यानी भारत से मुल्क की रक्षा करने में सक्षम है। वह यह दिखाती आई है कि उसके जनरल खासकर सेना प्रमुख ईमानदार और काबिल हैं, जबकि नेता केवल अपने हितों के बारे में सोचते हैं और जनकल्याण में उनकी कोई रुचि नहीं। यही कारण है कि शहबाज शरीफ सरकार द्वारा अगले सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर इमरान खुलेआम जो सवाल उठा रहे हैं, वे सेना में अधिकांश वर्गों को स्वीकार्य नहीं।

पाकिस्तानी सेना प्रमुख के चयन की प्रक्रिया स्पष्ट है। सेना मुख्यालय द्वारा चार-पांच वरिष्ठ जनरलों के नाम भेजे जाते हैं। प्रधानमंत्री उनमें से एक पर मुहर लगाते हैं। जब कोई व्यक्ति चुन लिया जाता है तो सेना निर्णय का सम्मान कर

पाकिस्तान में अनहोनी के आसार



पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट

एक तिहाई पाकिस्तान डूबा हुआ है। खेत जलमग्न हैं। करीब 10 अरब डालर से अधिक का बुनियादी ढांचा तबाह हो गया है। 'कंगाली में आटा गीला' वाली स्थिति यह है कि बाढ़ तब आई, जब पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट है। मुल्क बाहरी मदद का मोहताज हो गया है। वह आईएमएफ से लेकर सऊदी अरब और यूएई के आगे कटोरा लिए खड़ा है। इतने भारी संकट के बावजूद भारत के प्रति उसका शत्रुता भाव नहीं घटा और वह भारत से आयात के लिए तैयार नहीं, जिस पर उसने कश्मीर में संवैधानिक परिवर्तन के बाद प्रतिबंध लगा दिया था। पाकिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के प्रति संवेदना जताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही संदेश दिया। प्रश्न यह है कि क्या सहायता सामग्री भेजी जानी चाहिए? ध्यान रहे कि शहबाज शरीफ ने भारत पर जम्मू-कश्मीर में जनसंहार का मिथ्यारोप मढ़ा है। इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि मदद के बावजूद पाकिस्तान आतंकी हरकतों से बाज आए। इससे मोदी को ही शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। पठानकोट, उरी और पुलवामा हमलों की कड़वी स्मृतियां भूले नहीं भुलाई जा सकती। इसीलिए मोदी ने हमदर्दी तो दिखाई, पर मदद की पेशकश न करके राजनीतिक एवं कूटनीतिक स्तर पर बिलकुल सही किया।

एकजुटता प्रदर्शित करती है। सेना प्रमुख भले ही प्रधानमंत्री द्वारा चुने जाते हों, मगर उनके लिए सेना के हित ही सर्वोपरि होते हैं और सरकार या प्रधानमंत्री के राजनीतिक हितों की उन्हें बहुत ज्यादा परवाह नहीं होती। वह स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए स्वयं को पाकिस्तान के मुख्य रक्षक की भूमिका में देखता है।

पाकिस्तानी सेना अपनी और खासकर अपने मुखिया की यही छवि जनता के बीच भुनाती आई है। इमरान इसी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि उनके पसंदीदा जनरल फैज हमीद अब शीर्ष पद की होड़ में पिछड़ गए हैं, जिन्हें बाजवा पहले ही आईएसआई के मुखिया पद से चलता कर चुके हैं। असल में हमीद के चलते ही इमरान और बाजवा में तनातनी बढ़ी थी, क्योंकि इमरान ने हमीद के स्थानांतरण का प्रतिरोध किया था। यह स्थिति तब बनी, जब इमरान को सेना की सहायता से ही सत्ता मिली थी। सेना ने इमरान की टिप्पणी पर तल्ख बयान में कहा, 'फैसलाबाद में एक राजनीतिक रैली के दौरान पीटीआई के चेयरमैन द्वारा सेना के शीर्ष नेतृत्व के प्रति अनावश्यक एवं अपमानजनक टिप्पणी से पाकिस्तानी सेना हैरान

है।' उसने कहा कि इमरान एक ऐसे समय सेना के शीर्ष नेतृत्व को 'बदनाम और कमजोर' करने पर तुले हैं, जब सेना देश की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही है। उसने शिकायती लहजे में कहा कि इमरान सेना प्रमुख की चयन प्रक्रिया को 'स्कैंडलाइज' करने पर आमादा हैं।

पाकिस्तान सरकार ने भी इमरान के बयान की निंदा की। यकीनन, पाकिस्तान के विभिन्न संस्थानों में इमरान के समर्थक भी अब पीटीआई से पल्ला झाड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसा माना जाता है कि इमरान को सेना में कुछ वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों का समर्थन रहा है। वे भी अब इमरान को लेकर एहतियात बरतेंगे, क्योंकि उन्हें राजनीतिक रूप से अपरिपक्व और सियासी बोझ के रूप में देखा जाएगा। ऐसे आसार और प्रबल संभावनाएं हैं कि फैसलाबाद वाले बयान पर इमरान को कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़े। इमरान का जनाधार होने के बावजूद अब सेना उनकी सत्ता वापसी में अड़ंगा लगाएगी। इससे पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति और अस्थिर हो जाएगी।

● ऋतेन्द्र माथुर

पिछले सात दशकों से भारत-चीन संबंध उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं। भारत के तमाम शांति प्रयासों के बावजूद चीन द्वारा भारतीय सीमाओं और हितों पर चोट करना लगातार जारी है। जून 2020 में

गलवन घाटी में हुई झड़प ने दोनों देशों के बीच कड़वाहट को और गहरा कर दिया है। चाहे 1962 का युद्ध हो और उसके पश्चात सीमा

बदलनी होगी चीन नीति

विवाद के समाधान के प्रयास हों या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्य बनने का, चीन लगातार अड़ियल रुख अपनाए हुए है।

चीन हिंद महासागर में स्ट्रिंग ऑफ पर्स नीति के तहत भारत के चारों तरफ अपने सैन्य अड्डे का विस्तार करता रहा है। इसके साथ ही वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध भारत के प्रस्तावों पर भी रोड़ा लगाता रहा है। इससे चीन की नई दिल्ली के प्रति दुर्भावना स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। चीन के अड़ियल रुख के कारण ही द्विपक्षीय स्तर पर लगातार वार्ता के बाद भी भारत-चीन के बीच सीमा विवाद मामले में कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। अब यह साफ है कि वह सीमा विवाद सुलझाने का इच्छुक ही नहीं है।

गलवन में हुई झड़प के बाद 16 दौर की सैन्य वार्ता और अन्य मंचों पर द्विपक्षीय वार्ताओं के बाद भी सीमा पर तनाव की स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। भारत लगातार कह रहा है कि **समग्र द्विपक्षीय संबंधों में** प्रगति के लिए सीमा पर शांति एवं स्थिरता पूर्व शर्त है। इसके बाद भी पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले सभी स्थानों में चीन अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए हुए है। यह स्थिति चीन द्वारा संबंध सुधार के दावों को पूरी तरह खोखला साबित करती है।

चीन द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय नियमों और छोटे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन जारी है। यह क्षेत्रीय अशांति का कारण बन रहा है। हिंद महासागर के अफ्रीकी देश मजबूती में चीन द्वारा 2016 से नौसैनिक अड्डा का निर्माण किया जा रहा है, जिससे स्वेज नहर से आने जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर चीन को रणनीतिक



बढ़त हासिल हो सकती है। यह हिंद महासागर में भारतीय हितों के विपरीत है। हाल में भारत की आपत्तियों के बावजूद चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5 श्रीलंका के हंबनटोटा द्वीप पर गया, जबकि श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक अनुमति भी नहीं दी थी। चीन के जासूसी जहाज का इस क्षेत्र में आना भारत-चीन संबंधों के गिरते ग्राफ को ही दर्शाता है। अनेक वैश्विक मुद्दों पर भारत-चीन में आम सहमति नहीं है। वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में चीन द्वारा भारत के प्रयासों में बार-बार रोड़ा अटकया जा रहा है। पिछले दिनों भारत और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन चीन ने मक्की को सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव पर तकनीकी रोक लगा दी। यही हरकत उसने एक अन्य आतंकी अब्दुल रउफ अजहर के मामले में भी की।

गलवन की घटना के बाद स्थितियां काफी बदल गई हैं। भारत में चीनी विरोध की लहर चल रही है। भारत सरकार द्वारा सैकड़ों चीनी एप को प्रतिबंधित किया गया है। अब भारत को वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी चीन नीति का समग्र विश्लेषण करना चाहिए और उसमें बुनियादी बदलाव लाना चाहिए। हाल में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह चिंता प्रकट की कि बीजिंग ने भारत-चीन सीमा पर जो किया, उसके बाद दोनों देशों के बीच संबंध बेहद कठिन दौर से गुजर रहे

हैं। यदि दोनों देश हाथ नहीं मिला सके तो यह क्षेत्र एशिया की सदी बनने से चूक जाएगा।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वैश्विक राजनीति आजकल अपने सबसे अनिश्चित दौर में है। कुछ विश्लेषक शी जिनपिंग के नेतृत्व वाले चीन की तुलना हिटलर के नेतृत्व वाले जर्मनी से कर रहे हैं। चीन की विस्तारवादी नीतियों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र को अशांत कर दिया है। चीन द्वारा अपने पड़ोसी देशों के क्षेत्रों पर दावा करना और अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमाओं एवं कानूनों के लगातार उल्लंघन से इस क्षेत्र में अशांति और युद्ध की आशंका प्रबल होती जा रही है। ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत को चीन के प्रति अपनी नीति में कुछ बड़े बदलाव करने की आवश्यकता है।

भारत को व्यापक वैश्विक समर्थन हासिल करना चाहिए, जिससे चीन की वैश्विक पहुंच को संतुलित किया जा सके। भारत को अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में और सक्रिय होना चाहिए। इसके साथ वैश्विक एवं क्षेत्रीय आपूर्ति चेन को नियमित रखने के प्रयासों पर लगातार ध्यान देना चाहिए, जिससे चीन की व्यापारिक तानाशाही को नियंत्रित किया जा सके। क्षेत्रीय आपूर्ति चेन के लिए नए सिरे से विचार करना चाहिए, जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को मिलकर एक आर्थिक गलियारे के निर्माण पर विचार करना चाहिए।

● कुमार विनोद

ताइवान मुद्दे पर चीन लगातार विश्व के सभी

पड़ोसी देशों की संप्रभुता का सम्मान नहीं

देशों से वन चाइना पॉलिसी पर समर्थन मांग रहा है। यदि चीन को वन चाइना पॉलिसी की वैधता की चिंता है तो उसे अपने पड़ोसी देशों की संप्रभुता का भी सम्मान करना चाहिए। चीन को भारत की जमीन पर अपनी अनाधिकृत उपस्थिति को समाप्त करते हुए भारत की संप्रभुता और हिंद-प्रशांत क्षेत्र को खुला एवं मुक्त रखने में सहयोग करना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने 2010 के बाद से अब तक एक बार भी आधिकारिक मंचों से वन चाइना पॉलिसी का जिक्र नहीं

रहा है। अब समय आ गया है कि भारत यह स्पष्ट करे कि वह इन-इन कारणों से इस नीति का समर्थन नहीं कर सकता। यदि चीन को भारत की संवेदनशीलता की परवाह नहीं तो फिर भारत को भी उसकी संवेदनशीलता की चिंता करना छोड़ देना चाहिए। इसी तरह यदि चीन द्विपक्षीय समझौतों का पालन नहीं कर रहा है तो फिर भारत को भी यह स्पष्ट करना होगा कि वह उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बज सकती।

किया है। यह चीन के लिए चिंता का कारण बनता जा



**For Any Medical &
Pathology Equipments
Contact Us**

D-10™ Hemoglobin Testing System For HbA_{1c}, HbA₂ and HbF

Flexible

to solve more testing needs

Comprehensive

B-thalassemia and
diabetes testing

Easy

for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; it's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or HbA₂/F/A₂ testing using primary tube sampling—so you can accomplish more in fewer steps. With the D-10™ System, it's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress—and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

📍 C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 ✉ Email : shbple@rediffmail.com
☎ Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

महिलाओं के स्वास्थ्य का मामला अगर देश के समग्र जीवन के हर पहलू पर असर डाल रहा हो तो इसका आंकलन करने के लिए बड़े पैमाने पर सिर्फ महिला केंद्रित शोध सर्वेक्षणों की दरकार है। मगर अब तक जो अंदाजा लगता है उस हिसाब से महिलाओं को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर करने की फौरी जरूरत दिखाई पड़ती है।

देश के कुल कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी की बात हर साल होती है। खुलकर बताया जाता है कि

आर्थिक मामले में देश की महिलाएं भेदभाव की शिकार हैं। समाज में महिलाओं को समान अधिकार न मिलने का मुद्दा दशकों से चला आ रहा है, मगर उनके स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं होती। एक सर्वेक्षण के मुताबिक देश में महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज्यादा हो जाने के संकेत हैं। ऐसे में देश की आबादी के सबसे बड़े तबके के रूप में भी महिलाओं के स्वास्थ्य पर नजर जरूर जानी चाहिए। यह तथ्य चौंकाने वाला है कि देश की हर दूसरी महिला खून की कमी से पीड़ित है और हर तीसरी महिला का 'बाडी मास इंडेक्स' कम है। कुल आबादी की एक चौथाई महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं। तमाम वादों और उसके बाद दावों के बावजूद अगर यह हालत हो तो महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर हमें सतर्क हो जाने की जरूरत है।

कई सर्वेक्षणों से उजागर है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम पोषण मिलता है। इसका एक बड़ा कारण हमारी पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था को भी माना गया। सीमित आय वाले परिवारों में बचत के दबाव में आमतौर पर लड़कियों की तुलना में लड़कों को ज्यादा पोषक आहार दिया जाता है। कोरोना महामारी के पहले 'कम्प्रेहेंसिव नेशनल न्यूट्रीशन सर्वे 2019' के मुताबिक सभी पोषक तत्वों से भरपूर भोजन देश के बड़े तबके को नहीं मिल पा रहा था। मगर कोरोनाकाल में हालात हद से ज्यादा बिगड़ गए।

टाटा कानैल इंस्टीट्यूट फार एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रीशन की एक अध्ययन के मुताबिक कोरोना बंदी के समय महिलाओं के पोषक आहार में 42 फीसदी की गिरावट आ गई। उन्हें फल, सब्जियां और दूसरे पोषक खाद्य पदार्थ कम मिले। स्कूलों में 'मिड डे मील' जैसी योजनाएं कोरोना के चलते बंद रहने से आयरन फोलिक एसिड जैसे पूरक और पोषक आहार से छात्राएं वंचित रहीं। यह एक उजागर तथ्य है कि अपने देश की महिलाओं में पोषक तत्वों में सबसे ज्यादा कमी आयरन की ही पाई जाती है। यह बात चौंकाने वाली है कि आज भी 57 फीसदी भारतीय महिलाएं एनीमिया यानी रक्ताल्पता का शिकार हैं।

महिलाओं का गिरता स्वास्थ्य



कार्यबल में भी अहम भूमिका निभाती हैं महिलाएं

जागरूक तबके में अब यह भी सोचा जाने लगा है कि महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता न सिर्फ मानवता के लिहाज से तर्कसंगत है, बल्कि जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाली अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। देश की आधी आबादी होने के नाते महिलाएं कार्यबल में भी अहम भूमिका निभाती हैं। हालांकि कुछ लोग यह कुतर्क दे सकते हैं कि कार्यबल में उनकी भागीदारी कम है, लिहाजा अर्थव्यवस्था के लिहाज से श्रमबल में महिलाओं की कम भागीदारी ज्यादा असर नहीं डालती। यह कुतर्क वे ही दे सकते हैं, जो यह नहीं जानते कि देश के असंगठित क्षेत्र में उत्पादक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा दिखाई देती है। आबादी के लिहाज से चाहे देश का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र हो या कुटीर उद्योग हो या फिर भरा-पूरा वस्त्र उद्योग हो, इस असंगठित क्षेत्र का बड़ा हिस्सा आमतौर पर महिलाएं ही संभाले हैं। अगर इतनी बड़ी महिलाओं की आबादी का स्वास्थ्य सवालों से घिरा हो, तो एक आंकलन यह भी होना चाहिए कि महिलाओं का स्वास्थ्य देश के आर्थिक विकास को किस तरह प्रभावित कर रहा है।

घरेलू महिलाओं में भी कुपोषण की समस्या एक पहली बनी हुई है। प्रत्यक्ष अनुभव है कि घरेलू महिलाएं आमतौर पर सबको खाना खिलाने के बाद सबसे बाद में बचा हुआ खाना खाती हैं। भारतीय परिवेश में यह चलन उन्हें कई बार पर्याप्त और संतुलित भोजन से वंचित रखता है। इसी तरह कम उम्र में शादी का चलन भी कम जिम्मेदार नहीं है। कम उम्र में गर्भवती होने से भी शरीर पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ते हैं।

मसलन, नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे-5 के मुताबिक 23.3 फीसदी लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र के पहले ही कर दी गई। किशोरावस्था में मां बनने की दर आज भी 6.8 फीसदी है। कुपोषण की समस्या तो वयस्क गर्भवती महिलाओं के साथ भी है। यह एक स्थापित तथ्य है कि गर्भावस्था में पर्याप्त पोषक तत्व न मिल पाने से महिला और शिशु दोनों ही लंबे समय तक कुपोषण का शिकार रहते हैं। आजकल स्वास्थ्य विशेषज्ञ भारतीय महिलाओं में एक 'हिडन हंगर' यानी परोक्ष भूख की बात कह रहे हैं। इसका अर्थ है शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। कई दशकों तक महिलाओं के पोषण में मुख्य ध्यान आयरन की पूर्ति पर लगाया जाता रहा। लेकिन अब विशेषज्ञ भारतीय महिलाओं में विटामिन डी, विटामिन बी12 और जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पर भी ध्यान दिला रहे हैं। आज के सभ्य समाज में भी भारतीय

महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार बन रही हैं। घरेलू हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को भी गंभीर चोट पहुंचाती है। नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में 2019-21 में घरेलू हिंसा की दर 29.3 फीसदी थी। इतना ही नहीं, महिला स्वास्थ्य का एक और बड़ा पहलू है कि सामाजिक उपेक्षा के डर से ज्यादातर महिलाएं या उनके परिवार महिलाओं की बीमारियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। आज भी पुरुषों और महिलाओं में एक जैसे रोग को समाज में अलग-अलग नजरिए से देखने का चलन है।

महिलाएं खुद भी सामाजिक दबाव और घरेलू कामों में व्यवधान के डर से चिकित्सीय सलाह लेने से बचती हैं। यह बात भी छिपी हुई नहीं है कि चिकित्सा सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच भी पुरुषों की तुलना में कम है। इस बारे में विश्व आर्थिक मंच हर साल 'ग्लोबल जेंडर गैप' रिपोर्ट जारी करता है। ताजा रिपोर्ट में भारतीय महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की स्थिति यह है कि 146 देशों में अपना देश आखिरी पायदान पर रहा। खासकर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं महिलाओं के लिए आसानी से पहुंच में नहीं हैं। कई बार अस्पतालों में महिला डॉक्टर और नर्स या महिला कर्मचारी न होने से महिलाएं अस्पताल जाने से झिझकती हैं।

● ज्योत्सना अनूप यादव

हिंदू धर्म का एकमात्र धर्मग्रंथ है वेद। वेदों के चार भाग हैं- ऋग, यजु, साम और अथर्व। वेदों के सार को वेदांत या उपनिषद कहते हैं और उपनिषदों का सार या निचोड़ गीता में है। गीता हिंदुओं का सर्वमान्य एकमात्र धर्मग्रंथ है। श्रीमद्भगवद्गीता रहस्यों और रोमांच से भरा धर्मग्रंथ है। गीता के ज्ञान को भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में खड़े होकर दिया था। यह श्रीकृष्ण-अर्जुन संवाद नाम से विख्यात है। वैसे तो गीता श्रीकृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ एक संवाद है, लेकिन कहते हैं कि भगवान श्रीकृष्ण के माध्यम से उस कालरूप परम परमेश्वर ने गीता का ज्ञान विश्व को दिया। श्रीकृष्ण उस समय योगारूढ़ थे। गीता के चौथे अध्याय में कृष्णजी कहते हैं कि पूर्व काल में यह योग मैंने विवस्वान को बताया था। विवस्वान ने मनु से कहा। मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। यूँ पीढ़ी दर पीढ़ी परम्परा से प्राप्त इस ज्ञान को राजर्षियों ने जाना पर कालांतर में यह योग लुप्त हो गया। और अब उस पुराने योग को ही तुम्हें पुनः बता रहा हूँ। परंपरा से यह ज्ञान सबसे पहले विवस्वान् (सूर्य) को मिला था। जिसके पुत्र वैवस्वत मनु थे।

श्रीकृष्ण के गुरु घोर अंगिरस थे। घोर अंगिरस ने देवकी पुत्र कृष्ण को जो उपदेश दिया था वही उपदेश श्रीकृष्ण गीता में अर्जुन को देते हैं। छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि देवकी पुत्र कृष्ण घोर अंगिरस के शिष्य हैं और वे गुरु से ऐसा ज्ञान अर्जित करते हैं जिससे फिर कुछ भी ज्ञातव्य नहीं रह जाता है। यद्यपि गीता द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के समय रणभूमि में किंकर्तव्यविमू? अर्जुन को समझाने के लिए भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा कही गई थी, किंतु इस वचनमृत की प्रासंगिकता आज तक बनी हुई है।

गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। उसमें यम-नियम और धर्म-कर्म के बारे में भी बताया गया है। गीता ही कहती है कि ब्रह्म (ईश्वर) एक ही है। गीता को बार-बार पढ़ेंगे तो आपके समक्ष इसके ज्ञान का रहस्य खुलता जाएगा। गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। गीता में सृष्टि उत्पत्ति, जीव विकासक्रम, हिंदू संदेवाहक क्रम, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म, कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी, देवता, उपासना, प्रार्थना, यम, नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, वंश, कुल, नीति, अर्थ, पूर्वजन्म, जीवन प्रबंधन, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, कर्मसिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्रीभाव आदि सभी की जानकारी है।

श्रीमद्भगवद्गीता योगेश्वर श्रीकृष्ण की



रहस्यों से भरी है श्रीमद्भगवद्गीता

वाणी है। इसके प्रत्येक श्लोक में ज्ञानरूपी प्रकाश है, जिसके प्रस्फुटित होते ही अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान-भक्ति-कर्म योग मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है, इन मार्गों पर चलने से व्यक्ति निश्चित ही परमपद का अधिकारी बन जाता है। 3112 ईसा पूर्व हुए भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। कलियुग का आरंभ शक संवत् से 3176 वर्ष पूर्व की चैत्र शुक्ल एकम (प्रतिपदा) को हुआ था। वर्तमान में 1939 शक संवत् है। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईपू में हुआ। इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी तभी से कलियुग का आरंभ माना जाता है। उनकी मृत्यु एक बहेलिए का तीर लगने से हुई थी। तब उनकी उम्र 119 वर्ष थी। इसका मतलब कि आर्यभट्ट के गणना अनुसार गीता का ज्ञान 5154 वर्ष पूर्व श्रीकृष्ण ने अर्जुन को दिया था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब यह ज्ञान दिया गया तब तिथि एकादशी थी। संभवतः उस दिन रविवार था। उन्होंने यह ज्ञान लगभग 45 मिनट तक दिया था। गीता में श्रीकृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है।

गीता की गणना उपनिषदों में की जाती है। इसीलिए इसे गीतोपनिषद् भी कहा जाता है। दरअसल, यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। महाभारत में ही कुछ स्थानों पर उसका हरिगीता नाम से उल्लेख हुआ है। (शांति पर्व अ. 346.10, अ. 348.8 व 53)। श्रीकृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को इसलिए दिया क्योंकि वह कर्तव्य पथ से भटककर संन्यासी

और वैरागी जैसा आचरण करके युद्ध छोड़ने को आतुर हो गया था वह भी ऐसे समय जब की सेना मैदान में डटी थी। ऐसे में श्रीकृष्ण को उन्हें उनका कर्तव्य निभाने के लिए यह ज्ञान दिया। गीता को अर्जुन के अलावा और संजय ने सुना और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया।

गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिस पर दुनियाभर की भाषा में सबसे ज्यादा भाष्य, टीका, व्याख्या, टिप्पणी, निबंध, शोधग्रंथ आदि लिखे गए हैं। आदि शंकराचार्य, रामानुज, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क, भास्कर, वल्लभ, श्रीधर स्वामी, आनंद गिरि, मधुसूदन सरस्वती, संत ज्ञानेश्वर, बालगंगाधर तिलक, परमहंस योगानंद, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन, महर्षि अरविंद घोष, एनी बेसेंट, गुरुदत्त, विनोबा भावे, स्वामी चिन्मयानन्द, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी नारायण, जयदयाल गोयंदका, ओशो रजनीश, स्वामी क्रियानन्द, स्वामी रामसुखदास, श्रीराम शर्मा आचार्य आदि सैंकड़ों विद्वानों ने गीता पर भाष्य लिखे या प्रवचन दिए हैं। लेकिन कहते हैं कि ओशो रजनीश ने जो गीता पर प्रवचन दिए हैं वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रवचन हैं। किस समय, किसने गीता को महाभारत से अलग कर एक स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दिया इसका कोई प्रमाण कहीं नहीं मिलता। आदि शंकराचार्य द्वारा भाष्य रचे जाने पर गीता जिस तरह प्रमाण ग्रंथ के रूप में पूजित हुई है, क्या वही स्थिति उसे इसके पूर्व भी प्राप्त थी, इसका निर्णय कर पाना कठिन है।

● ओम

HEIDELBERGCEMENT

149 वर्षों का अतुलनीय अनुभव



माईसेम सीमेन्ट की सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता, मज़बूती और टिकाऊपन के पीछे उसके विश्व प्रख्यात उत्पादनकर्ता जर्मन कंपनी हाइडलबर्ग सीमेन्ट का 149 वर्षों का अतुलनीय अनुभव है जो 50 देशों में लगातार सुनिश्चित करता आया है कि उसके द्वारा उत्पादित सीमेन्ट का हर कण गुणवत्ता के मापदंड पर खरा उतरे ताकि उनका नारा “सर्वोत्तम निर्माण के लिए” उसके ग्राहकों का विश्वास पात्र बना रहे।

क्योंकि जब सीमेन्ट की गुणवत्ता का सवाल हो,
तो सीमेन्ट का हर कण मायने रखता है..

माईसेम सीमेन्ट | सर्वोत्तम निर्माण के लिए

सस्ता सीमेन्ट या बढ़िया सीमेन्ट - फ़ैसला आपका

For all licenses and BIS standards please refer to www.bis.gov.in
HeidelbergCement India Limited CIN: L26942HR1968FLC042301 Phone +91-124-4503700 e-mail - assistance@mycem.in

अ गहन पूस महीने में मदन हलवाई नया गुड़ और नए चावल की खुशबूदार मिठाई बनाता और मुहल्ले-मुहल्ले घूम-घूम कर बेचा करता है।

अपने गांव में ग्राहकों की उदासीनता देख मदन ने मन ही मन कहा, अपने मुहल्ले में कोई पूछ नहीं है मेरी मिठाई की। लेना-देना

टेढ़ा जवाब



साढ़े बाइस, सिर्फ मोल-जोल।

कहां चल दिए मदन काका? मदन को चिढ़ाने के लिए गांव के एक छोकरे ने कहा।

जहां इंसान का चेहरा नहीं उसका गुण देखते हैं लोग। मदन हलवाई ने छोकरे को टेढ़ा जवाब देकर दूसरे गांव की राह पकड़ ली।

- निर्मल कुमार डे

चेतना का गीत



जीवन को गतिशील बनाकर, बाधाओं से लड़ना होगा। मन को देकर नवल ताजगी, अवसादों से भिड़ना होगा।। निज सूरज को रोज उगाकर, नया सवेरा लाना होगा। साज नहीं, आवाज नहीं पर, गीत नया ही गाना होगा।। सकल दुखों को परे हटाकर, अब तो सुख को गढ़ना होगा! डगर भरी हो कांटों से पर, आगे को नित बढ़ना होगा!! पीर बढ़ रही, व्यथित हुआ मन, दर्द नित्य मुस्काता अपनाता जो सच्चाई को, वह तो नित दुख पाता किंचित भी ना शेष कलुषता, शुचिता से अब मढ़ना होगा! डगर भरी हो कांटों से पर, आगे को नित बढ़ना होगा!!

झूठ, कपट, चालों का मौसम, अंतर्मन अकुलाता हुआ आज बेदर्द जमाना, अश्रु नयन में आता जीवन बने सुवासित सबका, पुष्पों-सा अब झड़ना होगा! डगर भरी हो कांटों से पर, आगे को नित बढ़ना होगा!! कुछ तुम सुधरो, कुछ हम सुधरें, नव आगत मुस्काए सब विकार, दुर्गुण मिट जाएं, अपनापन छ जाए औरों की पीड़ा हरने को, करुणा लेकर अड़ना होगा! डगर भरी हो कांटों से पर, आगे को नित बढ़ना होगा!!

- प्रो. (डॉ.) शरद नारायण खरे

पसंद-नापसंद

विद्यालय के विशाल कक्ष में दसवीं कक्षा के बच्चों को एकत्रित किया गया था। एक प्रसिद्ध प्रवक्ता को वहां बुलाया गया था, जो व्यवहारिक रूप से एक दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात समझाने के लिए जाने जाते थे। प्रवक्ता ने उस विशाल कक्ष में प्रवेश किया। उनके साथ दो लोग और थे, जिनके पास दो टोकरियां थीं, जिनमें अलग-अलग किस्म के फल थे। उन्होंने मंच पर आते ही सभी को प्रणाम किया, और अपने साथ आए दोनों व्यक्तियों को वहां उपस्थित सभी बच्चों को एक-एक फल वितरित करने को कहा। उन दोनों ने टोकरी से निकालकर एक-एक फल सभी को पकड़ा दिया।

प्रवक्ता ने कहा, आप सभी बच्चे पांच मिनट में अपने-अपने फल को खा लें।

बच्चों ने फल खाने शुरू कर दिए। पांच मिनट के बाद प्रवक्ता ने कहा, जिन-जिन बच्चों ने फल नहीं खाए, वह हाथ खड़ा करें। कुछ बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए।

प्रवक्ता ने पूछा, आपने फल क्यों नहीं खाए?

बच्चों का जवाब था, यह फल हमें बिल्कुल पसंद नहीं हैं।

प्रवक्ता महोदय ने फिर पूछा, 'अब जिन-जिन बच्चों ने फल खा तो लिया, पर पूरा नहीं खाया, क्योंकि उनकी पसंद का नहीं था, वे अपना हाथ खड़ा करें। इस पर भी कुछ हाथ खड़े हो गए।

अब वे लोग हाथ खड़ा करें, जिनको यदि दूसरा मनपसंद फल दिया जाता, तो वे वही खाते, जो खाना पड़ा वह नहीं...। प्रवक्ता ने कहा। इस पर काफी बच्चों के हाथ खड़े हो गए।

तो बच्चों यह है हमारा आज का सबक, प्रवक्ता ने कहना शुरू किया, यदि हम अपनी मर्जी से फल वितरित न करके, आपसे अपनी-अपनी पसंद का फल उठाने के लिए कहते; या पहले से ही आप से



पूछकर आपकी पसंद के अनुसार फल वितरित करते, तो आप सभी को खुशी मिलती, हम भी खुश होते। दूसरा, यदि आपको आपस में फल बदलने का अवसर दिया जाता, या आप सभी स्वयं आपस में बदल लेते; तो भी अधिकतम को पसंदीदा फल खाने को मिलता। कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक हम एक-दूसरे की पसंद-नापसंद का ध्यान रखते हुए, एक-दूसरे के साथ स्नेह और सहयोग की भावना रखेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, तब तक हमें खुशी मिलती रहेगी, और हमारे दुख, कष्ट और कमियां न्यूनतम रहेंगी।

- विजय कुमार

पिछले कुछ महीने श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए विनाशकारी रहे हैं। दोनों ही देशों में राजनीतिक उथल-पुथल था। अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। वे एशिया कप के मूल मेजबान थे, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए आयोजन स्थल को यूएई में स्थानांतरित करना पड़ा। पाकिस्तान भी एक आर्थिक संकट से जूझ रहा है और बेहद खौफनाक बाढ़ का सामना कर रहा है। फिर भी इन दोनों देशों ने एशिया कप में सबसे शानदार प्रदर्शन किया। खेल शायद ही उन लोगों को सांत्वना दे सके, जिन्होंने अपना घर या नौकरी खो दी है। श्रीलंका की सफलता वाकई में घाव पर मरहम की तरह काम करेगा। उनका रवैया और दृष्टिकोण ऑस्ट्रेलिया में पांच सप्ताह में शुरू होने वाले टी20 विश्व कप के लिए चुनी गई करोड़ों डॉलर की टीम इंडिया के थिंकटैंक के लिए महत्वपूर्ण सबक हैं। बता दें कि भारत ने धोनी की कप्तानी में 2007 में पहले टी-20 वर्ल्ड कप सीजन का खिताब जीता था।

भारत आईसीसी की टी20 रैंकिंग में दुनिया में नंबर 1 है। श्रीलंका आठवें स्थान पर है। उसे विश्वकप के सुपर 12 के लिए क्वालिफाई करने के लिए तीन में से दो (नामीबिया, नीदरलैंड और यूएई) को पीछे छोड़ना होगा। याद रखें कि पिछले साल भारत ने शिखर धवन के नेतृत्व में एक तरह की बी टीम भेजी थी। उस समय मुख्य टीम विराट कोहली की कप्तानी में इंग्लैंड में खेल रही थी। भारत वनडे सीरीज 2-1 से जीतने में भी सफल रहा और टी20 1-2 से हार गया। एशिया कप में श्रीलंकाई टीम ने पासा ही पलट दिया। अपने रैंक से कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए हर किसी को चौंका दिया। द्विपक्षीय जीतकर रैंकिंग प्राप्त की जा सकती है, जहां बहुत कम चुनौती होती है, लेकिन एक टीम की असली ताकत का पता बड़े टूर्नामेंट में ही चलता है।

भारत के विपरीत श्रीलंका के पास खेल के मैदान और उसके बाहर कोई बहुत बड़ा सुपर स्टार नहीं था। यह टूर्नामेंट सितारों ने नहीं, बल्कि कलाकारों ने जीता। एशिया कप ऑल-फॉर-वन यूनिट के रूप में खेलने वाली टीम ने जीता। श्रीलंकाई टीम में किसी ने भी 200 से ज्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन टीम के रूप में उनके छोटे स्कोर ने ही गजब कर दिया। टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ हार के साथ शुरुआत की, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को लगातार दो बार हराया। यह मायने नहीं रखता कि आप टूर्नामेंट की शुरुआत कैसे करते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप इसे कैसे खत्म करते हैं। और हां, कप्तान दासुन शनाका ने आराम नहीं किया, इन दिनों शीर्ष भारतीय



श्रीलंका से सबक ले भारत

छठी बार एशियन चैंपियन बनी श्रीलंका

एशिया कप 2022 के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता। उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 170 रन बनाए। श्रीलंका के लिए भानुका राजपक्षा ने 41 गेंद में नाबाद 71 और वानिंदु हसरंगा डिसिल्वे ने 36 रन की पारी खेली। पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ ने तीन विकेट लिए। हालांकि पाकिस्तान की टीम यह लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। पाकिस्तान की टीम 171 रनों का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी और 20 ओवर में केवल 147 रन ही बना सके। अफसोस, अंडरडॉग श्रीलंकाई टीम के जज्बे ने आयोजकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

क्रिकेटर्स के लिए एक पसंदीदा शब्द, यहां तक कि पाकिस्तान के खिलाफ अर्थहीन सुपर 4 मुकाबले को भी सभी ने खेला।

अफगानिस्तान के खिलाफ सुपर 4 में टीम का टूर्नामेंट में कोई भविष्य नहीं होने के बाद भारत ने दबदबा भरा प्रदर्शन किया। एक उत्तम दर्जे का शतक या पांच विकेट लेना व्यक्तिगत जीत हो सकती है, लेकिन जब तक यह टीम के लिए उपयुक्त समय पर नहीं आता है, यह सिर्फ आंकड़े हैं। गुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, लेकिन सुपर 4 में बड़ा मुकाबला

था। यह एक बड़ी परीक्षा थी। यहां भारत पाकिस्तान और फिर श्रीलंका दोनों से हार गया। यह उसके आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है।

टी20 फॉर्मेट बड़े-बड़े हीरो को जन्म दे रहा है। यहां प्रेशर वाले गेम होते हैं, जो झेलता है वह स्टार बनता है। पाकिस्तान को ऐसे दो खिलाड़ी मोहम्मद नवाज और नसीम शाह के रूप में मिले। नवाज की 20 गेंदों में 42 रनों की पारी ने भारत को हरा दिया, जबकि अफगानिस्तान के खिलाफ नौ विकेट गिरने के बाद नसीम शाह ने लगातार दो छक्के लगाते हुए पासा पलट दिया। यह एक युवा, नंबर 10, के लिए अविश्वसनीय था। वानिंदु हसरंगा की ट्रिपल स्ट्राइक ने पाकिस्तान के निचले मध्य क्रम को कुचल दिया। गुप गेम में पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पंड्या को छोड़कर भारत को दबाव की स्थिति में कोई हीरो नहीं मिला।

एक व्यवस्थित बॉलिंग जीत या हार को अंजाम देती है। पाकिस्तान के पास जबरदस्त बॉलिंग यूनिट है, जो शाहीन शाह की वापसी के साथ और भी खतरनाक हो जाएगा। इसके विपरीत भारत कभी भी बड़े मैचों में उतना असरदार नहीं दिखा। भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत ग्रांडंड फील्डिंग, आउटफील्ड कैचिंग और विकेटों के बीच दौड़ थी। इन तीनों क्षेत्रों में मेन इन ब्लू काफी देर से फिसला है। श्रीलंका विकेटों के बीच जुनून के साथ दौड़ा। बल्लेबाज रन आउट से बचने के लिए खुद को झोंकते दिखे तो शानदार कैचिंग ने फाइनल में परिणाम बदल दिया।

● आशीष नेमा



...जब कमल हासन की फिल्म मरुधनायगम के सेट पर आई थीं महारानी एलिजाबेथ सेकंड

दुनिया ने अपनी सबसे पुरानी ब्रिटिश सम्राट महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को बीते दिनों खो दिया और इसका भारतीय लोगों को भी दुख है। महारानी का हमारे देश में आगमन हुआ था और वे फिल्मों की भी शौकीन थीं। एक बार वे साउथ के सुपरस्टार कमल हासन की फिल्म के सेट पर भी विजिट करने गई थीं। साल 1997 में वे कमल हासन की उनकी सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक के सेट पर गई थीं।

कमल भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं और उनकी हर फिल्म बहुत चर्चा में रहती है। वही सच था जब उन्होंने 1997 में ऐतिहासिक नाटक 'मरुधनायगम' पर काम करना शुरू किया था। इसमें तमिल स्टार ने लीड रोल निभाने के साथ-साथ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और को-राइटर के रूप में भी काम किया। यही वो फिल्म है जिसके सेट पर महारानी एलिजाबेथ सेकंड का आगमन हुआ था और सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं।



उस दौर की महंगी फिल्मों में से एक थी मरुधनायगम... अपने समय की सबसे महंगी फिल्मों में से एक मानी जाने वाली कमल हासन अभिनीत इस फिल्म का प्रस्तावित बजट उस दौरान में 85 करोड़ रुपए था, जो कि काफी ज्यादा था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जीवन पर आधारित फिल्म मरुधनायगम ने न केवल इसलिए शोर मचाया क्योंकि इसमें कमल हासन, अमरीश पुरी और नसीरुद्दीन शाह शामिल थे, बल्कि इसलिए भी कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय आधिकारिक लॉन्च समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थीं।

युद्ध दृश्य भी देखा

लॉन्च समारोह में, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने मरुधनायगम के सेट का दौरा किया और यहां तक कि फिल्म से एक छोटा युद्ध दृश्य भी देखा, जिससे उनके दौर के दौरान शूट किया जा रहा था। फिल्म के सेट पर जाने के अलावा उन्होंने कमल हासन, उनकी पूर्व पत्नी सारिका और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के साथ भी समय बिताया था। मरुधनायगम के सेट पर दिवंगत महारानी एलिजाबेथ ने कमल हासन की तारीफ की थी।

कैंसर-एक्सीडेंट से लेकर लाइफ में काफी मुश्किलों का सामना कर चुकी हैं महिमा

महिमा चौधरी बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। उन्होंने अपने कैरियर में कई हिट फिल्मों दी हैं और हर बार उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से फैंस और दर्शकों का दिल जीता है। महिमा चौधरी ने बॉलीवुड में डेब्यू डायरेक्टर सुभाष घई की फिल्म 'परदेस' से किया था। साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म परदेस ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे और महिमा रातों-रात बॉलीवुड की सुपरस्टार बन गई थीं। उनकी इस डेब्यू फिल्म के लिए ही उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था। महिमा की लाइफ में एक दौर ऐसा भी रहा है कि वो काफी



पॉपुलर एक्ट्रेस थीं, लेकिन अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में काफी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स की वजह से अक्सर खबरों में रही हैं। जिस वजह से उनके कैरियर का ग्राफ लगातार गिरता चला गया। वह अपने असफल प्रेम संबंधों और रिलेशनशिप को लेकर हमेशा विवादों में रही हैं। एक समय उनका नाम टेनिस स्टार लिण्डर पेस से जुड़ा था। हालांकि ये रिलेशनशिप जल्द ही खत्म हो गया।

पहली ही फिल्म से आयुष्मान ने लिया था बड़ा रिस्क, आसान नहीं था विक्की डोनर बनना

आयुष्मान खुराना एक आम आदमी और उसकी जिंदगी के संघर्षों को पर्दे पर जीना पसंद करते हैं। एक्टर अधिकतर रोमांटिक, चॉकलेटी या एक्शन हीरो वाली इमेज में नजर आना चाहते हैं, वहीं आयुष्मान ने 'विक्की डोनर', 'शुभ मंगल सावधान', 'गुलाबो सितारो' जैसी फिल्मों में एक साधारण संघर्ष करते युवक का किरदार निभाया। आयुष्मान खुराना जितने माहिर एक्टर हैं, उतने जबरदस्त सिंगर भी हैं। अपने कैरियर की शुरुआत आयुष्मान ने एक आरजे के तौर पर की थी। बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर आयुष्मान खुराना आज लाखों दिलों की धड़कन बन चुके हैं। 'रोडीज 2'



की सफलता के करीब 8 साल बाद फिल्म 'विक्की डोनर' से बॉलीवुड डेब्यू किया। इस फिल्म से डेब्यू करना एक नए एक्टर के लिए काफी रिस्की था। आयुष्मान ने 'विक्की डोनर' में शानदार काम किया और ये फिल्म हिट रही। इस फिल्म से एक्टर ने बता दिया कि रोमांस और मसालेदार फिल्मों के अलावा अगर शानदार स्क्रिप्ट और अदाकारी हो तो फिल्म सफल होती है।

बापू बेचैन हैं...!

शराब का एक प्रोटोकाल होता है जिसके तहत पीने के बाद गाली-गलौच मारपीट और नाली में लोटने जैसी क्रियाएं तो की जा सकती हैं किंतु प्रायश्चित करने के लिए गांधी जी की समाधि पर जाने का विचार ही पूरी बोतल का नशा उतारने के लिए काफी है।

बड़े-बुजुर्गों ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये अंगूर की बेटी यानी शराब न किसी की हुई है और न होगी। इतिहास गवाह है। इसके चक्कर में न जाने कितने लोग बर्बाद हो गए, नवाबों की हवेलियां बिक गईं और राजे-रजवाड़े तबाह हो गए। फिर भी कमबख्त बेवफा की बेवफा है। ताजा किस्सा देश के दिल कही जाने वाली दिल्ली का है। वहां इस किशमिश की पोती ने उधम काट रखा है।

कहानी कुछ दिन पहले दारू की दुकानों से शुरू हुई थी। उन पर एक बोतल खरीदने पर दूसरी मुफ्त मिल रही थी। पीने वालों को क्या चाहिए... माल-ए-मुफ्त, दिल-ए-बेरहम, पिए जा जाम भर-भर के। लोगों ने न सिर्फ जी भरकर पी, बल्कि डुबकी लगाकर स्नान तक कर लिया। कुछ ने तो इससे आगे भी अपनी उम्मीदें बांध लीं। उन्हें लगा आज एक बोतल पर दूसरी फ्री है। संभव है इसी नीति को विस्तार देकर आगे बिजली के साथ पेट्रोल और पानी के साथ डीजल भी फ्री में मिल जाए। अपराधी जनों ने एक लूट संग दूसरी लूट का सपना भी देख डाला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टे चौतरफा आलोचना और विरोध शुरू हो गया। नतीजा फैसले को पलट दिया गया। इसके बाद आलोचना और विरोध के स्वर और तेज हो गए।

इस सबके बीच एक नेताजी इतने दुखी हुए कि उन्होंने बाकायदा प्रायश्चित करने की ठान ली। कायदे से यह प्रायश्चित किसी देसी-विदेशी शराब के ठेके, होटल अथवा बार में हलक तर करके किया जा सकता था। इससे भी जी न भरता तो श्रद्धानुसार 21, 51 या 101 बेवड़ों को कॉकटेल पार्टी दी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने प्रायश्चित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों यानी बापू की समाधि पर करने के बारे में सोचा। यह



संकल्प सुन हम कांप उठे। जिन बापू की जयंती पर गांव-गांव, शहर-शहर के ठेकों की पिछली खिड़की छोड़कर मुख्य दरवाजों पर ताले लग जाते हैं, उन बापू के समक्ष दारू के लिए प्रायश्चित। इसके आगे की कल्पना से ही हमें डर लगने लगा।

आगे का दृश्य इस प्रकार है-बापू की आत्मा भी उन्हें देखकर कांप उठी। मरने से पहले बापू ने दक्षिण अफ्रीका देखा, इंग्लैंड देखा, अंग्रेजों का राज देखा, तमाम लार्ड-गवर्नर देखे, जेल देखी, आंदोलन देखे, खादी-चरखे के साथ देश का बंटवारा देखा। मरने के बाद समाधि पर आने

वाले पर्यटक, देसी-विदेशी राजनयिक, शपथ लेते नेता, 30 जनवरी का सालाना श्रद्धांजलि कार्यक्रम देखा। आजाद भारत की कई सरकारें देखीं, कुर्सी के लिए जूतम पैजार देखी, परिवारवाद, भाई-भतीजावाद देखा, खुद उनके नाम पर लोगों को झूठी कसमें खाते, झूठे वादे करते देखा...और हाल ही में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव भी देखा।

हमें भी लगा कुछ गलत है। शराब का एक प्रोटोकाल होता है, जिसके तहत पीने के बाद गाली-गलौच, मारपीट और नाली में लोटने जैसी क्रियाएं तो की जा सकती हैं, किंतु प्रायश्चित करने के लिए गांधी जी की समाधि पर जाने का विचार ही पूरी बोतल का नशा उतारने के लिए काफी है। हम सोचने लगे-हे प्रभु, आपने बापू को किस परीक्षा में डाल दिया। वह ठहरे सत्य और अहिंसा के पुजारी। तीन बंदरों के मदारी। उन्होंने जीते जी बकरी के दूध और देशवासियों के गम के अलावा कुछ न पिया। क्या अब उन्हें कौन सी शराब नीति सही है या गलत, इस पर बहस और विवाद का भी साक्षी बनना पड़ेगा। मदिरा के विरोधी रहे बापू को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वह शराब नीति पर किन नेताओं की बातों पर ध्यान दें-

पक्ष के या विपक्ष के।

हमने महसूस किया कि बापू व्यथित हैं। वह सच्चे दिल से 'हे राम' कहना चाहते हैं, किंतु मन मसोस कर रह जाते हैं। आज के दौर में राम का नाम लेने वाला सांप्रदायिक माना जाता है। बापू बेचैन हैं, लेकिन नेतागण अपने लाव-लशकर के साथ उनकी समाधि पर विराजमान हैं। उन्हें प्रायश्चित करना है, लेकिन तरीका नहीं जानते। फिर भी नेता लोग अपने इरादे पर अडिग हैं और ये नजारा देख बापू खुद प्रायश्चित करने का निश्चय करते हैं।

● प्रमोद दीक्षित 'मलय'



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

अन्न उत्सव

हर माह 7, 8 और 9 तारीख को

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
प्रति सदस्य 5 किलो निःशुल्क खाद्यान्न वितरण



- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत खाद्यान्न 5 किलो प्रति सदस्य 1 रु. प्रति किलो
- अंत्योदय अन्न योजना - 35 किलो प्रति परिवार 1 रु. प्रति किलो
- प्राथमिकता श्रेणी परिवार - 5 किलो प्रति सदस्य
- नमक - 1 रु. प्रति किलो प्रति परिवार
- शक्कर - 20 रु. प्रति किलो अंत्योदय अन्न योजना अंतर्गत
- प्रत्येक दुकान पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति
- राज्य स्तर से भी मॉनिटरिंग

हितग्राही की पहचान हेतु eKYC करायें। आपको वितरित सामग्री की जानकारी SMS से देने हेतु मोबाइल नम्बर POS में दर्ज करायें।

अपील : अन्न उत्सव के अवसर पर उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त करें।

119 लाख परिवार,
509 लाख हितग्राही

वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत किसी भी
दुकान से राशन प्राप्त करने की सुविधा

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन

सबको भोजन, पर्याप्त पोषण

D-19389/22



SMILES
TO A MILLION
ENERGY SECURITY
TO A BILLION



MCL

MAHANADI COALFIELDS LIMITED

(A Govt. of India Undertaking & Subsidiary of Coal India Limited)

Corporate Office: At/Po.- Jagruti Vihar, Burla, Sambalpur, Odisha-768 020

www.mahanadicoal.in



mahanadicoal



mahanadicoal